शर्मा हार्डवेयर
SHARMA HARDWARE
Sharma Gali, SJ Road
Athgaon, Guwahati-01
98648-02947

E-Paper : www.goodluckpublications.com, • www.vbslive.in
हिंदी दैनिक
गुवाहाटी, नई दिल्ली, शिमला और जम्मू से एकसाथ प्रकाशित

राष्ट्र निर्माण में प्रयत्नशील

विकसित भारत समाचार

वर्ष : 11 | अंक : 185 | गुवाहाटी | बुधवार, 5 फरवरी, 2025 | मूल्य : 10 रुपए | पृष्ठ : 8 | VIKSIT BHARAT SAMACHAR | Regd. RNI No. ASSHIN/2014/56526

बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कड़ा वार, नहीं डाल पाएंगे फर्जी वोट — पेज 2
कृषि उत्पाद निर्यात में अग्रणी बनने का प्रयास : बिमल बोरा — पेज 3
अनिता चौधरी हत्याकांड : सीबीआई ने केस दर्ज किया, तैयब अंसारी और सुनीता नामजद — पेज 5
राष्ट्रीय खेल : उत्तराखंड के नीरज जोशी ने वुशू में जीता रजत पदक — पेज 7

S.S. Traders
Suppliers in : All kinds of Door Fittings Modular Kitchen & Accessories, etc.
D. Neog Path, Near Dona Planet ABC, G.S. Road, Guwahati - 05
97079-99344

सुप्रभात

हमारा कर्तव्य है की हम हर उस व्यक्ति का हौंसला बढ़ाए, जो अपने ऊंचे विचारों पर जीवन व्यतीत करने के लिए संग्रह कर रहा है।

- स्वामी विवेकानंद

विदेशियों को वापस न भेजने पर एससी ने असम सरकार को लगाई फटकार, कहा-

क्या आप किसी मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को असम सरकार की कड़ी आलोचना की क्योंकि उसने आधिकारिक तौर पर विदेशी घोषित किए गए लोगों को वापस भेजने में कोई कदम नहीं उठाया। कोर्ट ने इन लोगों को अनिश्चित काल तक हिरासत केंद्रों में रखने के राज्य के फैसले पर सवाल उठाया और इसे उनके अधिकारों का उल्लंघन बताया। साथी न्यायालय ने असम सरकार को निर्देश दिया कि वह अगले दो सप्ताह के भीतर हिरासत केंद्रों में बंद 63 व्यक्तियों के निर्वासन की प्रक्रिया शुरू करे। सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार को निर्देश दिया कि वह हिरासत केंद्रों में बंद विदेशियों के निर्वासन के संबंध में दो सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करे। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने अन्य व्यक्तियों की नागरिकता स्थिति के सत्यापन पर अद्यतन जानकारी मांगी। अदालत ने असम सरकार के इस तर्क पर चिंता जताई कि हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के विदेशी पते की जानकारी के अभाव के कारण उनका निर्वासन संभव नहीं है। न्यायालय ने असम के रुख पर सवाल उठाया, असम के मुख्य सचिव से पूछा गया कि सरकार बंदियों के स्थानीय पते का इंतजार क्यों कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की जब किसी को विदेशी घोषित कर दिया जाता है, तो उसे तुरंत निर्वासित कर दिया जाना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको उनका स्थानीय पता पता है या नहीं। आप उन्हें अनिश्चित काल तक हिरासत में नहीं रख सकते। यह दूसरे देश पर निर्भर करता है कि वह तय करे कि उन्हें कहां जाना चाहिए। अदालत ने असम सरकार के वकील को सुझाव दिया कि संबंधित देश की राजधानी में निर्वासन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि व्यक्ति पाकिस्तान से है, तो वकील से पूछा गया कि क्या वे पाकिस्तान की राजधानी जानते हैं। अदालत ने पूछा विदेशी स्थानीय पते की कमी का हवाला देते हुए आप उन्हें अनिश्चित काल तक हिरासत में कैसे रख सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार को चेतावनी दी कि वह झूठी गवाही के लिए नोटिस जारी कर सकती है। पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य सरकार के तौर पर असम को इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। जवाब में, याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता कोलिन गोंजाल्विस ने बताया कि ये लोग दो देशों के बीच फंस गए हैं: भारत का दावा है कि ये भारतीय नहीं हैं, जबकि बांग्लादेश उन्हें बांग्लादेशी मानने से इनकार करता है। इन व्यक्तियों को 12 से 13 साल तक हिरासत में रखा गया है, और बांग्लादेश ने बार-बार कहा है कि वह उन लोगों को स्वीकार नहीं करेगा जो कई सालों से भारत में रह रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने इन व्यक्तियों को इतने लम्बे समय तक हिरासत में रखने की भारी लागत पर गौर किया तथा सवाल किया कि सरकार इस मुद्दे से अप्रभावित क्यों दिख रही है। हाल ही में, 5 जनवरी को ग्वालपाड़ा के माटिया ट्रांजिट कैंप से तीन रोहिंग्याओं के भागने के बाद निर्वासन का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आया, जिसके बाद पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया। इस घटना ने असम के हिरासत -शेष पृष्ठ दो पर

दो बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़कर भेजा गया सीमा पार : मुख्यमंत्री

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने मंगलवार को कहा कि अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे दो बांग्लादेशी नागरिकों को असम पुलिस ने श्रीभूमि जिले में पकड़ लिया और उन्हें पड़ोसी देश के अधिकारियों को सौंप दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी घुसपैठिये को राज्य में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। शर्मा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा अवैध घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं! -शेष पृष्ठ दो पर

वैश्विक उपस्थिति पर चर्चा के लिए सीएम ने एस जयशंकर से की मुलाकात

नई दिल्ली। असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने मंगलवार को यहां साउथ ब्लॉक कार्यालय में केंद्रीय विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर से मुलाकात की। 30 मिनट तक चली बैठक के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. शर्मा ने केंद्रीय मंत्री जयशंकर से आगामी एडवांटेज असम 2.0 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत की एक्ट ईस्ट नीति में असम की महत्वपूर्ण भूमिका पर एक सत्र की अध्यक्षता करने का अनुरोध किया। केंद्रीय विदेश मंत्री ने सत्र की शोभा बढ़ाने के लिए निमंत्रण स्वीकार कर लिया। मुख्यमंत्री ने विदेश मंत्री को भूटान, दक्षिण कोरिया और जापान की अपनी हालिया यात्राओं के बारे में जानकारी दी और इन देशों में भारत के विकास पथ की जबरदस्त सराहना के अपने अनुभव साझा किए। बाद में, एक्स पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने लिखा मुझे हमारे विद्वान माननीय केंद्रीय मंत्री श्री @DrSJaishankar जी से मुलाकात करने का सौभाग्य मिला। हमारी बातचीत के दौरान, मुझे उन्हें भूटान, दक्षिण कोरिया और जापान की अपनी हाल की यात्राओं और भारत की विकास कहानी की जबरदस्त प्रशंसा के बारे में जानकारी देने का अवसर मिला, जिसे मैंने इन देशों में पहली बार देखा। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय राजधानी स्थित छत्तीसगढ़ भवन में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका से मुलाकात की। अधिकारियों ने इसे शिष्टाचार भेंट बताया। इससे पहले मुख्यमंत्री डॉ. शर्मा ने यहां असम हाउस में आगामी असम एडवांटेज 2.0 शिखर सम्मेलन के सिलसिले में कुछ संभावित निवेशकों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने करीब एक घंटे तक चली अपनी आमने-सामने की मुलाकात के दौरान निवेशकों से असम में आकर निवेश करने का आग्रह किया।

न्यूज गैलरी

श्रीराम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास की हालत नाजुक

लखनऊ (हि.स.)। अयोध्या में श्रीराम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का एसजीपीजीआई के चिकित्सकों ने मंगलवार को मेडिकल बुलेटिन जारी किया। मेडिकल बुलेटिन के अनुसार सत्येंद्र दास की हालत बेहद नाजुक है। चिकित्सकों की एक टीम -शेष पृष्ठ दो पर

गौ-तस्करों को बीच सड़क गोली मारो : मंत्री

कारवार। गौ तस्करी का मामला देश के ज्यादातर राज्यों में देखने को मिलता है। इसके खिलाफ स्थानीय प्रशासन सख्त कार्यवाई भी करता है, लेकिन इसके बावजूद तस्कर बेखौफ कानून को हाथ में लेते हैं। अब इसको लेकर कर्नाटक सरकार एक्शन मोड में आ गई है। दरअसल, उत्तर कन्नड़ जिले में गाय चोरी की घटनाओं के बीच, जिले के प्रभारी मंत्री मंकल एस वैद्य ने चेतावनी दी है कि ऐसी -शेष पृष्ठ दो पर

आईएमडी ने राज्य में बारिश की चेतावनी दी, 10 जिले प्रभावित होने की आशंका

गुवाहाटी। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने इस सर्दी में असम में बारिश की चेतावनी दी है। बारिश से 10 जिले प्रभावित होने की आशंका है, जिससे दैनिक जीवन प्रभावित हो सकता है। प्रभावित होने वाले जिलों में नगांव, कार्बी आंग्लांग, होजाई, श्रीभूमि, हैलाकांदी, धुबड़ी, ग्वालपाड़ा, बोंगाईगांव, कोकराझाड़ और दक्षिण सलमारा शामिल हैं। आईएमडी के अनुसार, आज से बारिश शुरू होने की उम्मीद है, जिसका असर संभवतः इन क्षेत्रों पर पड़ेगा। सर्दियों में आम तौर पर तापमान में थोड़ी गिरावट होगी, लेकिन बारिश से समस्याएं पैदा हो सकती हैं, खासकर निचले इलाकों और बाढ़ की आशंका वाले इलाकों में। इस बीच, पिछले महीने की शुरुआत में, असम पुलिस ने एक निर्देशात्मक वीडियो जारी किया था, जिसमें पिकनिक -शेष पृष्ठ दो पर

असम-नगालैंड सीमा पर गोलीबारी, तनाव

मोरियानी। असम-नगालैंड सीमा पर मोरियानी में तनाव तब फैल गया जब कथित तौर पर अज्ञात नगा बदमाशों ने मैंग्री बॉर्डर आउटपोस्ट (बीओपी) के पास हवा में गोलियां चलाईं। इस घटना से इलाके के निवासियों में दहशत फैल गई है। स्थिति का जायजा लेने और सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के लिए मोरियानी और देबेरापारा से पुलिस दल तुरंत मौके पर पहुंचे। स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए अधिकारी बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। रिपोर्ट पर आगे की जानकारी की प्रतीक्षा है।

अब गुजरात में लागू होगा यूसीसी, सीएम ने पांच सदस्यीय समिति का एलान किया

नई दिल्ली। गुजरात सरकार ने मंगलवार को घोषणा की कि राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का मसौदा तैयार करने और इसे लागू करने के लिए सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय समिति बनाई गई है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस फैसले की जानकारी दी और कहा कि यह समिति 45 दिनों के भीतर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद सरकार इस पर निर्णय लेगी। सीएम पटेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम संविधान की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में काम किया जा रहा है। यह कदम सभी नागरिकों को समान अधिकार देने के लिए उठाया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत का संविधान नागरिकों के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए है और सरकार इस दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि रिपोर्ट तैयार -शेष पृष्ठ दो पर

पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर *बांग्ला* करने को मंजूरी दे केंद्र

टीएमसी ने राज्यसभा में उठाई मांग

नई दिल्ली (हि.स.)। राज्यसभा में मंगलवार को पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर *बांग्ला* करने की मांग की गई। इसके पीछे यह तर्क दिया गया कि नया नाम राज्य के इतिहास और संस्कृति को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करेगा। शून्यकाल के दौरान आल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की सदस्य रीताब्रत बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा ने जुलाई 2018 में सर्वसम्मति से नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया था लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक इसे मंजूरी नहीं दी है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा था। पत्र में ममता ने कहा था नामांतरण से राज्य के इतिहास, संस्कृति और पहचान के साथ-साथ लोगों की आकांक्षाओं का भी पता चलेगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोगों के जनादेश का सम्मान किया जाना -शेष पृष्ठ दो पर

राहुल के आरोपों पर बोले पीएम, कहा-

जब सत्ता सेवा बन जाए, तो राष्ट्र निर्माण होता है, हम संविधान को जीते हैं

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम संविधान को जीते हैं। उन्होंने कहा कि संविधान में जो धाराएं हैं, एक स्पिरिट भी है। मोदी ने कहा कि संविधान को मजबूती देने के लिए संविधान की भावना को जीना पड़ता है। हम वो लोग हैं जो संविधान को जीते हैं। मोदी ने कहा कि 2014 में जब हम आए, तब मान्य विपक्ष नहीं था। उतने अंक लेकर भी कोई नहीं आया था। भारत के अनेक कानून ऐसे थे कि हमें पूरी स्वतंत्रता थी उस कानून के हिसाब से काम करने की। अनेक कमेटियां भी ऐसी थीं, जिसमें लिखा था विपक्ष के नेता उसमें आएंगे, लेकिन विपक्ष कोई था ही नहीं। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि ये हमारा संविधान जीने का स्वभाव था, हमने तय किया कि भले मान्य विपक्ष नहीं होगा, लेकिन जो सबसे बड़े दल का नेता है, उसे मीटिंग्स में बुलाएंगे। उन्होंने कहा कि जब सत्ता सेवा बन जाए, तो राष्ट्र निर्माण होता है। जब सत्ता को विरासत बना दिया जाए, तो लोकतंत्र खत्म हो जाता है। उन्होंने कहा कि हम संविधान की भावना को लेकर चलते हैं, हम जहर की राजनीति नहीं करते हैं। हम देश की एकता को सर्वोपरि रखते हैं और इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाते हैं। जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। नरेंद्र -शेष पृष्ठ दो पर

बांग्लादेश में अवामी लीग के पर्चे बांटने पर दो कार्यकर्ता गिरफ्तार

ढाका। बांग्लादेश पुलिस ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी के पर्चे बांटने पर दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अंतरिम सरकार द्वारा इस तरह के अभियान में शामिल लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने की चेतावनी दिए जाने के एक दिन बाद यह कदम उठाया। एक अखबार ने मंगलवार को खबर दी कि अवामी लीग के फेसबुक पेज पर पर्चे बांटने का वीडियो प्रसारित होने के बाद पुलिस ने सोमवार रात दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अखबार ने एक पुलिस -शेष पृष्ठ दो पर

वक्फ की जमीन पर 15 लाख किरायेदार, जेपीसी की रिपोर्ट में चिंता

नई दिल्ली। वक्फ संपत्तियों पर लंबे समय से रह रहे किरायेदारों की समस्याओं पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) ने अपनी रिपोर्ट में गंभीर चिंता व्यक्त की है। समिति के अनुसार, देशभर में वक्फ की जमीन पर लगभग 10 से 15 लाख किरायेदार रहते हैं, जिनमें से दिल्ली में 2,600 किरायेदार वक्फ संपत्तियों पर हैं। इन किरायेदारों का कहना है कि वे पिछले 75 वर्षों से वक्फ की दुकानों में अपनी रोजी-रोटी कमा रहे हैं, लेकिन अब वक्फ बोर्ड उनका शोषण कर रहा है और उन्हें अतिक्रमणकारी जैसा व्यवहार मिल रहा है, जो पूरी तरह से गलत और मनमाना है। समिति की रिपोर्ट के पेज 407 और 408 में दिल्ली वक्फ किरायेदार कल्याण संघ की तरफ से पेश की गई समस्याओं का विस्तार से उल्लेख किया गया है। किरायेदारों ने संसदीय समिति के सामने यह आरोप लगाया कि पिछले कई दशकों से वे वक्फ संपत्तियों पर रह रहे हैं और कई बार अपनी दुकानों की मरम्मत भी की है, लेकिन इसके बदले उन्हें कभी कोई मुआवजा नहीं -शेष पृष्ठ दो पर

स्वीडन में स्कूल पर हमला, पांच लोगों को मारी गई गोली

स्टॉकहोम। मध्य स्वीडिश शहर ओरेब्रो के रिसबर्गस्का स्कूल में कम से कम पांच लोगों को गोली मार दी गई। पीड़ितों को लगी चोटों की सीमा अभी तक निर्धारित नहीं की गई है, और आपातकालीन प्रतिक्रियाकर्ता सक्रिय रूप से स्थिति का आकलन कर रहे हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, स्वीडन की राष्ट्रीय टास्क फोर्स घटनास्थल पर पहुंच गई है। इस बीच, पुलिस ने एक सार्वजनिक सलाह जारी की है और निवासियों से वस्थगा क्षेत्र से बचने या सुरक्षा के लिए घर के -शेष पृष्ठ दो पर

चीन का ट्रंप को करारा जवाब!

अमेरिकी आयात पर 15-25 प्रतिशत टैरिफ लगाने का एलान, गूगल पर भी कसा शिकंजा

बीजिंग। चीन ने मंगलवार को कहा कि वह अमेरिका के उत्पादों पर 15 प्रतिशत टैरिफ कोयला, एलएनजी (लिक्विफाइड नेचुरल गैस) और 10 प्रतिशत टैरिफ कच्चे तेल एवं अन्य उत्पादों पर लगाएगा। चीन का यह जवाब डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ के खिलाफ है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अमेरिका का एकतरफा टैरिफ बढ़ाना विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के नियमों का गंभीर उल्लंघन है। मंत्रालय ने आगे कहा कि यह न केवल अमेरिका की अपनी समस्याओं को हल करने में मदद नहीं करता, बल्कि अमेरिका और चीन के बीच सामान्य आर्थिक और व्यापार सहयोग को भी नुकसान पहुंचाता है। यह टैरिफ मंगलवार को लागू होने वाले थे, हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से कुछ दिनों में बातचीत करने की योजना बनाई है। इसके अलावा चीन की राज्य प्रशासनिक मार्केट -शेष पृष्ठ दो पर

CLASSIFIED

For all kinds of classified advertisements please contact

97070-14771
86382-00107

MURTI AVAILABLE

Available all kinds of Marble & White Metal Murties, Ganesh Laxmi, Radha Krishna, Bishnu-Laxmi, Hanuman, Maa Durga, Saraswati, Shivling, Nandi etc. **ARTCLE WORLD,** S-29, 2nd Floor, Shoppers Point, Fancy Bazar, Guwahati-01, **Ph. : 94350-48866, 94018-06952**

तिनसुकिया और कटिहार मंडल का जनवरी में उत्कृष्ट परिचालन

गुवाहाटी (हिंस)। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (पूसीरे) अपने ग्राहकों की सेवा और अंतिम उपयोगकर्ताओं को आवश्यक वस्तुओं की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए चौबीसों घंटे अथक प्रयास कर रही है। जनवरी में तिनसुकिया और कटिहार मंडल ने माल लोडिंग एवं अनलोडिंग में निरंतर प्रगति की है। पूसीरे के सीपीआरओ कपिंजल किशोर शर्मा ने आज एक बयान में बताया है कि जनवरी में तिनसुकिया मंडल में विभिन्न वस्तुओं के लिए 0.1225 मिलियन टन माल लोड किया गया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 15.9 फीसदी अधिक है। 24 जनवरी को एक ही दिन में कुल 273 वैगन लोड किए गए। इसी तरह, जनवरी में कुल 4124 वैगन अनलोड किए गए, जबकि दिसंबर में 3204 वैगन थे। इसके अलावा, कटिहार मंडल में जनवरी के दौरान विभिन्न वस्तुओं में 0.2322 मिलियन टन माल लोडिंग किया गया।

दिल्ली विधानसभा चुनाव

बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कड़ा वार, नहीं डाल पाएंगे फर्जी वोट

नई दिल्ली (हि.स.)। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से पहले अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ विशेष तलाशी अभियान शुरू किया गया है। दिल्ली पुलिस ने राजधानी में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने और गिरफ्तार करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। बताया जा रहा है कि फर्जी मतदान न होने पाए, इसके पूरे प्रयास किए गए हैं। मतदान केंद्रों पर बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कैमरा नजर रखेगा। चेहरे की पहचान होते ही वे प्रशासन की पकड़ में होंगे और इसके बाद वापस बांग्लादेश भेजे जाएंगे। यह भी बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और इसके बाद से बांग्लादेश के साथ बिगड़ते रिश्तों को देखते हुए सरकार सख्त रुख अपनाए हुए है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको के घुसपैठियों को वापस भेजने की तकनीक अपनाई, उसी तरह से बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिपोर्ट किया जाएगा। बता दें कि दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ अभियान एलजी वीके सक्सेना के आदेश पर 10 दिसंबर 2024 को शुरू किया गया था, जिसमें दिल्ली में रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया था। अब तक दिल्ली पुलिस ने 58 से अधिक बांग्लादेशियों को निर्वासित किया है और 8 को गिरफ्तार किया है। चुनाव आयोग की सतर्कता और एलजी के आदेश के कारण दिल्ली में 200 से अधिक संदिग्ध घुसपैठियों की पहचान कर ली गई है। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए न केवल सुरक्षा के लिए खतरा हैं, बल्कि वे स्थानीय नागरिकों के रोजगार, सरकारी योजनाओं और मतदाता सूची को भी प्रभावित कर सकते हैं। पुलिस द्वारा संदिग्धों की पहचान कर घर-घर जाकर सत्यापन किया जा रहा है। स्थानीय पुलिस और एफआरआरओ के समन्वय से हो रही कार्रवाई। इसके अलावा गृह राज्यों से वेरिफिकेशन के लिए टीमें भेजी गई। पुलिस मौजूद दस्तावेजों की गहनता से जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी मानव तस्करी और अवैध दस्तावेज बनाने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया था।

लोग गरीबी और बेरोजगारी के चलते गांवों से शहरों में कर रहे हैं पलायन : गडकरी

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि, गरीबी और बेरोजगारी के कारण बड़ी संख्या में लोग ग्रामीण क्षेत्रों से दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर जैसे महानगरों की ओर पलायन कर रहे हैं। गडकरी ने कहा कि लोग शहरी क्षेत्रों की ओर इसलिए भी पलायन कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी कृषि उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। एक कार्यक्रम में बोलते हुए सड़क एंव परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि बेरोजगारी और गरीबी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर बहुत अधिक पलायन हो रहा है। यही कारण है कि आज हम दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बैंगलोर जैसे महानगरों में बहुत सारी समस्याएं देख रहे हैं। भारत में फ्लेक्स इंजन वाली गाड़ियां आ रही हैं और देश में इथेनॉल पंप खोले जा रहे हैं और इससे किसानों की आय बढ़ेगी। उन्होंने आगे कहा कि यह वह क्षेत्र है जहां हम कृषि को समर्थन दे सकते हैं... पहले हम किसानों को *अन्नदाता* कहते थे, लेकिन हमारी सरकार ने किसानों को *ऊर्जादाता* भी बना दिया है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन बताते हुए गडकरी ने कहा कि हमारा सपना हाइड्रोजन ईंधन का निर्यातक बनना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि टिकाऊ विमानन ईंधन सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इससे पहले नितिन गडकरी ने सोमवार को कहा कि सड़क परिवहन मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रियों को राहत देने के लिए एक समान टोल नीति पर काम कर रहा है। गडकरी ने यह भी कहा कि अब भारत का राजमार्ग बुनियादी ढांचा अमेरिका के बराबर है। उन्होंने कहा था कि हम एक समान टोल नीति पर काम कर रहे हैं। इससे यात्रियों को होने वाली समस्याओं का समाधान होगा। गडकरी अधिक टोल शुल्क और खराब सड़क की शिकायतों के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलने वालों के बीच बढ़ते असंतोष पर एक सवाल का जवाब दे रहे थे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहा कि मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर एक बाधा रहित वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली (जीएनएसएस) आधारित टोल संग्रह प्रणाली को लागू करने का फैसला किया है।

आतंकवादी संगठन से जुड़े आरोपी को कोर्ट ने भेजा सात दिन की पुलिस हिरासत में

गुवाहाटी (हिंस)। ऑपरेशन *प्रघात* के तहत असम स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने आतंकवादी नेटवर्क और वैश्विक आतंकी संगठनों (जीटीओ) के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की है। आतंकवादी संगठन से जुड़े गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस ने आज न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। असम पुलिस मुख्यालय से आज जारी एक बयान में बताया गया है कि एसटीएफ असम और कोकराझाड़ पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में तीन फरवरी की सुबह कोकराझाड़ जिले से नसीम उद्दीन एसके नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी अंसारुल्लाह बांग्ला टीम (एबीटी) और जमात-उल-मुजाहिदीन (जेएएम) का सक्रिय सदस्य है। वह पहले गिरफ्तार किए गए नूर इस्लाम मंडल का करीबी सहयोगी था, जो इसी मामले में चरमपंथी गतिविधियों में शामिल पाया गया था। 17 दिसंबर, 2024 से आरोपी फरार था और सुरक्षा एजेंसियों से बचने की कोशिश कर रहा था। जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी नूर इस्लाम मंडल के साथ मिलकर हथियार जुटाने और आईईडी निर्माण में शामिल था। इसका मकसद राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुंचाना, अशांति फैलाना और देश की संप्रभुता को कमजोर करना था। गिरफ्तार व्यक्ति के खिलाफ एसटीएफ पीएस केस नंबर 21/2024 के तहत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है, जिसमें भारतीय दंड संहिता, गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, पासपोर्ट अधिनियम, विस्फोटक अधिनियम, शस्त्र अधिनियम और विदेशी अधिनियम की धाराएं शामिल हैं। अदालत में पेशी के बाद आरोपी को आज सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। जांच जारी है ताकि आतंकवादी नेटवर्क के गहरे संबंधों का पर्दाफाश किया जा सके।

रतनजोत के बीज खाने से पांच बच्चों की हालत बिगड़ी

सिरोही (हिंस)। पिंडवाड़ा के मोरस गांव में दो परिवारों के पांच बच्चों ने जंगल से मिले रतनजोत के बीज खा लिए। सोमवार शाम को खेलते हुए जंगल की ओर गए बच्चों ने बिना जाने-समझे इन बीजों को खा लिया, जिसके कुछ समय बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। बच्चों को उल्टी और दस्त की शिकायत होने पर परिजन तुरंत उन्हें पिंडवाड़ा के सरकारी अस्पताल ले गए। प्रभावित बच्चों में सोनाराम की छह वर्षीय पुत्री पूजा, नौ वर्षीय नीतू, सात वर्षीय संध्या, राजू की तीन वर्षीय पुत्री जया कुमारी और पांच वर्षीय पुत्र आसाराम शामिल थे।

वेस्ट बैंक में इजरायल का बड़ा ऑपरेशन, 50 से ज्यादा फिलिस्तीनी आतंकियों को उड़ाया

तेल अवीव। हमास के साथ बंधकों की अदला-बदली में महत्वपूर्ण घटनाक्रम के बीच, इजराइल रक्षा बलों (आईडीएफ) ने रविवार (स्थानीय समय) को दावा किया कि उसने लगभग एक पखवाड़े पहले उत्तरी वेस्ट बैंक में आक्रमण शुरू करने के बाद से 50 फिलिस्तीनी आतंकवादियों को मार डाला, जैसा कि द टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया है। आईडीएफ ने कहा कि जेनिन, तुलकेरेम और तमुन क्षेत्र में ऑपरेशन के दौरान 35 बंदूकधारी मारे गए, जबकि 15 अन्य ड्रोन हमलों में मारे गए। द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार, आईडीएफ ने इन ऑपरेशनों के दौरान एक बच्चे सहित नागरिकों को गलती से निशाना बनाने की बात भी स्वीकार की। आईडीएफ के अनुसार, उसने 100 फिलिस्तीनी आतंकवादियों को हिरासत में लिया है और 40 से अधिक हथियार जब्त किए गए हैं। आईडीएफ ने कहा कि *ऑपरेशन आयरन वॉल* के दौरान 80 से अधिक विस्फोटकों को भी निष्क्रिय कर दिया गया। आक्रामक हमला 21 जनवरी को शुरू किया गया था और सेना ने कहा कि यह अगले कई हफ्तों तक जारी रहेगा। द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार, आईडीएफ ने जेनिन शरणार्थी शिविरों में 23 इमारतों को ध्वस्त कर दिया है, जिनके बारे में उसका कहना है कि इनका इस्तेमाल आतंकवादियों ने अपने अभियानों के लिए किया था। इजराइली सेना ने बताया कि एक हमलावर ने उत्तरी वेस्ट बैंक में स्थित तयासिर गांव में एक जांच चौकी पर तैनात सैनिकों पर गोलीबारी की। सेना ने बताया कि मुठभेड़ में सैनिकों ने जवाबी गोलीबारी की, जिसमें हमलावर मारा गया। इजराइली अस्पतालों ने बताया कि गोलीबारी में घायल हुए कुल छह लोगों को भर्ती कराया गया है।

पृष्ठ एक का शेष

क्या आप किसी ...

शिविरों में सुरक्षा चिंताओं को उजागर किया। सितंबर 2024 में, सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार को मटिया ट्रांजिट कैंप में रखे गए 211 विदेशी नागरिकों के लिए एक विस्तृत निर्वासन योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। न्यायालय ने निर्वासन को सुगम बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वित प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया, क्योंकि गृह मंत्रालय ने एक हलफनामा देकर यह जिम्मेदारी राज्य सरकार को सौंपी थी। न्यायालय ने आगे कहा कि निर्वासन के लिए भारत के विदेश मंत्रालय और बांग्लादेश सरकार के बीच कूटनीतिक समन्वय की आवश्यकता होगी, क्योंकि इसमें शामिल विदेशी नागरिक कथित तौर पर बांग्लादेश से हैं। जनवरी 2023 तक, विदेशी घोषित किए गए 1,000 से अधिक व्यक्तियों को असम के छह हिरासत केंद्रों में रखा गया था, जिनमें कोकराझाड़, ग्वालपाड़ा, तेजपुर, जोरहाट, डिब्रूगढ़ और सिलचर शामिल हैं। हालांकि, इनमें से कई व्यक्तियों को गुवाहाटी उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के आदेशों के बाद सशर्त जमानत पर रिहा कर दिया गया है।

दो बांग्लादेशी नागरिकों ...

अवैध घुसपैठ के प्रयास पर सख्त कार्रवाई करते हुए @sribhumipolice ने 2 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ लिया और उन्हें सीमा पार भेज दिया। दोनों घुसपैठियों की पहचान मुहीदा बीबी और मुहम्मद कौसर के रूप में हुई है। शर्मा ने कहा कि हम किसी भी अवैध घुसपैठिये को असम में घुसने नहीं देंगे। असम में 220 से अधिक घुसपैठियों को पकड़कर वापस भेजा गया है और पिछले साल पड़ोसी देश में अशांति फैलने के बाद से पूर्वोत्तर में 1,885 किलोमीटर लंबी भारत-बांग्लादेश सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है।

आईएमडी ने राज्य ...

के मौसम और सर्दियों में कोहरे के कारण होने वाली कठिनाइयों के मद्देनजर सड़क सुरक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। सलाह में अवकाश यात्रा और खराब मौसम में ड्राइविंग के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा उपायों पर प्रकाश डाला गया था। वीडियो में सलाह दी गई थी कि हर यात्रा के लिए एक शांत चालक को नियुक्त किया जाए। यात्रियों को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया कि ड्राइविंग की जिम्मेदारी किसी ऐसे व्यक्ति को सौंपी जाए जो शराब न पीता हो, ताकि यात्रा के दौरान सभी सदस्य सुरक्षित रहें। मौसम के पूर्वानुमान के आधार पर यात्रा की योजना बनाने को भी प्रोत्साहित किया गया, साथ ही भारी बारिश या कोहरे के समय यात्रा न करने की सख्त सलाह दी गई। पुलिस ने कहा कि कम दृश्यता से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए यात्रा को दिन के उजाले के घंटों तक सीमित रखा जाना चाहिए, जो सूर्योदय के बाद शुरू होकर सूर्यास्त से पहले समाप्त हो।

अब गुजरात में ...

करने में सभी पहलुओं पर विचार किया जाएगा। संघवी ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल ने यूसीसी (समान नागरिक संहिता) समिति का गठन किया है। इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रंजना देसाई करेंगी। सेवानिवृत्त वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सीएल मीना, अधिवक्ता आरसी कोडेकर, पूर्व कुलपति दक्षेश ठाकर और सामाजिक कार्यकर्ता गीता श्रॉफ भी इस समिति का हिस्सा होंगे। मुख्यमंत्री ने इस समिति को अगले 45 दिनों में इस पर विस्तृत शोध करने और सरकार को रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। इस महीने की शुरुआत में उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से अपने भाषण में धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता का उल्लेख किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वहां लंबी चर्चा हुई। बहस के बाद यह तय हुआ कि बेहतर होगा कि जो सरकार चुनेगी, वह इस पर फैसला ले और देश में समान नागरिक संहिता लागू करे... सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि समान नागरिक संहिता को देश में लाया जाना चाहिए... संविधान की भावना और संविधान निर्माताओं को ध्यान में रखते हुए हम धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता के लिए पूरी ताकत से काम कर रहे हैं।

पश्चिम बंगाल का ...

चाहिए। बनर्जी ने कहा कि आज कोई पूर्वी पाकिस्तान नहीं है। हमारे राज्य का नाम बदलने की जरूरत है। पश्चिम बंगाल के लोगों के जनादेश का सम्मान किए जाने की जरूरत है। आखिरी बार 2011 में किसी राज्य का नाम बदला गया था, जब उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा किया गया था। इसी तरह राज्यसभा में बीजू जनता दल (बीजद) के देबाशीष सामंतराय ने महानदी तट पर हर साल मनाए जाने वाले त्योहार बाली जात्रा को राष्ट्रीय पर्व का दर्जा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि एक समय राज्य के नाविक व्यापार और संस्कृति के विस्तार के लिए प्राचीन काल में इंडोनेशिया, बोर्नियो और श्रीलंका में बाली, सुमात्रा और जावा जाते थे। तृणमूल कांग्रेस की ममता ठाकुर ने गंगासागर मेले के पौराणिक महत्व को रेखांकित करते हुए इसे राष्ट्रीय मेले का दर्जा दिए जाने की मांग उठाई। महाकुंभ में भगदड़ की घटना का जिक्र कर उन्होंने केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की घटना गंगासागर में हुई होती तो अब तक केंद्र सरकार की कई टीमें बंगाल पहुंच गई होतीं। भाजपा के के. लक्ष्मण ने भगवान ऋषभदेव की जयंती को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाने की मांग की। आम आदमी पार्टी के विक्रमजीत सिंह साहनी ने देश में बढ़ती बेरोजगारी पर चिंता जताते हुए सरकार से इस बारे में अल्पकालिक चर्चा की मांग की। उन्होंने कहा कि यह एक कटु सत्य है कि पिछले वर्ष आईआईटी से निकलने वाले करीब 38 प्रतिशत छात्रों को प्लेसमेंट नहीं मिला। टीएमसी के साकेत गोखले ने आग्रह किया कि पेट्रोल में सस्ते इथेनॉल का लाभ उपभोक्ताओं को दिया जाना चाहिए। टीएमसी की सुष्मिता देव ने अनुरोध किया कि जलमार्ग के माध्यम से माल की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए असम में बराक नदी की सफाई की जाए। भाजपा की कविता पाटीदार ने रेलवे लाइन अंडरपास की बाढ़ को दूर करने के लिए भूजल पुनर्भरण जैसी जल संरक्षण रणनीतियों की वकालत की। पीटी उषा (मनोनीत) ने केरल के कोझिकोड जिले के किनालूर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की स्थापना किये जाने की मांग की। कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के एस. सेल्वागणपति ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे अनियमित मौसम पैटर्न ने फसल की पैदावार को नुकसान पहुंचाया है, जिसके कारण किसानों को काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने बीजों की नई किस्मों का परीक्षण करने की सिफारिश की, जो इन मौसम के उतार-चढ़ाव को झेल सकें।

जब सत्ता सेवा बन...

मोदी ने कहा कि सात दशक तक जम्मू-कश्मीर-लद्दाख को संविधान के अधिकारों को अलग रखा गया। ये संविधान के साथ भी अन्याय था और जम्मू-कश्मीर-लद्दाख के साथ भी अन्याय था। हमने अनुच्छेद 370 की दीवार गिरा दी। अब जम्मू-कश्मीर-लद्दाख को देशवासियों को जो अधिकार हैं, वो अधिकार उन्हें मिल रहे हैं। हम संविधान के महात्म्य को जानते हैं। संविधान की भावना को जीते हैं, इसलिए ऐसे मजबूत निर्णय भी हम करते हैं। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि जाति की बातें करना कुछ लोगों का फैशन बन गया है। पिछले 30 साल से सदन में आने वाले ओबीसी समाज के सांसद दलों के भेदभाव से ऊपर उठकर एक होकर मांग कर रहे थे कि ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। जिन लोगों को आज जातिवाद में मलाई दिखती है, उन लोगों को उस समय ओबीसी की याद नहीं आई। हमने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया। उन्होंने कहा कि हमारा निरंतर प्रयास है कि हर योजना का शत प्रतिशत लाभ हर लाभार्थी को मिले। लेकिन कुछ लोगों ने मॉडल ही ऐसा बनाया था कि कुछ ही लोगों को दो औरों को तड़पाओ और तुष्टिकरण की राजनीति करो। देश को विकसित बनाने के लिए तुष्टिकरण से मुक्ति पानी होगी। हमने रास्ता चुना है- संतुष्टिकरण का। हर समाज, हर वर्ग के लोगों को उनका हक मिलना चाहिए। मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति जी के भाषण की चर्चा के समय यहां विदेश नीति की भी चर्चा हुई। कुछ लोगों को लगता है कि जब तक विदेश नीति नहीं बोलते तब तक वो परिपक्व नहीं लगते। उनको लगता है विदेश नीति तो बोलना चाहिए, भले ही देश का नुकसान हो जाए। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि अगर उन्हें सच में विदेश नीति में रूचि है और विदेश नीति को समझना है और आगे जाकर कुछ करना भी है, तो मैं ऐसे लोगों को कहूंगा कि एक किताब जरूर पढ़ें। किताब का नाम है कि जेएफकेस फॉरगोटेन क्राइसिस। इस किताब में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और अमेरिका के तब के राष्ट्रपति जॉन एफ केनेडी के बीच हुई चर्चाओं और निर्णयों का भी वर्णन है। जब देश ढेर सारी चुनौतियों का सामना कर रहा था, तब विदेश नीति के नाम पर क्या खेल हो रहा था इस किताब के माध्यम से सामने आ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बाद एक महिला राष्ट्रपति का सम्मान न कर सके, लेकिन क्या क्या कह कर उन्हें अपमानित किया जा रहा है। मैं राजनीतिक हताशा समझ सकता हूं लेकिन राष्ट्रपति के खिलाफ... क्या कारण है। उन्होंने कहा कि जो लोग संविधान की बातें करते हैं, उन्हें ज्यादा ज्ञान नहीं है, ये भी दुर्भाग्य की बात है। बहुत कम लोगों को मालूम होगा की हमारे देश में पानी की योजनाओं को लेकर बाबा साहेब अंबेडकर का विजन इतना स्पष्ट, व्यापक और समावेशी था, जो आज भी हमें प्रेरणा देता है। 10 से ज्यादा सिंचाई परियोजनाएं, जो दशकों से लटकी हुई थीं, हमने उन्हें पूरा किया ताकि किसानों के खेतों तक पानी पहुंचे।

बांग्लादेश में अवामी ...

अधिकारी के हवाले से कहा कि उन्हें सोमवार रात नारायणगंज के बांदर उपजिला के सोनाकांडा इलाके में एक ऑटो-रिक्शा गैराज से गिरफ्तार किया गया। खबर में कहा गया है कि वे *अवामी लीग के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश* पर पिछले दो दिनों से पर्चे बांट रहे थे। पुलिस ने कहा कि दोनों कार्यकर्ता उसकी हिरासत में हैं और उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि पर्चों में ऐसी सामग्री थी, जो कानून-व्यवस्था में व्यवधान डाल सकती थी। ये गिरफ्तारियां मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शफीक आलम के उस बयान के कुछ घंटों बाद हुईं, जिसमें उन्होंने कहा था कि *फासीवादी* अवामी लीग के समर्थन में पर्चे बांटने वाले किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लगभग 16 साल पुरानी अवामी लीग सरकार को पिछले वर्ष पांच अगस्त को छात्रों के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर हुए विरोध-प्रदर्शन के बाद अपदस्थ कर दिया गया था। तीन दिन बाद यूनुस और उनके सलाहकारों की परिषद ने अंतरिम सरकार के रूप में शपथ ली थी।

वक्फ की जमीन...

मिला। इसके अलावा, वक्फ बोर्ड ने समय-समय पर उनसे बड़ी राशि दान के रूप में ली है और किराया भी बढ़ाया है, लेकिन अब उन्हें उन संपत्तियों की नीलामी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के किरायेदारों ने यह भी बताया कि जब एक किरायेदार की मृत्यु होती है, तो उनके उत्तराधिकारी को संपत्ति पर अधिकार नहीं दिया जाता और वक्फ बोर्ड उनसे फीस वसूलने की कोशिश करता है, जो पूरी तरह से अनुचित है। इन घटनाओं से इन किरायेदारों में असुरक्षा और डर की भावना उत्पन्न हो रही है। संयुक्त संसदीय समिति ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और वक्फ बोर्ड तथा किरायेदारों के बीच एक भरोसे और सहयोग का माहौल बनाने की आवश्यकता जताई है। समिति ने सरकार से सख्त कदम उठाने की अपील की है ताकि दोनों पक्षों के हितों का संतुलन बना रहे और किरायेदारों के अधिकारों का संरक्षण किया जा सके। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि वक्फ किरायेदारों के बीच डर को समाप्त करने के लिए लंबी अवधि के पट्टे दिए जाएं। इससे न केवल किरायेदारों का भविष्य सुरक्षित रहेगा, बल्कि वक्फ संपत्तियों की स्थिति भी बेहतर हो सकेगी। समिति का कहना है कि सरकार को जल्द ही वक्फ किरायेदारों की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी कदम उठाने चाहिए। यदि सरकार समय रहते उचित कदम नहीं उठाती, तो यह समस्या और बढ़ सकती है, और इन किरायेदारों का जीवन और भी कठिन हो सकता है। अब सरकार पर यह दबाव बढ़ गया है कि वह वक्फ किरायेदारों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए त्वरित और प्रभावी कदम उठाए। संसद की संयुक्त संसदीय समिति ने एक ठोस कदम उठाने की जरूरत को महसूस किया है, ताकि किरायेदारों को उनके अधिकार मिले और वे किसी तरह की असुरक्षा का सामना न करें। संविधान और कानूनी ढांचे के तहत वक्फ संपत्तियों के किरायेदारों की स्थिति और अधिकारों को लेकर संसद की संयुक्त संसदीय समिति ने गंभीर चिंता जताई है। समिति ने सरकार से आग्रह किया है कि वक्फ संपत्तियों पर रहने वाले किरायेदारों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाए जाएं। रिपोर्ट में वक्फ बोर्ड और किरायेदारों के बीच सहयोग और विश्वास का माहौल बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

स्वीडन में स्कूल ...

अंदर रहने का आग्रह किया है। स्वीडिश पुलिस ने बताया कि यह घटना स्थानीय समयानुसार दोपहर 13:00 बजे स्टॉकहोम से लगभग 200 किलोमीटर (125 मील) दूर ओरेब्रो शहर में हुई है। पांच लोगों को गोली लगी हैं। हालांकि, पुलिस ने अभी यह नहीं बताया कि घायलों में क्या कोई बच्चा भी शामिल है। टैब्लॉइड एक्सप्रेसन ने बताया कि संदिग्ध शूटर ने खुद को गोली मार ली थी, लेकिन पुलिस ने उस जानकारी की पुष्टि नहीं की है। एक्सप्रेसन और आफ्टनब्लाडेट ने यह भी बताया कि घटनास्थल पर पुलिस पर गोलीबारी की गई थी। पुलिस ने कहा कि आसपास के स्कूलों और संबंधित स्कूल के छात्रों को *सुरक्षा कारणों से* बंद कर दिया गया है। ब्रॉडकास्टर एसवीटी से बात करते हुए, न्याय मंत्री गुन्नार स्ट्रोमर ने कहा कि रिपोर्ट *बहुत गंभीर* थीं। स्ट्रोमर ने एसवीटी को बताया कि सरकार पुलिस के साथ निकट संपर्क में है और घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रही है। कई स्वीडिश मीडिया के अनुसार, गवाहों ने सुना कि वे स्वचालित गोलीबारी मान रहे थे। समाचार पत्र आफ्टनब्लाडेट ने लिखा है कि उसे रिपोर्ट मिली है कि स्थानीय अस्पताल ने घायलों की आशंका में अपने आपातकालीन कक्ष और गहन देखभाल इकाई को खाली कर दिया है।

अमेरिकी आयात पर ...

रेगुलेशन (एसएएमआर) ने मंगलवार को गूगल के खिलाफ एंटीट्रस्ट कानूनों के उल्लंघन के आरोप में जांच शुरू करने का एलान किया। हालांकि, इस बयान में टैरिफ का जिक्र नहीं था, लेकिन यह घोषणा ट्रंप के 10 प्रतिशत टैरिफ लागू होने के कुछ मिनटों बाद की गई थी। चीन ने पहले ही ट्रंप की टैरिफ नीति की आलोचना करते हुए कहा था कि कोई भी व्यापार युद्ध में जीत नहीं सकता। चीनी प्रतिनिधि फू कॉन्ग ने कहा कि हम इस अनावश्यक वृद्धि का विरोध करते हैं और मानते हैं कि यह डब्ल्यूटीओ के नियमों का उल्लंघन है। सप्ताहांत में, व्हाइट हाउस ने घोषणा की थी कि ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको से आयात पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ और चीन से आयात पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लागू किया है। व्हाइट हाउस ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने मैक्सिको, कनाडा और चीन को उनके वादों के प्रति जिम्मेदार ठहराने के लिए यह कदम उठाया है, जिनमें अवैध आप्रवासन को रोकना और हमारे देश में विषाक्त फेंटानाइल और अन्य ड्रग्स के प्रवाह को रोकना शामिल है। चीन के दूतावास ने कहा कि व्यापार युद्ध में कोई विजेता नहीं होता, और हम उम्मीद करते हैं कि अमेरिका अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढे, जो खुद के लिए और पूरे विश्व के लिए फायदेमंद हो। फू कॉन्ग ने कहा कि ईमानदारी से कहें तो, मुझे नहीं लगता कि टैरिफ बढ़ाना अमेरिका के लिए फायदेमंद है।

श्रीराम मंदिर के ...

प्रत्येक घंटे पर उनका चेकअप कर रही है। मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास की तबियत को लेकर लखनऊ के एसजीपीजीआई के निदेशक डॉ. आरके धीमान ने कहा कि विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में सत्येंद्र दास का उपचार चल रहा है। वर्तमान समय में न्यूरोलॉजी वॉर्ड की आईसीयू में सत्येंद्र दास को भर्ती कराया गया है। उन्हें डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर की भी समस्या हैं, जिसे देखते हुए आवश्यक उपचार दिया जा रहा है। बता दें कि सत्येंद्र दास अयोध्या स्थित भव्य श्रीराम मंदिर के मुख्य पुजारी हैं। उनकी आयु 87 वर्ष है। सत्येंद्र दास का नाम सन 1992 से रामलला के पुजारी के रूप में जाना जाता है। सत्येंद्र दास के अनुयायियों की संख्या बहुत बड़ी है। यही कारण है कि उनके एसजीपीजीआई में भर्ती होने पर बड़ी संख्या में लोग व्याकुल हैं।

गौ-तस्करों को ...

गतिविधियों में शामिल लोगों को खुलेआम गोली मार दी जाएगी। मंत्री ने कहा कि वह जिले में ऐसी गतिविधियों को जारी नहीं रहने देंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रशासन गायों की रक्षा और उन्हें पालने वालों के हितों के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहा है। मंत्री का यह बयान यहां होन्नावर के पास एक गर्भवती गाय की हत्या की हालिया घटना पर आक्रोश के मद्देनजर आया है। वैद्य ने आगे कहा कि गाय चोरी कई सालों से हो रही है। मैंने एसपी से कहा है कि यह बंद होना चाहिए और किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होना चाहिए। हम गायों की पूजा करते हैं। हम इस जानवर को प्यार से पालते हैं। हम इसका दूध पीकर बड़े हुए हैं। पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि उन्होंने पुलिस को निर्देश दिया है कि इसके पीछे जो लोग हैं, चाहे वे कोई भी हों, उनके खिलाफ निर्दयी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी चीजें जारी रहीं तो मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आरोपियों को सड़क पर गोली मार दी जाए।

कृषि उत्पाद निर्यात में अग्रणी बनने का प्रयास : बिमल बोरा

राज्य सरकार और एपीडा के सहयोग से क्रेता-विक्रेता सम्मेलन

गुवाहाटी (हिंस)। असम सरकार राज्य को कृषि उत्पादों के एक अग्रणी निर्यातक राज्य में बदलने के लिए प्रयासरत है। राज्य के उद्योग, वाणिज्य और सार्वजनिक उद्यम विभाग के मंत्री बिमल बोरा ने कहा कि असम के सामने कई चुनौतियां हैं, लेकिन सरकार इस लक्ष्य को जल्द ही प्राप्त करेगी। वे गुवाहाटी के एक होटल में असम सरकार और केंद्र सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय क्रेता-विक्रेता सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि असम एक कृषि प्रधान राज्य है और इसकी अनुकूल परिस्थितियां और भौगोलिक स्थिति इसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के लिए विश्व स्तरीय कृषि उत्पादों के निर्यात बाजार में बदलने की पूरी क्षमता रखती हैं। सरकार इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। हाल ही में 16 मीट्रिक टन प्राकृतिक शहद और 26 मीट्रिक टन अदरक असम से दुबई निर्यात किया गया, जिसे मंत्री ने सकारात्मक संकेत बताया। उन्होंने कहा कि सरकार कच्चे कृषि उत्पादों के बजाए प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को प्राथमिकता दे रही है। मंत्री ने कहा कि एपीडा के सहयोग से किसानों को प्रशिक्षण मिल रहा है, जिससे वे लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने खाद्य उत्पादों के संरक्षण के लिए शीत भंडारण, पैकेजिंग सुविधाओं और आधुनिक निर्यात प्रणाली की आवश्यकता पर भी जोर दिया, ताकि असम के किसानों के उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जगह बना सकें। असम में पहली बार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) से नलबाड़ी में ग्रीन फील्ड परियोजना के तहत चिप्स उत्पादन की योजना बनाई गई है, जिसके लिए आवश्यक आलू असम में ही उगाए जाएंगे। इसके अलावा, जागीरोड में एक लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जाएगा, जो निर्यातकों को परिवहन और अन्य सुविधाएं प्रदान करेगा। इस सम्मेलन में देश-विदेश के कई क्रेता-विक्रेता शामिल हुए। मंत्री ने उन्हें असम के कृषि उत्पादों को वैश्विक बाजार में ले जाने में सहयोग करने का आह्वान किया। गौरतलब है कि असम सरकार और एपीडा ने इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं क्रेता-विक्रेता बैठक का आयोजन राज्य के कृषि एवं बागवानी उत्पादों को वैश्विक बाजार में पहुंचाने, खरीद-बिक्री की प्रक्रिया को सरल बनाने और अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों को असम के उत्पादों से अवगत कराने के उद्देश्य से किया। इस अवसर पर एपीडा के अधिकारियों के साथ-साथ असम सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की आयुक्त-सचिव अरुणा राजोरिया, जल संसाधन विभाग के आयुक्त-सचिव बीरेंद्र मित्तल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

चाय और शराब व्यवसायी राजेन लोहिया के घर पर ईडी की छापेमारी

डिब्रूगढ़(हिंस)। डिब्रूगढ़ के प्रतिष्ठित व्यवसायी और मनोहारी चाय बागान के मालिक राजेन लोहिया के आवास पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने मंगलवार सुबह छापेमारी की। यह छापेमारी सुबह लगभग 6 बजे शुरू हुई और उनके अन्य व्यावसायिक परिसरों समेत कुल छह स्थानों पर एक साथ कार्रवाई की गई। लोहिया न केवल चाय व्यवसाय से जुड़े हैं, बल्कि उनका संबंध शराब व्यवसाय से भी बताया जाता है। उनके पास अरुणाचल प्रदेश में वेयरहाउस और चाय उत्पादन इकाइयां भी हैं। 2022 में उनके स्वामित्व वाले मनोहारी चाय बागान ने उस समय सुर्खियां बटोरी थीं, जब वहां उत्पादित चाय की नीलामी प्रति किलोग्राम डेढ़ लाख रुपए में हुई थी। सूत्रों के अनुसार, आयकर चोरी और अन्य आर्थिक अनियमितताओं के आरोप में यह छापेमारी की गई है। शाम तक यह कार्रवाई जारी थी, लेकिन ईडी की ओर से अब तक कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है।

बोको में पूर्व सैनिक पुनर्मिलन रैली आयोजित

कामरूप (हिंस)। असम के कामरूप जिले के नगोपारा, बोको में मंगलवार को पूर्व सैनिक पुनर्मिलन रैली आयोजित की गई। इस रैली का उद्देश्य पेंशन, बैंकिंग और दस्तावेजीकरण से जुड़ी समस्याओं का समाधान एक ही मंच पर करना था। इसमें 126 पूर्व सैनिकों, एक दृष्टिहीन पूर्व सैनिक, 86 वीर नारियों और 104 पूर्व सैनिकों के परिवारजनों ने भाग लिया। रैली की अध्यक्षता निदेशक, सैनिक कल्याण निदेशालय, असम, ब्रिगेडियर पलाश चौधरी, एसएम (सेवानिवृत्त) ने की। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, कामरूप (मेट्रो) कर्नल पद्मलोचन बर्मन (सेवानिवृत्त) एवं उनकी टीम ने आयोजन की मेजबानी की। कार्यक्रम में बोको अंचल के खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) के प्रतिनिधि अजिरुद्दीन अहमद, 1971 युद्ध के वीर सैनिक स्व. सूबेदार दधिराम बोरो की पत्नी पुष्पलता बोरो, मांडिरा एवं छयगांव ईएसएम एसोसिएशन के अध्यक्ष व सचिव आदि उपस्थित रहे। पूर्व-सूबेदार कृष्णपति बोरो, सलाहकार, पूर्व सैनिक संघ, बोको ने सभी गणमान्य अतिथियों, वीर नारियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों का स्वागत किया। रैली में कर्नल पद्मलोचन बर्मन (सेवानिवृत्त) ने पूर्व सैनिकों के पुनर्वास और कल्याण से जुड़ी योजनाओं पर प्रकाश डाला, जिसमें केंद्रीय सैनिक बोर्ड और राज्य सैनिक बोर्ड, असम की योजनाएं शामिल हैं। असम सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं, एसपीएआरएसएच (स्पर्श) और पेंशन संबंधी शिकायत निवारण, ईसीएचएस सुविधाओं और उससे जुड़ी समस्याएं, मेडिकल, डेंटल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में आरक्षण नीति और असम सरकार की ग्रुप ए, बी, सी और डी पदों में दो फीसदी आरक्षण नीति आदि शामिल किए गए। उन्होंने उपस्थित लोगों को 7 फरवरी को ब्रह्मपुत्र हॉल, नारंगी आर्मी कैंप, मुख्यालय 51 सब एरिया में आयोजित *जॉब फेयर* और *गवर्नर असम राष्ट्रीय कृतज्ञता एवं जागरूकता योजना* के बारे में भी जानकारी दी। ब्रिगेडियर पलाश चौधरी (सेवानिवृत्त) ने अपने संबोधन में पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के योगदान के प्रति आभार व्यक्त किया और उन्हें समाज व राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी की प्रेरणा दी। उन्होंने आश्वासन दिया कि सैनिक बोर्ड पूर्व सैनिकों की समस्याओं के समाधान हेतु निरंतर प्रयासरत रहेगा। रैली के दौरान वीर नारियों, अनाथों, दिव्यांग आश्रितों और वरिष्ठ पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया, जिससे उनका उत्साहवर्धन हुआ। यह आयोजन पूर्व सैनिक समुदाय के बीच एकजुटता की भावना को बढ़ाने और उनके कल्याण एवं सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

मणिपुर में उग्रवादी संगठनों के सात सदस्य गिरफ्तार हथियार व वाहन बरामद

इंफाल (हिंस)। मणिपुर पुलिस और सुरक्षा बलों ने अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई कर उग्रवादी संगठनों के सात सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से हथियार, विस्फोटक और वाहन बरामद किये हैं। पुलिस ने इंफाल पूर्व जिले के हिंगांग थाना क्षेत्र के मंत्रिपुखरी ठाकुरबाड़ी से पुलिस ने केसीपी (सिटी मैतेई) के पांच सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया। इनकी पहचान लैश्रम बुलु सिंह (26), आरके नेल्सन (19), लैरेलरकपम थोइबा सिंह (27), कांगुजम जेबाश सिंह (28) और योयामयुम जबीरखान (19) के रूप में हुई है। उनके पास से एक 9 एमएम पिस्तौल (11 जिंदा कारतूस सहित), दो 36 एचई हैंड ग्रेनेड, तीन मोबाइल फोन, एक स्लिंग बैग, 5700 रुपए नकद और एक चार पहिया वाहन बरामद किया है।

सेना ने आईआईटीजी के साथ एपॉक्सी बांस आधारित सामग्री के लिए किया समझौता

गुवाहाटी (हिंस)। भारतीय सेना की गजराज कोर और आईआईटी गुवाहाटी ने उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बंकर निर्माण के लिए एपॉक्सी बांस-आधारित मिश्रित सामग्री के अनुसंधान, डिजाइन और निर्माण हेतु एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। यह सामग्री पारंपरिक निर्माण सामग्रियों का स्थान लेगी। इस परियोजना के तहत उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कई रक्षा संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा, जिनका फील्ड ट्रायल किया जाएगा। इन संरचनाओं को छोटे हथियारों की फायरिंग और पूरे मौसम चक्र की चुनौतियों का सामना करना होगा। यह पैनल पारंपरिक सामग्रियों के समान सुरक्षा प्रदान करेंगे, लेकिन हल्के होने के कारण सामग्री परिवहन में कम समय और प्रयास लगेगा, जिससे सेना की तैनाती में मजबूती आएगी। समझौते पर हस्ताक्षर मेजर जनरल रोहिन बावा, वाईएसएम, जीओसी, रेड हॉर्न्स डिवीजन और प्रो. देवेंद्र जालिहाल, निदेशक, आईआईटी गुवाहाटी की उपस्थिति में हुए। यह पहल भारतीय सेना की क्षमता को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो *दशक का परिवर्तन* के सेना प्रमुख के दृष्टिकोण के अनुरूप है। यह साझेदारी केवल एक समझौता नहीं, बल्कि एक साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसमें सेना और शैक्षणिक संस्थान मिलकर नई तकनीकों का अन्वेषण कर रहे हैं और आधुनिक युद्धक्षेत्र की चुनौतियों का समाधान खोज रहे हैं। समारोह में अधिकारी ने भारतीय सेना में उन्नत तकनीकों के एकीकरण पर जोर दिया और इस समझौते के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि इस साझेदारी से अभिनव उपलब्धियां सामने आएंगी और *आत्मनिर्भर भारत* पहल को समर्थन मिलेगा।

ध्यान फाउंडेशन की गौशाला में कामरूप जिला उपायुक्त ने चाहरदिवारी और पुल का शिलान्यास किया

गुवाहाटी (विभास)। कामरूप जिले के जिला आयुक्त देव कुमार मिश्रा ने गुवाहाटी के निकट दादरा हाजो में ध्यान गौ सेवा परिवार द्वारा आयोजित एक समारोह में सुशांत दत्ता जिला विकास आयुक्त और शांतनु नाथ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी विभाग की उपस्थिति में नई चाहरदीवारी और नाले पर नए पुल का शिलान्यास किया। हाल ही में ध्यान फाउंडेशन गौशाला की 20 बीघा भूमि पर चाहरदीवारी का निर्माण किया जाएगा। जिसे कुछ साल पहले असम के सीएम डॉ. हिमंत विश्वा शर्मा ने आवंटित किया था। यह भूमि निचली भूमि है और बाढ़ के दौरान ब्रह्मपुत्र नदी से पानी गौशाला में घुस जाता है और गौशाला की भूमि और कामकाज को नुकसान पहुंचाता है। गौवंश की सुरक्षा को देखते हुए भी दीवार का निर्माण करना और फिर बाढ़ को रोकने के लिए भूमि की ऊंचाई बढ़ाना बहुत जरूरी था। देव कुमार मिश्र की अध्यक्षता में हुई बैठक में उन्होंने गौशाला की गतिविधियों पर प्रकाश डाला और वे आज के नींव का उद्घाटन करके बहुत खुश नजर आए। उन्होंने गौशाला का दौरा किया और गौओं को दर्शन तथा उन्हें घास और गुड़ खिलाया। बैठक का संचालन पूर्णिमा बोंगवांग और गायत्री कपूर ने किया तथा पदाधिकारियों का स्वागत बाल किशन गोयल, दया राम शर्मा, शरद भजनका संजय कालिका, देवदास सिन्हा ने किया तथा रवि सुरेका ने सभा के अंत मे धन्यवाद ज्ञापन किया। वरिष्ठ सदस्य अशोक थर्ड ने गौशाला की समस्याओं पर प्रकाश डाला तथा कुछ आवश्यक गतिविधियों का सुझाव दिया तथा प्रशासन से सहयोग मांगा। गौ सेवा परिवार के अध्यक्ष अजय पोद्दार ने गौशाला का संक्षिप्त परिचय दिया तथा बताया कि गौशाला के विकास के लिए शीघ्र ही 5000 वर्ग फीट का नया गौशाला, बीमार गायों के लिए हॉल रूम, रसोई कक्ष, शौचालय ब्लॉक तथा चारा स्टॉक प्लेटफार्म आदि का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। पीडब्ल्यूडी ठेकेदार देबोजीत बोरा भी उपस्थित थे तथा उन्होंने गुणवत्तापूर्ण कार्य करने की प्रतिबद्धता जताई तथा कहा कि कार्य समय पर पूरा हो जाएगा। नजदीकी दादरा गांव से से सुभम शर्मा, करुणा कांत दास, सत्य भराली शामिल थे। ध्यान फाउंडेशन गुवाहाटी गौशाला 1000 गौवंश का घर है, जिनमें मुख्य रूप से नंदी और दूध न देने वाली गायें हैं, जिन्हें पुलिस और बीएसएफ ने तस्करों और पशु माफियाओं से बचाया है। ध्यान फाउंडेशन अपने 45 से अधिक आश्रयों के माध्यम से देश भर में 70000 से अधिक गौवंश की देखभाल कर रहा है, जिनमें से 4 असम राज्य में स्थित हैं। बीएसएफ के अनुसार, ध्यान फाउंडेशन एकमात्र संगठन है जो पशु तस्करों के खिलाफ युद्ध में उनकी मदद के लिए आगे आया है। ध्यान गौ सेवा परिवार गुवाहाटी के अध्यक्ष अजय पोद्दार द्वारा प्रेस विज्ञप्ति द्वारा दी गई।

24 घंटे के अंदर दो कुख्यात बाइक चोर दबोचे गए

गुवाहाटी। वशिष्ठ थानांतर्गत कोइनाधारा इलाके से बीते 3 फरवरी की भोर में डिंपी बर्मन नामक महिला की स्कूटी एएस 01 ईएक्स 1673 चोरों ने उड़ा दी। 3 फरवरी को दिन में डिंपी बर्मन ने वशिष्ठ थाने में एक एफ आई आर दर्ज कराई, जिसको देखते हुए नवागत थाना प्रभारी कपिल पाठक ने एक टीम बना कर छानबीन शुरू कर दी और जिसका रिजल्ट जल्द मिला, रात में सुराग लगा कर 2 कुख्यात चोरों को सोनपुर इलाके स्कूटी के साथ गिरफ्तार कर लिया, चोरों की पहचान मंदीप कुंवर उर्फ रोहन 24 सोनपुर तथा दामून राभा उर्फ बाबू 30 सोनपुर के रूप में हुई है, पुलिस सूत्रों के अनुसार ये पहले भी कई बार जेल जा चुके हैं, वशिष्ठ पुलिस इनको कोर्ट से रिमांड पर लेकर पुराने चोरियों का भी निस्तारण करने का प्रयास करेगी

आईएएसएस टी के वैज्ञानिकों ने लाल बिच्छू के डंक के खिलाफ नए चिकित्सीय सूत्रीकरण विकसित किया

गुवाहाटी। बिच्छू के डंक को अक्सर सार्वजनिक स्वास्थ्य की चर्चाओं में नजरअंदाज कर दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप दुनिया भर में बड़ी संख्या में मौतें होती हैं। भारतीय लाल बिच्छू (वैज्ञानिक नाम मेसोबुथस टैमुलस) का विष अत्यंत घातक होता है, जिसके फलस्वरूप इसे विश्व के सबसे खतरनाक बिच्छूओ में से एक माना जाता है। लाल बिच्छू के डंक से मरीज की मृत्यु भी हो सकती और इसके विष के प्रभाव को खत्म करने के लिए तत्काल चिकित्सा सुविधाओं पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। भारतीय लाल बिच्छू के डंक के खिलाफ पारंपरिक उपचार में कई कमियां हैं, जिसके कारण बिच्छू के डंक के खिलाफ अधिक प्रभावी उपचार के लिए एक नई दवा की खोज की आवश्यकता अनुभव किया गया। इस समस्या को सुलझाने के लिए गुवाहाटी स्थित भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वशासी संस्थान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उच्च अध्ययन संस्थान (आईएएसएस टी) के निदेशक प्रोफेसर आशीष कुमार मुखर्जी के नेतृत्व डॉ. मोजिबुर आर. खान और तेजपुर विश्वविद्यालय के डॉ. भावना दास ने मिलकर एक अभिनव दवा निर्माण के विकास के माध्यम से भारतीय बिच्छू के डंकों के लिए मौजूदा उपचारों की कमियों को दूर करने की खोज आरंभ की। उनके द्वारा निर्मित एस्कॉर्बिक एसिड (विटामिन सी), वाणिज्यिक बिच्छू रोधी एंटीवेनम (एएसए) और एक अल्फा वन-एड्रेनोरेसेप्टर विरोधी दवा का सहक्रियात्मक दवा संयोजन प्रयोगात्मक जानवरों में भारतीय लाल बिच्छू के विषाक्तता को कम करने में काफी असरदार सिद्ध हुई। मीडिया को संबोधित करते हुए प्रो. आशीष मुखर्जी ने बताया की वर्तमान आविष्कार का नया सूत्रीकरण भारतीय लाल बिच्छू के डंक से उत्पन्न जटिलताओं को दूर करने में बेहतर प्रभावकारिता दर्शाता है। यह नवीन चिकित्सीय फार्मूलेशन एक ऐसी उभरती हुई औषधि है, जिसमें बिच्छू के डंक से पीड़ित रोगी के उपचार की प्रभावकारिता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने की क्षमता परिलक्षित होती है। उन्होंने बताया कि इस अभूतपूर्व फार्मूलेशन को हाल ही में एक भारतीय पेटेंट प्रदान किया गया है और इस नई दवाई को जल्द ही एंटीवेनम उत्पादन में विशेषज्ञता रखने वाले व्यवसाय में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। प्रो. मुखर्जी ने बाजार में इस नए एंटीवेनम फार्मूलेशन की शुरुआत को सुविधाजनक बनाने के लिए अधिक व्यापक पूर्व-नैदानिक और नैदानिक जांच की आवश्यकता को रेखांकित किया।

कोकराझाड़ : एसएसबी ने लगाया पशु चिकित्सा शिविर

कोकराझाड़ (विभास)। छठी वाहिनी सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी), रानीगुली, कोकराझाड़ (असम) के डॉ. ई. चौबा सिंह, पशु चिकित्सा अधिकारी के नेतृत्व में सीमा चौकी नहारानी के अंतर्गत भारत-भूटान सीमावर्ती कार्यक्षेत्र में जन कल्याण योजना के तहत पशु चिकित्सा शिविर का अयोजन किया गया। यह कार्यक्रम मैनागुरी। गांव में आयोजित किया गया, जिसमें सीमा चौकी नहारानी के अंतर्गत आने वाले गांवों के पशुधन को चिकित्सा उपचार एवं दवाइयां वितरण की गई। इस नि:शुल्क पशु चिकित्सा शिविर में कुल 60 मवेशियों की जांच/उपचार तथा दवाईयां वितरण कराई गई। इस कार्यक्रम में सीमावर्ती क्षेत्रों के ग्रामीणों ने सशस्त्र सीमा बल के द्वारा आयोजित की गई पशु चिकित्सा शिविर के लिए सराहना की।

असम में कैंसर के खिलाफ लड़ाई : इंडस टावर्स एसीसीएफ और असम सरकार का संयुक्त प्रयास

गुवाहाटी। समुदायों को समर्थन देने की अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए, भारत के अग्रणी दूरसंचार बुनियादी ढांचा प्रदाताओं में से एक, इंडस टावर्स ने आज असम सरकार और असम कैंसर केयर फाउंडेशन (एसीसीएफ) के सहयोग से असम में कैंसर देखभाल कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की। इंडस टावर्स के प्रमुख सीएसआर कार्यक्रम के तहत कार्यक्रम प्रगति शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य कैंसर के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान देना और निवासियों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। यह कार्यक्रम असम के जोरहाट, बंगाईगांव, लखीमपुर, चराइदेव, धेमाजी, हैलाकांदी, उदालगुड़ी, शिवसागर और बाक्सा में चलाया जाएगा। 2021 में प्रकाशित भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) की रिपोर्ट के अनुसार, कैंसर रोगियों की राष्ट्रीय दर प्रति लाख जनसंख्या पर 97 है, जबकि असम में यह प्रति लाख जनसंख्या पर 114 है। हाल के दिनों में, असम में कैंसर के मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जिसके लिए तत्काल और निरंतर हस्तक्षेप की आवश्यकता है। 70 प्रतिशत मामले उच्च मृत्यु दर के साथ चरण दो या तीन में रिपोर्ट होते हैं। नया कार्यक्रम कैंसर की देखभाल के लिए एक समग्र दृष्टिकोण लागू करके, प्रारंभिक पहचान, सामुदायिक भागीदारी और रोगियों के लिए निरंतर समर्थन पर ध्यान केंद्रित करके इस समस्या से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। कार्यक्रम में आउटरीच, सामुदायिक स्क्रीनिंग, फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण, जागरूकता और व्यवहार परिवर्तन अभियान, रोगी नेविगेटर और देखभाल की निरंतरता शामिल है। कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के लिए रेफरल और दंत चिकित्सक द्वारा मौखिक कैंसर की शारीरिक जांच के साथ-साथ घर-घर स्क्रीनिंग का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम नर्सों द्वारा गर्भाशय ग्रीवा और स्तन कैंसर के लिए शारीरिक जांच और जागरूकता बैठकों और स्कूल संवेदीकरण सहित केंद्रित समूह चर्चा की सुविधा भी प्रदान करेगा। एनईएसए, इंडस टावर्स के सर्कल सीईओ, राजेंद्र गुरुंग ने कहा कि यह पहल असम में स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे और सेवाओं में सुधार के लिए हमारे समर्पण का एक प्रमाण है। समय की मांग है कि रोग का शीघ्र पता लगाया जाए और समय पर उपचार सुनिश्चित किया जाए। हमारा प्रयास यह सुनिश्चित करना है कि हम प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचें, चाहे वह कहीं भी रहता हो, ताकि उसे सर्वोत्तम संभव कैंसर देखभाल उपलब्ध हो सके।

सोनापुर में चोरी की स्कूटी बरामद, दो आरोपी गिरफ्तार

गुवाहाटी (हिंस)। गुवाहाटी के बशिष्ठ थाना के प्रभारी कपिल पाठक के नेतृत्व में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर चोरी की गई स्कूटी बरामद कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सोनापुर निवासी मोनदीप कुंवर उर्फ रोहन (24) और दामुन राभा उर्फ बाबू उर्फ डिंगकोल (30) के रूप में हुई। पूछताछ के दौरान, मोनदीप कुंवर ने दामुन राभा का नाम उजागर किया, जिसके बाद पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों की निशानदेही पर चोरी की गई स्कूटी एनटॉर्क (एएस- 01 ईएक्स-1673) जोगदल, करबी देहाल मंदिर के पास से बरामद की गई। स्कूटी मालिक की पहचान डिंपी बर्मन के रूप में हुई है। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है।

मारवाड़ी हॉस्पिटल ने एएचपीआई नर्सिंग एक्सीलेंस अवार्ड जीता

गुवाहाटी (विभास)। आठगांव स्थित मारवाड़ी हॉस्पिटल ने एएचपीआई हेल्थकेयर एक्सीलेंस अवार्ड 2025 में कोच्चि, केरल में *नर्सिंग प्रथाओं में उत्कृष्टता* के लिए पुरस्कार प्राप्त किया। पुरस्कार केरल के कोच्चि के होटल ली मेरिडियन में एएचपीआई ग्लोबल कॉन्क्लेव में प्रदान किया गया और यह पुरस्कार मारवाड़ी हॉस्पिटल की नर्सिंग अधीक्षक जुबिदा रिनजाह के साथ मारवाड़ी हॉस्पिटल के अस्पताल अधीक्षक रोहित उपाध्याय और गुणवत्ता विभाग में वरिष्ठ प्रबंधक प्रियंका सेनगुप्ता ने हास्पिटल का प्रतिनिधित्व करते हुए समारोह मे उपस्थित होकर प्राप्त किया। यह पुरस्कार केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देवन रामचंद्रन द्वारा प्रदान किया गया। मारवाड़ी हॉस्पिटल्स को नर्सिंग देखभाल में गुणवत्ता प्रबंधन, वरिष्ठ नर्सों के अच्छे नेतृत्व और विभिन्न रोगियों की सुरक्षा पहलों के कठोर मूल्यांकन के बाद यह पुरस्कार और मान्यता प्राप्त हुई नर्सिंग इकाइयों, स्टेशनों को प्रभावी कामकाज के लिए पर्याप्त आपूर्ति और सुविधाएं प्रदान की गई हैं जैसे-नर्सिंग संसाधन प्रबंधन, नर्सिंग देखभाल और रोगी सुरक्षा, दवा प्रबंधन, शिक्षा संचार और मार्गदर्शन, संक्रमण नियंत्रण प्रथाएं, सशक्तिकरण और शासन। अस्पताल ने नर्सिंग देखभाल परिणामों, संरचित स्टाफिंग, जोखिम प्रबंधन, प्रशिक्षण कार्यक्रम और डिजिटल परिवर्तनों आदि में उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया। इसने नर्सिंग देखभाल, पर्यावरणीय स्थिरता और संसाधन प्रबंधन में नवाचार में उन्नति पर भी प्रकाश डाला। संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण प्रथाओं के अस्पताल-व्यापी कार्यान्वयन की एक प्रणाली है। अस्पताल में प्रत्येक नर्सिंग स्टेशन के लिए संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण पर प्रशिक्षित नर्सों की पर्याप्त संख्या है। अस्पताल अधीक्षक रोहित उपाध्याय ने कहा कि यह पुरस्कार गुणवत्तापूर्ण कार्य के प्रति मारवाड़ी अस्पताल की प्रतिबद्धता और अस्पताल के सभी कर्मचारियों विशेष रूप से नर्सों द्वारा समर्पित कार्य की पुष्टि करता है। उन्होंने यह भी कहा कि मारवाड़ी अस्पताल का समर्पित कार्य जारी रहेगा और उन्हें उम्मीद है कि भविष्य में इस तरह के और भी पुरस्कार मिलेंगे। नर्सिंग अधीक्षक सुश्री जुबिदा रिन्जा ने कहा कि मैं प्रबंधन और विशेष रूप से मेरी नर्सिंग टीम के समर्पण, उनकी करुणा और असाधारण देखभाल के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती हूं, जिसके कारण मुझे यह सम्मान मिला। उन्होंने मरीजों और स्वास्थ्य सेवा टीम पर उनके काम के विशिष्ट प्रभाव को भी उजागर किया। हम मरीजों की गुणवत्तापूर्ण देखभाल को पूरा करने के लिए भविष्य में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना जारी रखेंगे। यह उल्लेख करना उल्लेखनीय होगा कि मारवाड़ी अस्पताल असम का एकमात्र अस्पताल है जिसे एनएबीएच से *नर्सिंग प्रथाओं में उत्कृष्टता* जैसा पुरस्कार मिला है।

संपादकीय

स्वास्थ्य बजट पर्याप्त नहीं

भारत में औसतन 10,000 लोगों पर मात्र 2-3 डॉक्टर ही हैं। देश में डॉक्टरों की किल्लत है। जो नए एम्स खड़े किए जा रहे हैं, उनमें डॉक्टरों के आधे से अधिक पद खाली पड़े हैं, क्योंकि योग्य और विशेषज्ञ डॉक्टरों का बहुत अभाव है। ऐसे में आगामी 5 सालों में 75,000 मेडिकल सीटों का सृजन महत्वपूर्ण घोषणा है। उनमें से 10,000 सीटें आगामी एक साल में ही सृजित करने का लक्ष्य तय किया गया है, लेकिन यह भी सवालिया है, क्योंकि विशेषज्ञ और वरिष्ठ चिकित्सक मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर आशंकित हैं। फिलहाल देश में 1.16 लाख मेडिकल सीटें हैं। नए बजट में 200 जिला अस्पतालों में कैंसर के डे-केयर सेंटर स्थापित करने की घोषणा भी बेहद मानवीय है, क्योंकि महानगरों को छोड़ दें, तो दूरदराज और कस्बाई इलाकों में कैंसर जैसी घातक बीमारी की जांच और उसके इलाज की बुनियादी सुविधाएं ही नहीं हैं। कैंसर के विशेषज्ञ डॉक्टर भी बहुत कम हैं। राजधानी दिल्ली में ही कैंसर अस्पताल में न तो नियमित डॉक्टर हैं और न ही जांच करने वाली मशीनें कार्यरत हैं। औसतन मरीज को 7-8 महीने बाद की तारीख दी जाती है। इतने अंतराल में मरीज की मौत भी संभावित है, लिहाजा 200 केंद्र खोलने की घोषणा महत्वपूर्ण है, लेकिन यह चरणबद्ध होनी चाहिए कि कब, कितने केंद्र खुलेंगे और बाकायदा सुचारू रूप से काम करना शुरू कर देंगे? यह भी गौरतलब सवाल है कि कैंसर केंद्रों का संचालन कैसे किया जाएगा? क्या उनका संचालन निजी भागीदारी के साथ होगा अथवा सरकार के स्तर पर ही तमाम बंदोबस्त किए जाएंगे? निजी अस्पतालों में कैंसर के इलाज की सुविधाएं तो हैं, लेकिन इलाज बेहद महंगा है। औसत व्यक्ति इतना पैसा खर्च करने में असमर्थ है। कुछ साल पहले इसी तर्ज पर जिला अस्पतालों में गुर्दा मरीजों के लिए डायलिसिस की सुविधा शुरू की गई थी। उसका फायदा काफी लोगों को मिला था। इसी तरह कैंसर के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सकती है। स्वास्थ्य बजट के राजनीतिक आयाम भी हैं। मोदी सरकार ने 'आयुष्मान भारत' योजना लागू तो कर रखी है, लेकिन उसका भी अद्र्धसत्य यह है कि सिर्फ सर्जरी के मामले में ही वह कार्ड मान्य है। यदि आप अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं, तो 'आयुष्मान' के जरिए इलाज नहीं करा सकते। 'आयुष्मान' की पात्रता के लिए भी कई शर्तें हैं, लिहाजा उन्हीं को यह सेवा उपलब्ध है, जो बिल्कुल वंचित जमात के हैं। विश्व बैंक के अनुसार, भारत में सरकार 50.2 फीसदी इलाज का ही खर्च उठाती है। शेष 49.8 फीसदी लोग अपनी जेब से ही इलाज कराने को विवश हैं। दिल्ली अद्र्धराज्य की सरकार 'मुफ्त स्वास्थ्य' के जुमले का शोर मचाती रही है, लेकिन सरकारी अस्पतालों में आम आदमी की स्थिति कीड़े-मकौड़े जैसी है। डॉक्टरों का व्यवहार बेहद रूखा है। शायद ही कोई अपवाद होगा, जिसका इलाज दिल्ली सरकार ने अपने खर्च पर निजी अस्पताल में कराया होगा! बहरहाल इन समस्याओं का बजट में अक्सर उल्लेख नहीं होता। बजट तो भारत सरकार की 'बैलेंस शीट' होती है। 2025-26 में स्वास्थ्य बजट 99,858 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। बीते वित्त वर्ष की तुलना में यह 8-9 हजार करोड़ रुपए अधिक है। यह पर्याप्त नहीं है। बजट में अनुसंधान पर भी विशेष फोकस किया गया है। चालू वित्त वर्ष में अनुसंधान विभाग का बजट 3301 करोड़ रुपए था। उसे बढ़ाकर 3900 करोड़ किया गया है। कुछ गंभीर बीमारियों की जीवनरक्षक दवाएं सस्ती करने की घोषणा की गई है, लेकिन असली दवाओं की उपलब्धता बेहद जरूरी है। लंबे अंतराल से बहस जारी है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के बजट कमोबेश 6 फीसदी होने चाहिए। चूंकि मुद्रास्फीति बढ़ती रही है, लिहाजा बजट का कमोबेश 10 फीसदी स्वास्थ्य पर खर्च करना चाहिए। यह बजट 1 लाख करोड़ से भी कम है, जबकि कुल बजट 50 लाख करोड़ रुपए से अधिक का है। गणना कर लीजिए कि शिक्षा-स्वास्थ्य पर कितना बजट आवंटित किया गया है।

> नए बजट में 200 जिला अस्पतालों में कैंसर के डे-केयर सेंटर स्थापित करने की घोषणा भी बेहद मानवीय है, क्योंकि महानगरों को छोड़ दें, तो दूरदराज और कस्बाई इलाकों में कैंसर जैसी घातक बीमारी की जांच और उसके इलाज की बुनियादी सुविधाएं ही नहीं हैं। कैंसर के विशेषज्ञ डॉक्टर भी बहुत कम हैं। राजधानी दिल्ली में ही कैंसर अस्पताल में न तो नियमित डॉक्टर है और न ही जांच करने वाली मशीनें कार्यरत हैं। औसतन मरीज को 7-8 महीने बाद की तारीख दी जाती है। इतने अंतराल में मरीज की मौत भी संभावित है, लिहाजा 200 केंद्र खोलने की घोषणा महत्वपूर्ण है, लेकिन यह चरणबद्ध होनी चाहिए कि कब, कितने केंद्र खुलेंगे और बाकायदा सुचारू रूप से काम करना शुरू कर देंगे? यह भी गौरतलब सवाल है कि कैंसर केंद्रों का संचालन कैसे किया जाएगा? क्या उनका संचालन निजी भागीदारी के साथ होगा अथवा सरकार के स्तर पर ही तमाम बंदोबस्त किए जाएंगे? निजी अस्पतालों में कैंसर के इलाज की सुविधाएं तो है, लेकिन इलाज बेहद महंगा है।

भारत में मध्यमवर्गीय परिवार देश की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता आया हैं

वित्तीय वर्ष 2025-26 का अग्रणी, पथप्रदर्शक एवं अतुलनीय बजट

प्रह्लाद सबनानी

> वित्तमंत्री द्वारा लोक सभा में पेश किया गया बजट अपने आप में पथप्रदर्शक, अग्रणी एवं अतुलनीय बजट कहा जा रहा है क्योंकि इस बजट के माध्यम से किसानों, युवाओं, महिलाओं, गरीब वर्ग एवं मध्यम वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है। पिछले कुछ समय से देश की अर्थव्यस्था में विकास की गति कुछ धीमी पड़ती हुई दिखाई दे रही थी अतः विशेष रूप से मध्यम वर्ग एवं गरीब वर्ग के हाथों में अधिक धनराशि शेष बच सके ताकि वे विभिन्न उत्पादों को खरीदकर अर्थव्यवस्था में इनकी मांग बढ़ा सकें, ऐसा प्रयास इस बजट के माध्यम से किया गया है

दिनांक 1 फरवरी 2025 को केंद्र सरकार की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लोकसभा में बजट पेश किया। सीतारमन ने एक महिला वित्तमंत्री के रूप में लगातार 8वां बजट लोकसभा में पेश कर एक रिकार्ड बनाया है। वित्तमंत्री द्वारा लोक सभा में पेश किया गया बजट अपने आप में पथप्रदर्शक, अग्रणी एवं अतुलनीय बजट कहा जा रहा है क्योंकि इस बजट के माध्यम से किसानों, युवाओं, महिलाओं, गरीब वर्ग एवं मध्यम वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है। पिछले कुछ समय से देश की अर्थव्यस्था में विकास की गति कुछ धीमी पड़ती हुई दिखाई दे रही थी अतः विशेष रूप से मध्यम वर्ग एवं गरीब वर्ग के हाथों में अधिक धनराशि शेष बच सके ताकि वे विभिन्न उत्पादों को खरीदकर अर्थव्यवस्था में इनकी मांग बढ़ा सकें, ऐसा प्रयास इस बजट के माध्यम से किया गया है। साथ ही, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से रोजगार उन्मुख क्षेत्रों यथा कृषि क्षेत्र, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, निवेश, निर्यात एवं समावेशी विकास जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि इन्हें विकास के ईंजिन के रूप में विकसित किया जा सके। भारत में मध्यमवर्गीय परिवार देश की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता आया हैं। हाल ही के समय में प्रत्यक्ष कर संग्रहण में व्यक्तिगत आयकर की भागीदारी कारपोरेट क्षेत्र से आयकर की भागीदारी से भी अधिक हो गई है। अतः मोदी सरकार से अब यह अपेक्षा की जा रही थी कि मध्यमवर्गीय परिवारों को बजट के माध्यम से कुछ राहत दी जाय। और फिर, मुद्रा स्फीति की सबसे अधिक मार भी गरीब वर्ग के परिवारों एवं मध्यमवर्गीय परिवारों पर ही पड़ती दिखाई देती है। केंद्रीय वित्तमंत्री ने मध्यमवर्गीय परिवारों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से आयकर की वर्तमान सीमा को 7 लाख रुपए से बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया है। अर्थात अब 12 लाख रुपए तक की आय अर्जित करने वाले नागरिकों पर किसी भी प्रकार का आयकर नहीं लगेगा। वेतन एवं पेंशन पाने वाले नागरिकों को 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड कटौती की राहत इसके अतिरिक्त प्राप्त होगी। इस वर्ग के करदाताओं को 12.75 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं चुकाना होगा। इसके साथ ही, आय कर की दरों में भी परिवर्तन किया गया है।

अब 4 लाख रुपए तक की करयोग्य आय पर आयकर की दर शून्य रहेगी। 4 लाख रुपए से 8 लाख रुपए तक की करयोग्य आय पर आयकर की दर 5 प्रतिशत, 8 लाख रुपए से 12 लाख रुपए तक की कर योग्य आय पर आयकर की दर 10 प्रतिशत, 12 लाख रुपए से 16 लाख रुपए तक की कर योग्य आय पर आयकर की दर 15 प्रतिशत, 16 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक की कर योग्य आय पर आयकर की दर 20 प्रतिशत, 20 लाख रुपए से 24 लाख रुपए तक की कर योग्य आय पर आयकर 25 प्रतिशत एवं 24 लाख रुपए से अधिक की कर योग्य आय पर 30 प्रतिशत की दर से आयकर लागू होगा। मध्यमवर्गीय करदाताओं को उक्त सुधारों से लगभग 80,000 रुपए से 1.10 लाख रुपए तक की राशि की बचत होने की सम्भावना व्यक्त की जा रही है। इस सुधार से कुल मिलाकर देश के बजट में एक लाख करोड़ रुपए की राशि कम प्राप्त होगी अर्थात मध्यमवर्गीय परिवारों को कुल एक लाख करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि का लाभ होगा। और, यह लाभ लगभग 2 करोड़ करदाताओं को होने की सम्भावना है। इससे देश के मध्यमवर्गीय एवं गरीब परिवारों के हाथों अतिरिक्त राशि उपलब्ध होगी जिसे वे विभिन्न उत्पादों की खरीद पर खर्च करेंगे और देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में सहायक होंगे। मध्यमवर्गीय एवं गरीब परिवारों ने जितना सोचा था शायद उससे भी कहीं अधिक राहत उन्हें इस बजट के मध्यम से दी गई है। इसीलिए ही, इस बजट को अग्रणी, पथप्रदर्शक एवं अतुलनीय बजट की संज्ञा दी जा रही है। मध्यमवर्गीय एवं गरीब परिवारों को, आयकर में छूट देकर, दी गई राहत देते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि इससे बजटीय घाटा में वृद्धि नहीं हो। वित्तीय वर्ष 2024-25 में बजटीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5.9 प्रतिशत रहने की सम्भावना पूर्व में की गई थी, परंतु अब संशोधित अनुमान के अनुसार यह बजटीय घाटा कम होकर 5.8 प्रतिशत रहने की सम्भावना है। साथ ही, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजटीय घाटा 5.4 रहने का अनुमान लगाया गया है। अतः देश की वित्तीय व्यवस्था पर किसी भी प्रकार का विपरीत प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है। हां, पूंजीगत खर्चों में जरूर कुछ कमी रही है और वित्तीय वर्ष 2024-25 में 11.11 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत खर्च के अनुमान के विरुद्ध 10.18 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत खर्च होने की सम्भावना व्यक्त की गई है। हालांकि वित्तीय वर्ष 2025-26 में 11.12 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत खर्च की व्यवस्था बजट में की गई है। इस राशि को 11.11 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 15 लाख करोड़ रुपए किया जाना चाहिए था क्योंकि पूंजीगत खर्च में वृद्धि से देश में आर्थिक विकास की दर तेज होती है और रोजगार के नए अवसर निर्मित होते हैं। इस संदर्भ में एक रास्ता यह निकाला गया है कि केंद्र सरकार के उपक्रमों एवं निजी क्षेत्र की कम्पनियों से अपेक्षा की गई है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में ये संस्थान भी अपने पूंजीगत खर्चों में वृद्धि करें ताकि उनके द्वारा किए गए पूंजीगत खर्चों की राशि को मिलाकर कुल पूंजीगत खर्च को 15 लाख करोड़ रुपए से ऊपर ले जाया जाए। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से राज्यों के साथ मिलकर कृषि धन धान्य योजना को 100 जिलों में प्रारम्भ किया जा रहा है, इस योजना के माध्यम से इन जिलों में ली जा रही फसलों की उत्पादकता में वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दलहन के उत्पादन में आत्म निर्भरता प्राप्त करने के लिए 6 वर्षीय मिशन चलाया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा को 5 लाख तक बढ़ाया जा रहा है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ऋण सीमा को 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए एवं स्टार्टअप के लिए ऋण की सीमा को 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए किया जा रहा है। लेदर उद्योग में रोजगार के 22 लाख नए अवसर निर्मित किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। भारत को खिलौना उत्पादन का अंतरराष्ट्रीय केंद्र बनाया जाएगा। यूरिया उत्पादन के क्षेत्र में भारत को आत्म निर्भर बनाया जाएगा।

दृष्टि कोण

क्यों कम हो रहे सरकारी स्कूलों में छात्र

सरकारी स्कूलों में हर वर्ष बच्चों की संख्या कम हो रही है। इससे जाहिर है कि शिक्षा की नीतियों में खामियां हैं जिन्हें समय रहते दूर किया जाना आवश्यक है। जब हम मकान बनाते हैं तो उसकी नींव पर खास ध्यान देते हैं कि नींव काफी मजबूत हो, ताकि उसके ऊपर बहुमंजिल खड़ी की जा सके। कमजोर नींव के ऊपर बहुमंजिल का निर्माण नहीं किया जा सकता। इसी तरह बच्चों की शिक्षा भी मजबूत आधार पर निर्भर है। यदि बच्चों की शिक्षा का आधार मजबूत होगा, तो इसका लाभ इन्हें आगे उच्च शिक्षा ग्रहण करने में मिलेगा। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व शिक्षा के क्षेत्र में आम नागरिक कितना पीछे था, इसके लिए गुलामी के दिनों का इतिहास गवाह है। अंग्रेज उच्च विद्यालय तो दूर, प्राथमिक विद्यालय तक नहीं खोलना चाहते थे, ताकि हिंदोस्तानी ज्यादा पढ़े-लिखे न हो जाएं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारा देश आगे बढ़ा, यह किसी से छिपा नहीं है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में कुछ समय उपरांत जो कमियां उभरी, वे भी कम नहीं थीं। आज सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं और हर प्रांत एक-दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। यह अच्छी बात है लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जो भारी त्रुटियां हैं यह अच्छा संकेत नहीं है। जब नन्हा बच्चा पहली बार विद्यालय में प्रवेश करता है, तो इस सोच के साथ प्रवेश करता है कि मैं आज अपने माता-पिता के घर से व उनकी गोद से अलग होकर ऐसे घर में प्रवेश कर रहा हूं, जहां से मेरे जीवन के सुनहरे कल का उदय होगा व इस घर से शिक्षित होकर जीवन की मजबूत मंजिल की ओर बढ़ूंगा और अपने जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति के अतिरिक्त समाज व देश की सेवा में भागीदार बनूंगा, अर्थात यही उस बच्चे का सपना भी है और अधिकार भी जो उसे एक समान मिलना चाहिए। हर बच्चे को एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए, चाहे वह सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है या निजी स्कूल में। लेकिन एक समान शिक्षा का अधिकार एक सपना बन कर रह गया है। ऊपर वाले ने तो सबको एक समान बनाकर पैदा किया, लेकिन पैदा होते ही हमारा विभाजन हो गया। अर्थात एक अमीर, दूसरा गरीब। अमीर तो अच्छी और उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम है, लेकिन गरीब बेचारा बेबस है। आज गरीब के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो अमीर के बच्चे दूसरे तामझाम वाले प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। गरीब का बच्चा भी पहली कक्षा से ही अंग्रेजी व अंग्रेजी भाषा में विज्ञान और गणित विषय सीखना चाहता है। यदि प्राईवेट स्कूलों के अध्यापक कम वेतन मिलने के बावजूद अंग्रेजी भाषा में उक्त विषय पढ़ा सकते हैं, तो अच्छा वेतन लेने वाले व प्रशिक्षित राजकीय प्राथमिक पाठशालाओं के अध्यापक पहली कक्षा से बच्चों को अंग्रेजी व अंग्रेजी भाषा में विज्ञान और गणित विषय क्यों नहीं पढ़ा सकते? शिक्षा का आधार तो प्राइमरी स्कूलों में ही बनता है। यदि गरीब के बच्चे से वास्तव में ही सरकार को सच्ची हमदर्दी है, तो उसे भी वही शिक्षा प्रदान की जाए, जो शिक्षा एक अमीर, राजनेता व उच्चाधिकारी का बच्चा ग्रहण कर रहा है। आज गरीब के बच्चे भी शिक्षित होकर उच्च पदों पर विराजमान हैं। कभी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला श्री नरेंद्र मोदी आज विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत का प्रधानमंत्री है। तो एक गरीब परिवार में पैदा हुआ, हर कठिनाइयों का सामना करता हुआ आज श्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री है। आज किसी भी अधिकारी, मंत्री व राजनेता के बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ते। एक तरफ पांचवीं और आठवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं सरकार ने बंद कर दी और दूसरा आठवीं कक्षा तक कोई बच्चा फेल नहीं करना, अर्थात सभी बच्चे पास करने की प्रथा बनाई दी गई है। रही-सही कसर सतत समग्र मूल्यांकन प्रणाली ने पूरी कर दी। सरकारी स्कूलों के अध्यापकों के पास पढ़ाने के लिए सरकार ने समय ही कहां छोड़ा है। उसे राशन डिपुओं से खिचड़ी के लिए राशन भी लाना है, रोज खिचड़ी भी बनवानी है, बच्चों की वर्दी व किताबों का हिसाब भी रखना है व सतत समग्र मूल्यांकन प्रणाली के अधीन तमाम रजिस्टर भी रोज भरने हैं। इसके अतिरिक्त ढेर सारे और अन्य काम भी अध्यापकों को करने हैं, जैसे कि पंचायत चुनाव, विधानसभा व लोकसभा चुनाव, जनगणना व वोटर लिस्ट तैयार करना आदि अनेक कार्य। आठवीं कक्षा तक कोई बच्चा फेल नहीं करना व सतत समग्र मूल्यांकन प्रणाली का असर सरकारी स्कूलों में दसवीं व जमा दो के वार्षिक परीक्षा परिणामों में देखने को मिल रहा है। कई सरकारी स्कूलों में अध्यापक ही पूरे नहीं, ऐसे में परीक्षा परिणाम तो प्रभावित होंगे ही। तो दूसरी तरफ कई स्कूलों के भवन ही पूरे नहीं।

कुछ अलग

धर्मो रक्षति रक्षित

उनके इस तर्क से हतप्रभ होते हुए झुन्नू जी ने कहा कि आप आम लोगों के युवा और बेरोजगार बेटों से धर्म की रक्षा करने का आग्रह करते हैं। लेकिन आपके सभी बच्चे विदेशों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। सुना है कि आपका बड़ा बेटा पढ़ाई के बाद किसी विदेशी बैंक में नौकरी कर रहा है। आज के सत्ताधीशों के एकमात्र एजेंडे में सामाजिक ध्रुवीकरण क्यों है? शत्रुता और सांप्रदायिकता के अलावा कोई और बात क्यों नहीं करते। भुखमरी, लचर शैक्षणिक व्यवस्था, बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं, बेरोजगारी, ईमान की तरह गिरती अर्थव्यवस्था, पलायन, औरतों और मजलूमों पर बढ़ते अत्याचार, अस्त-व्यस्त कानून-व्यवस्था, साम्प्रदायिकता जैसी समस्याओं को हल किए बिना धर्म की पताका कैसे लहरा सकती है। नेता जी हंसते हुए बोले, 'क्या आप यह चाहते हैं कि हम इन मुद्दों पर बात करें। आप पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं और आप शहर के बुद्धिजीवियों में शामिल हैं। मुझे पता है कि आपसे हुई कोई चर्चा बाहर नहीं जाएगी। इसलिए आपसे क्या छिपाना। क्या आपको लगता है कि हमारी सरकार के किसी भी पदाधिकारी में इतनी काबिलियत है या उनकी ऐसी नीयत है कि वह आम लोगों, समाज और देश के बारे में कुछ सोच सके। जब हमने पिछले एक दशक के अपने शासन के दौरान किया ही कुछ नहीं तो लोगों से बताएं क्या? ऐसे में बेहतर तरीका है कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए या तो विपक्ष को गालियां दो, उनकी कमियां निकालो या आए दिन बेसिर पैर का कोई मुद्दा उछाल दो। लोगों का क्या, वे बेचारे भूखे पेट भी अपने मनोरंजन के लिए कोई न कोई जरिया ढूंढ ही लेते हैं। लोग सुनहरी भविष्य के सपने देखते हुए सुअर की तरह माटी में लोटते रहते हैं और हम सत्ता में बने रहते हैं। आपको क्या लगता है कि कल अगर विपक्ष सत्ता में आ गया तो लोग चांदी की कटोरी में दूध-बताशे खाएंगे? हमारे सत्ता में आने से पहले क्या देश स्वर्ग था। आम आदमी की किस्मत में जद्दोजहद ही लिखी है। फिर चाहे राज देसी रजवाड़ों का हो, मुगलों का हो, गोरों का हो या कालों का।' झुन्नू लाल निराश होते हुए बोले, 'लेकिन वास्तव में धर्म की परिभाषा तो 'धारयति इति धर्मः' होती है। धर्म वही जिसे धारा जा सके। आत्म के अलावा तो कोई और धर्म हो ही नहीं सकता।' यह सुनकर नेता जी पहले तो खूब हंसे। फिर गंभीर होते हुए बोले, 'झुन्नू लाल जी, तभी तो आप प्रतिभावान होते हुए झुन्नू ही रह गए। आपकी सारी उम्र लोगों और पार्टी की सेवा करते हुए निकल गई। मुझे देखिए। आपसे तीन दशक बाद राजनीति में आया और आज सांसद हूं। मंत्री बनने की लिस्ट में भी नाम शामिल है। राजनीति का एक ही धर्म होता है, सत्ता और सिर्फ सत्ता। उसके लिए चाहे फूट डालनी पड़े या किसी की जान लेनी पड़े। पार्टी चाहे कोई भी हो, बस कुरसी बनी रहनी चाहिए। क्या प्रदूषित गंगा और क्या गंदे नाले। कुरसी मिलते ही सब आब-ए-हयात हो जाते हैं। अब तो सत्ता कायम रखने के सौ सहारे हैं। तमाम तरह की जांच एजेंसियां हैं, चुनाव आयोग है, ब्यूरोक्रेसी है और आंखों की पट्टी खोल चुकी न्याय की देवी भी हमारे साथ है। धर्म की असली परिभाषा है- कुरसी पर काबिज रहना अर्थात 'धारयति इति सिंहासनः।' हमारे नेतृत्व का धर्म है- साम, दाम, दंड और भेद से सत्ता में बने रहना और हमारा धर्म है किसी भी कीमत पर अपने नेतृत्व के सिंहासन को कायम रखना। उसके लिए चाहे कोई भी कीमत क्यों न अदा करनी पड़े और यह कीमत हम अपनी जेब से तो चुकाते नहीं। लोगों की दमड़ी नहीं तो चमड़ी सही।'

देश दुनीया से

चुनौतियों के बीच विवेकपूर्ण बजट

जबकि पिछली दो तिमाहियों में जीडीपी वृद्धि में कमी, रुपए में गिरावट, मुद्रास्फीति जारी रहना, उपभोग में कमी, व्यापार घाटा बढ़ना, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी के कारण अर्थव्यवस्था की सेहत को लेकर चिंताएं व्यक्त की जा रही थीं। मध्यम आय वाले करदाताओं को कर राहत देने की मांग भी बढ़ रही थी। लेकिन, साथ ही देश की राजकोषीय सेहत भी काफी अच्छी स्थिति में थी, जिसमें राजकोषीय घाटा कम था, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में उछाल, एनआरआई द्वारा बड़ी मात्रा में धन प्रेषण और चालू वित्त वर्ष में निजी निवेश की बढ़ती घोषणाएं इसका प्रमाण दे रही थीं। इससे वित्त मंत्री को छोटे करदाताओं, खासकर वेतनभोगी वर्ग को बड़ी राहत देने और लगभग एक लाख करोड़ रुपए के कर राजस्व और 12 लाख सालाना या कहें कि एक लाख रुपए मासिक आय को आयकर से मुक्त करने का विकल्प चुनने का मौका मिल सका। बजट 2025-26 की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें कॉर्पोरेट टैक्स को लगभग अछूता छोड़ दिया गया है। बजट में उल्लेखनीय बात यह है कि मध्यम वर्ग को एक लाख करोड़ रुपए की राहत के बावजूद बजट का आकार 50 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। बजट घोषणाओं में एक महत्वपूर्ण बात यह देखी गई कि विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है। हालांकि, विनिर्माण को बढ़ावा सिर्फ एक या दूसरे क्षेत्र तक सीमित नहीं है, लेकिन सबके साथ स्वच्छ तकनीक विनिर्माण में भी स्पष्ट रूप से बढ़ावा देखा जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में, इलेक्ट्रिक वाहनों, सौर पैनलों, पवन ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन के लिए ऊर्जा और प्रौद्योगिकी के अन्य नवीकरणीय स्रोतों को बढ़ावा दिया गया है। इस बजट में लिथियम बैटरी, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए मोटर और अन्य स्वच्छ तकनीक विनिर्माण को बढ़ावा देकर स्वच्छ तकनीक मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने का प्रयास किया गया है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आयातित बैटरियों, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए मोटर और सौर सेल पर हमारी अत्यधिक निर्भरता के कारण हमारा आयात बिल बढ़ रहा है और भविष्य में आयातित घटकों पर हमारी निर्भरता के कारण भविष्य में देश का शोषण भी हो सकता है। इसलिए, यह बजट आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दे रहा है और देश को विदेशियों के शोषण से बचा रहा है। एमएसएमई के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन, स्टार्टअप के लिए विभिन्न योजनाएं, भारत को दुनिया का खिलौना हब बनाने के लिए खिलौना उद्योग को प्रोत्साहन आदि घोषणाएं उल्लेखनीय हैं। हालांकि, बजट पर चर्चा में मखाना बोर्ड पर बहुत अधिक बात हो रही है, जो बिहार में किसानों की आय को बहुत जरूरी सहायता प्रदान कर सकता है। दालों में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास, कपास मिशन और कृषि के लिए कई अन्य योजनाएं भी कम सराहनीय नहीं हैं। शायद, निर्मला सीतारमण यह कहने में सही हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में पलायन एक विकल्प बन सकता है, लेकिन सरकार के प्रयासों से ग्रामीण क्षेत्रों में आय में वृद्धि के साथ यह अब एक मजबूरी नहीं रहेगी। देश के सामने ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में सापेक्ष आय में कमी की एक बड़ी चुनौती है। आर्थिक सर्वेक्षण ने सुझाव दिया कि ग्रामीण और शहरी आबादी के बीच में एमपीसीई (मासिक प्रतिव्यक्ति खर्च) का अंतर 84 प्रतिशत से घटकर 70 प्रतिशत हो गया है। यह ग्रामीण सडकों, आवास, स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन, पानी, बिजली, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता और कई अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर बढ़ते खर्च के कारण संभव हुआ है। बजट के प्रावधान इस प्रवृत्ति को आगे बढ़ाने वाले हैं। बजट 2025-26 ग्रामीण आय को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करता है। किसान क्रेडिट कार्ड की 5 लाख तक उच्च सीमा, कृषि को बढ़ावा, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा और ग्रामीण आय बढ़ाने के लिए कई अन्य प्रयास ग्रामीण-शहरी असमानताओं को कम करने में एक लंबा रास्ता तय कर सकते हैं। स्वास्थ्य उपकरणों के लिए प्रोत्साहन, मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ाना, केंद्रीय बजट 2025-26 में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए 98311 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जो विकास के लिए एक महत्वपूर्ण बढ़ावा देने का संकेत देते हैं, जिसमें जीवन रक्षक दवाओं पर सीमा शुल्क छूट और डेकेयर कैंसर केंद्रों की स्थापना जैसे प्रमुख उपाय कुछ आवश्यक कदम हैं, जो इस बजट में उठाए गए हैं। पीएम रिसर्च फेलोशिप योजना के तहत 10 हजार छात्रवृत्तियों की घोषणा स्वागतयोग्य पहल है, लेकिन भारत की शिक्षा प्रणाली की मूलभूत कमियों को संबोधित नहीं करती है। हालांकि कौशल विकास कार्यक्रम महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वे गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की आवश्यकता की जगह नहीं ले सकते। सरकार को आलोचनात्मक सोच, अनुसंधान और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करते हुए शिक्षा के मूलभूत पहलुओं को मजबूत करने को प्राथमिकता देनी चाहिए। उच्च शिक्षा में पर्याप्त सुधारों के बिना, कौशल विकास कार्यक्रम उद्योग की जरूरतों और कार्यबल क्षमताओं के बीच अंतर को पाटने में अपर्याप्त रहेंगे। इलेक्ट्रिक कारों को सस्ता करने से पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिलेगी। मोबाइल सस्ता हो रहा है। इससे करोड़ों उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। रोगियों के लिए भी सरकार ने अच्छे इंतजाम किए हैं। आवश्यक दवाएं सस्ती हो जाएंगी। साथ ही कपड़ा भी सस्ता हो जाएगा। इससे भी करोड़ों लोगों को लाभ मिलेगा। एलईडी आदि भी अब सस्ते हो जाएंगे। इससे भी लोगों को राहत मिलेगी। हालांकि, यह भी सच है कि बजट की सफलता कार्यान्वयन पर निर्भर करती है। युवाओं को रोजगार देने की भी कोशिश की गई है, हालांकि प्राइवेट सेक्टर को भी प्रोत्साहन देकर ही बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो सकता है।

आप का नजरीया

अल्लाह विभाग को मेघ दे

विभागीय कसौटियों में अब सतसंग, लोक परंपराएं और धार्मिक मान्यताएं भी शरीक होने लगी हैं। यह कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग के दायित्व में हो, तो इसके उद्देश्य समझे जा सकते हैं, लेकिन जल शक्ति विभाग भी अगर पानी के लिए मंदिरों में अरदास करता दिखे, तो योजनाओं पर किए गए हस्ताक्षर गौण हो जाएंगे। धर्मशाला के जल शक्ति विभाग का सारा कुनबा इंद्रु नाग की शरण में दंडवत है, क्योंकि अब तक सारी परियोजनाएं बहते पानी में हाथ धोती रहीं। न जल संरक्षण की कोई प्राथमिकता और न ही जलापूर्ति संरचना की कोई वैज्ञानिक या आवश्यकता के अनुरूप स्थायी बंदोबस्त। प्रकृति मेहरबान रहे, बारिशें होती रहें और पहाड़ पर बर्फबारी का प्रबंध दैवीय शक्ति से होता रहे, तो जलशक्ति विभाग, इस प्रचुरता के साक्ष्यों में अपने फर्ज की 'गुड बुक' में रहना पसंद करता है। हमारी जलापूर्ति का आधार प्राकृतिक जल स्रोतों के सीधे बहाव और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर पहाड़ियों से नीचे बहने का मुहाना है। ऐसे में प्रकृति के व्यवहार व जलवायु परिवर्तन की मार से पैदा हो रही प्रतिकूल प्रतिस्थितियों में जलशक्ति विभाग ने आखिर कौन सा नवाचार किया। ईश्वर का फरियादी बन कर आखिर इंद्रुनाग बरसेंगे भी कितनी बार, क्योंकि वहां आम इनसान तो पहले से खड़ा है। किसी को खेती के लिए पानी चाहिए, तो कोई बच्चों की शादी या पारिवारिक समारोह के दौरान आसमान को बादलों से दूर रखने की मन्नत मांग रहा है। हम चाहेंगे कि इंद्र देवता खूब बरसें, समय-समय पर नियमितता के साथ बरसें, लेकिन यह मन्नत है भविष्य की तैयारी नहीं। खासतौर पर जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच जलशक्ति विभाग की तैयारी यह तो कतई नहीं हो सकती कि हर मुसीबत के वक्त ईश्वरीय शक्ति को परीक्षा में डाला जाए। जनवरी में 85 प्रतिशत कम बरसे हैं मेघ, तो कृषि, बागवानी और जलशक्ति विभाग की तत्परता भी कहीं पानी लाने गई है। प्रदेश में बर्फबारी का पैटर्न बुरी तरह बदल रहा है और पिछले कुछ दशकों में मौसम की सफेदी ने खुद को तीस फीसदी कम पर समेट लिया, लेकिन क्या कोई सर्वेक्षण या शोध जलशक्ति विभाग ने किया। राजस्थान में तो बर्फाच्छादित पहाड़ नहीं होते, फिर भी वहां की जनता पानी पीती है। इस अंतर को समझना होगा। हमने कौन सा ऐसा बांध बनाया जो पेय जल आपूर्ति का शक्ति स्रोत बना। हमारी परंपराओं में पेय जल आपूर्ति सामुदायिक व्यवहार की शक्ति रही है। हमीरपुर के साथ मंडी और कांगड़ा के कुछ इलाकों में खातरियों के जरिए प्यास को सारा साल बुझाया जाता रहा है, तो हर गांव ने जलसंरक्षण की अवधारणा में प्राकृतिक स्रोतों को परिष्कृत किया। आश्चर्य यह कि मनरेगा के बजट और दिहाड़ी ने प्राकृतिक जलस्रोत ही सुखा दिए। यह दीगर है कि धूमल सरकार ने वाटर हार्वेस्टिंग का संकल्प लेकर ग्रामीण एवं शहरी प्लानिंग का उद्घोष किया, लेकिन राजनीतिक बदलाव ने ये पन्ने फाड़ दिए और संबंधित विभाग भूल गए कि यह वक्त की जरूरत है। ग्रामीण एवं शहरी विकास विभाग, नगर नियोजन और जलशक्ति विभाग अगर वाटर हार्वेस्टिंग की दिशा में कुछ कर पाते, तो हर गांव और शहर का जल कोष स्थापित होता। आश्चर्य यह कि नवनिर्माण के पंजों ने नदी-नालों और कूहलों तक को नहीं बख्शा।

अनिता चौधरी हत्याकांड : सीबीआई ने केस दर्ज किया, तैयब अंसारी और सुनीता नामजद

जोधपुर (हिंस)। बहुचर्चित अनिता चौधरी हत्याकांड मामले में अब सीबीआई ने भी केस दर्ज कर लिया है। रिपोर्ट मुख्य आरोपी गुलामुदीन के साथ अब सुनीता और कारोबारी को भी नामजद किया गया है। पुलिस ने हाल ही में मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन और उसकी पत्नी को दोषी मानते हुए चार्जशीट दाखिल की थी। सीबीआई की तरफ से अब केस दर्ज में तफ्तीश आरंभ की जाएगी। सीबीआई पहले ही एक केस लवली कंडारा की जांच में जोधपुर में बैठी है और जांच पड़ताल में जुटी है। इधर अनिता चौधरी हत्याकांड को लेकर काफी समय से परिजन की तरफ से सीबीआई जांच की मांग की जाती रही है। राज्य सरकार से भी सीबीआई जांच की मांग रखी गई थी। पुलिस द्वारा प्रकरण से जुड़े आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद अब केस

दर्ज किया गया है। उल्लेखनीय है कि जोधपुर कमिश्नरेट पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट पेश की थी। पुलिस ने अनिता हत्याकांड में मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन और उसकी पत्नी आबिदा को ही आरोपी मानते हुए उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। जांच अधिकारी एडीसीपी (महिला अपराध अनुसंधान सेल पश्चिम) सुनील के पंवार ने नियत समय में मामले की जांच कर गत तीस जनवरी को कोर्ट में यह चार्जशीट पेश कर दी जिसमें गुलामुद्दीन द्वारा अनिता की हत्या कर टुकड़ों में काटना और उसकी पत्नी को उसका सहयोगी माना है। दोनों आरोपी अभी न्यायिक हिरासत में चल रहे हैं। जांच अधिकारी सुनील के पंवार ने बताया कि अनिता चौधरी की हत्या लूट के इरादे से की गई थी। गत 27 अक्तूबर को अनिता अपने पार्लर से गुलामुद्दीन के घर गई, तो वह उसे एस्कॉर्ट कर रहा था। नशीला पदार्थ पिलाकर उसे बेहोश किया गया। उसके पहने हुए जेवर उसने उतार लिए। अपनी पत्नी को उसकी बहन के घर भेज दिया। अगले दिन 28 अक्तूबर को सुबह जब अनिता नहीं उठी, तो वह घबरा गया। बेहोशी की हालत में उसने सिर फोड़कर हत्या कर दी। शव को ठिकाने लगाने के लिए उसने सरदारपुरा से एक तेज चाकू खरीदा जिससे छह टुकड़े कर शव गाड़ दिया था। पुलिस ने इस हाइप्रोफाइल मामले में एक प्रॉपर्टी डीलर को भी कई दिनों तक हिरासत में रखा था। लेकिन उसके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं मिले, जिसके चलते उसे छोड़ना पड़ा। फिलहाल पुलिस को अभी अनिता चौधरी के मोबाइल से कुछ सबूत मिलने की उम्मीद है, जो अभी एफएसएल जांच में गया हुआ है। अगर कुछ अन्य तथ्य आते हैं, तो उनको भी पूरक चार्ज शीट में शामिल किया जाएगा। हत्या के बाद भागा था मुंबई जांच में सामने आया कि 29 अक्तूबर को गुलामुद्दीन जोधपुर से मुंबई भाग गया था। तीन नवंबर को वह वापस जोधपुर लौटा। अपने रिश्तेदार की दुकान पर गया, तो जोधपुर के अखबार और टीवी चैनल पर अनिता हत्याकांड की खबरें देखीं। इसके बाद वह अशोक उद्यान की तरफ गया। जांच में सीसीटीवी में पुलिस को नजर आया।

अमृतसर में बंद पड़ी पुलिस चौकी में धमाका

चंडीगढ़(हिंस)। पंजाब के अमृतसर जिले में सोमवार की रात एक बंद पड़ी पुलिस चौकी में जोरदार धमाका हुआ है। पुलिस इस मामले जांच कर रही है लेकिन अमृतसर के पुलिस आयुक्त ने किसी प्रकार के धमाके से इनकार कर दिया है। जानकारी के मुताबिक अमृतसर बाईपास पर स्थित फतेहगढ़ चूड़ियां पुलिस चौकी में यह धमाका देर रात सुना गया। इसमें किसी के मारे जाने या घायल होने की सूचना नहीं है। घटनास्थल पर करीब छह इंच का गड्ढा देखा जा सकता है। इसकी जिम्मेदारी किसी आतंकी संगठन ने नहीं ली है। जिस फतेहगढ़ चूड़ियां पुलिस चौकी को निशाना बनाया गया, वह पिछले साल बंद हो चुकी थी। धमाके की सूचना मिलते ही पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर अन्य अधिकारियों के साथ पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना कर मामले की जानकारी ली। पुलिस कमिश्नर अमृतसर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने स्थिति का जायजा लेने के लिए तुरंत घटनास्थल का दौरा किया। सीपी भुल्लर ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि यह आवाज किसी ग्रेनेड धमाके के कारण नहीं हुई है, लेकिन पुलिस इस आशंका से पूरी तरह इनकार भी नहीं कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि इसका प्रभाव बहुत कम था और शुरुआती तौर पर किसी विस्फोट के संकेत नहीं मिले हैं। हालांकि, पुलिस इस आवाज के कारणों का पता लगाने के लिए सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है।

राशन कार्ड नहीं बनने से परेशान युवतियों ने डीएफएससी को दफ्तर में घुसकर पीटा

पुलिस ने दो युवतियों के विरुद्ध दर्ज की एफआईआर

सोनीपत(हिंस)। सोनीपत में दो लड़कियों ने जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक की धुनाई कर दी। लड़कियां कई दिनों से राशन कार्ड के सिलसिले में जिला खाद्य एवं आपूर्ति कार्यालय के चक्कर लगा रही थीं। डीएफएससी से बात करने के बाद लड़कियां बाहर जा रही थी तो अचानक वापस लौटी और डीएफएससी हरवीर सिंह को थप्पड़ मारने लगी। शोर शराबा सुनकर कर्मचारी वहां आ गए। उनके सामने भी लड़की ने अधिकारी को कई थप्पड़ जड़ दिए। डीएफएससी की शिकायत पर पुलिस ने दोनों लड़कियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस जांच कर रही है कि अचानक बाहर जा रही लड़कियां किस बात पर भड़क गईं। सोनीपत के डीएफएससी हरवीर सिंह ने पुलिस को बताया कि दो लड़कियां राशन कार्ड, फैमिली आईडी से संबंधित समस्या लेकर उनके कार्यालय में आई थी। इनमें से एक लड़की एक के बाद एक 3-4 बार कार्यालय में आई। दोनों लड़कियों को राशन कार्ड से जुड़ा प्रक्रिया के बारे में पहले ही विस्तार से समझा दिया था। अंतिम बार जब वह लड़की उनके पास आई और पूछा कि उसे समाधान शिविर मे जाकर क्या बताना है। अधिकारी ने उसे फिर से पूरी प्रक्रिया के बारे मे बताया। इसके बाद लड़की दरवाजे की तरफ गई। फिर एक दम से वापस मुड़कर आ गई। लड़की ने मेज पर रखी चीजों को धक्का मारा, जिसकी वजह से वहां रखा पानी का ग्लास, डीएफएससी का फोन आदि फर्श पर गिर गया। लड़की ने इसके बाद चिल्लाते हुए डीएफएससी को थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। साथ ही वह आवाज देकर अपने साथियों को बुलाने लगी। कार्यालय में शोर-शराबा सुनकर अधीक्षक भी वहां पहुंची। इसके बाद दूसरे स्टाफ के कर्मी भी वहां उनके कमरे में आ गए। डीएफएससी का कहना है कि अधीक्षक के सामने भी लड़की ने उसे थप्पड़ मारे। बड़ी मुश्किल से लड़कियों को वहां से हटाया गया। डीएफएससी ने पुलिस को बताया कि बाद में उनको पता चला कि थप्पड़ मारने वाली लड़की सोनिया थी और उसके साथ आई दूसरी लड़की का नाम मोनिका है। डीएफएससी का आरोप है कि दोनों लड़कियों ने किसी सोची-समझी साजिश के तहत यहां हंगामा किया उसके साथ मारपीट की है। उसने दोनों लड़कियों के खिलाफ पुलिस से कार्रवाई की अपील की। सोनीपतके सिविल लाइन थाना के एसआई परविंद कुमार के अनुसार, डीएफएसी हरवीर सिंह ने कार्यालय में हुई घटना को लेकर दो लड़कियों के खिलाफ शिकायत दी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौके का मुआयना किया, ऑफिस के अन्य कर्मियों से घटना का ब्योरा लिया और इसके बाद मामला दर्ज किया है।

सफाई कर्मचारी यूनियन अध्यक्ष मोहन की संदिग्ध हालात में मौत

धौलपुर (हिंस)। राजस्थान सफाई कर्मचारी मजदूर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष मोहन सिंह थनवार की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। पुराने नगर परिषद कार्यालय में उनका शव फंदे से लटका मिला है। इस संबंध में थनवार के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए कोतवाली में मामला दर्ज कराया है। उधर, पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक राजस्थान सफाई कर्मचारी मजदूर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष तथा नगर परिषद में वरिष्ठ सफाई निरीक्षक के रूप में तैनात मोहन सिंह थनवार का शव पुराने नगर परिषद कार्यालय में फंदे से लटका मिला है। शहर के संतर रोड इलाके के निवासी करीब 55 वर्षीय थनवार के सोमवार देर रात तक घर नहीं पंहुचने पर उनकी तलाश में नगर परिषद पहुंचे उनके पुत्र करन सिंह को उनका शव फंदे में लटका मिला। मंगलवार सुबह एफएसएल टीम के साथ में मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने मृतक मोहन सिंह थनवार के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया है। इस संबंध में मृतक थनवार के पुत्र करन सिंह ने कोतवाली में अज्ञात लोगों के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज कराया है। घटना की जानकारी मिलने पर डीएम श्रीनिधि बी टी तथा एसपी सुमित मेहरडा भी मौके पर पंहुचे तथा हालात का जायजा लिया। पुलिस द्वारा हत्या के साथ-साथ अन्य एंगल से भी मामले की जांच की जा रही है।

छावा का प्रमोशन करने जयपुर आए विक्की कौशल ने फैंस से कहा, खम्माघणी जयपुर

जयपुर (हिंस)। छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित फिल्म छावा के प्रमोशन के लिए अभिनेता विक्की कौशल जयपुर पहुंचे। राज मंदिर सिनेमा पर फैंस के बीच उन्होंने फिल्म का प्रमोशन किया, साथ ही खम्माघणी कहकर अभिवादन करते हुए हर-हर महादेव का जयकारा लगाया। इस दौरान राजमंदिर में ही फिल्म का एक प्रोमो वीडियो भी रिलीज किया गया। लक्ष्मण उटेकर की ओर से निर्देशित पीरियड ड्रामा छावा में विक्की कौशल और रश्मिका मंधाना लीड रोल प्ले कर रहे हैं, जबकि अक्षय खन्ना फिल्म में नेगेटिव किरदार निभा रहे हैं। फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से दर्शकों में जबर्दस्त क्रेज है और यही क्रेज मंगलवार को जयपुर में दिखा। विक्की कौशल फिल्म के प्रमोशन के लिए राज मंदिर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने फैंस का अभिवादन किया। साथ ही कहा कि जयपुर आकर जोश हाई हो जाता है। कोई नई फिल्म आए और जयपुर ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। इस बार 14 फरवरी को छावा आ रही है। उन्होंने कहा कि जयपुर आकर हमेशा खुश होते हैं। जब भी कोई नई फिल्म रिलीज होती है, तो उसकी शुरुआत जयपुर से होती है, क्योंकि जयपुर की धरती से, जयपुर के लोगों के प्यार और आशीर्वाद के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। वो जब-जब जयपुर आए मूवी हिट हुई है। पहले *जरा हटके जरा बचके* आई थी, उसमें तेरे वास्ते सॉन्ग का लॉन्च जयपुर में किया था। वो गाना और फिल्म सुपरहिट रही। उसके बाद *सैम बहादुर* के लिए आए, वो मूवी भी सुपरहिट रही। इस बार छावा मूवी को लेकर आए हैं जो सुपर हिट से आगे जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि छावा फिल्म हमारे देश के महान योद्धा, महान राजा छत्रपति संभाजी महाराज पर आधारित है। उन्होंने संभाजी महाराज का जयकारा लगाते हुए कहा कि उनकी वीरता पूर्ण यात्रा की शक्तिशाली झलक इस फिल्म में पेश की गई है। इस फिल्म का टीजर, ट्रेलर और गाना बाहर आ चुका है, जिसको लोगों का बहुत प्यार मिला है, हिट रहा है और अब जयपुर में फिल्म का एक प्रोमो वीडियो रिलीज किया जा रहा है। ये ज्यादा हिट रहना चाहिए। इससे पहले विक्की कौशल का स्वागत महाराष्ट्र के प्रसिद्ध ढोल-ताशे बजाते हुए किया गया, जिस पर विक्की कौशल भी झूम उठे।

डल्लेवाल के समर्थन में खनौरी पहुंचे सोनीपत के किसान

सोनीपत (हिंस)। खरखौदा में मंगलवार को भारतीय नौजवान किसान यूनियन से जुड़े विभिन्न गांवों के किसान अपने-अपने खेतों का जल लेकर खनौरी बॉर्डर पर धरना दे रहे किसान नेता डल्लेवाल के समर्थन में रवाना हुए। यूनियन के ब्लॉक प्रधान वेद प्रकाश उर्फ वेदी गोपालपुर ने कहा कि यह भ्रांति फैलाई जा रही है कि खनौरी बॉर्डर पर केवल पंजाब के किसान धरना दे रहे हैं। जबकि हरियाणा के सभी क्षेत्रों से किसान खनौरी बॉर्डर पर धरने में एक साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार किसानों की मांगों को पूरा नहीं करती है तब तक किसान अपने धरने पर डटे रहेंगे। क्योंकि किसान नेता डल्लेवाल सभी किसानों के हकों की लड़ाई लड़ने के लिए आमरण अनशन पर है। लंबे समय से किसान अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।

सूर्य सप्तमी महोत्सव : जोधपुर शहर में धूमधाम से निकाली शोभायात्रा

जोधपुर (हिंस)। शाकद्वीपीय ब्राह्मण समाज द्वारा सूर्यसप्तमी महोत्सव मंगलवार को धूमधाम से श्रद्धापूर्वक मनाया गया। इस दौरान शहर के भीतरी भाग में शोभायात्रा निकाली गई। साथ ही यज्ञ, महाप्रसादी का आयोजन हुआ। मंदिरों में भगवान सूर्य की विशेष पूजा अर्चना की गई। शाकद्वीपीय ब्राह्मण समाज के विभिन्न घटकों के सहयोग से सप्तमी पर आज शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा फतेहपोल से रवाना हुई। बैंडबाजों, शहनाई, ढोल-नगाड़ों के साथ समाज के लोग चल रहे थे। देशभक्ति का संदेश देते महापुरुष के रूप में युवा व बच्चे घोड़े पर सवार थे। इस दौरान अखाड़ों द्वारा हैरतअंगेज करतब दिखाए गए। भगवान सूर्यदेव का रथ भी साथ चल रहा था। शोभायात्रा फतेहपोल से गुंदी का मोहल्ला, नवचौकिया, नायो का बड़, फुलेराव, चांदपोल से भास्कर वाटिका विद्याशाला रोड आकर विसर्जित हुई। शोभायात्रा में पुरुषों ने सिर पर भगवा साफा और महिलाओं ने भगवा रंग की साड़ी पहनकर भाग लिया। बच्चों ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सूर्य भगवान का वेश धारण किया। भगवान सूर्यनारायण को समर्पित प्रमुख मंदिरों में रातानाडा, भास्कर चौराहा, पंचवटी कॉलोनी स्थित

सूर्य प्रतिष्ठानों स्थापित भगवान सूर्यनारायण व मां गायत्री की विशेष पूजा अर्चना की गई। राजस्थान शाकद्वीपीय ब्राह्मण संघ जोधपुर की ओर से सूर्य प्रतिष्ठान प्रांगण में सूर्य सप्तमी, रथ सप्तमी का पर्व मनाया गया जिसमें सुबह भगवान सूर्य देव को सामूहिक अर्घ्य के बाद में सूर्य गायत्री शांति यज्ञ का आयोजन हुआ। साथ ही भास्कर चौराहा पर पुष्प माला व लाइटिंग से सजावट की गई। राजस्थान शाकद्वीपीय ब्राह्मण संघ के अध्यक्ष अधिवक्ता सूर्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि दोपहर में रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। फिर बच्चों व युवाओं के लिए विविध खेलकूद प्रतियोगिताएं हुई। बालिकाओं के लिए विशेष रूप से रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई।

मेगा हाईवे पर कार-जीप में भिड़ंत एक परिवार के पांच लोगों की मौत

बाड़मेर (हिंस)। बालोतरा जिले के सिणधरी पुलिस थाना क्षेत्र में मेगा हाईवे पर पायला कला के पास सोमवार देर शाम एक कार और जीप की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए और कार में सवार एक ही परिवार के चार लोगों की मौके पर मौत हो गई। जबकि एक गंभीर घायल ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी घटनास्थल पहुंचे और मामले की जानकारी जुटाई। सिणधरी थानाधिकारी सुरेश सारण ने बताया कि मेगा हाईवे पर हादसे में कार में सवार अशोक (60) पुत्र शिवलाल, श्रवण (28) पुत्र अशोक, मंदीप (04) पुत्र प्रवीण सोनी, रिंकू (6 माह) पुत्री अरुण सोनी, ब्यूटी (25) पत्नी अरुण सोनी निवासी पायला कलां की मौत हो गई। जबकि अरुण पुत्र अशोक, अभिनंदन पुत्र अरुण सोनी गंभीर घायल हो गए। दूसरी गाड़ी में सवार राणाराम पुत्र मोमताराम निवासी डांगेवा, दिनेश पुत्र चंदाराम निवासी डांगेवा, मोमताराम पुत्र गणेशाराम, चंदाराम पुत्र मोमताराम निवासी डांगेवा गंभीर घायल हो गए। घायलों को राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया। जहां उनका उपचार चल रहा है। पायला कलां निवासी अशोक सोनी परिवार के साथ कार में सवार होकर सिणधरी से गांव लौट रहे थे। मेगा हाईवे पर हुए इस हादसे में अशोक समेत पुत्र, पुत्रवधु और पौत्र व पौत्री की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में रिश्तेदार व ग्रामीण अस्पताल पहुंच गए। हादसे के बाद पूरे गांव में मातम छा गया।

मिल्कीपुर में सपा पोलिंग एजेंटों को धमकाया जा रहा है : राजेंद्र चौधरी

लखनऊ (हिंस)। समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी एवं प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने संयुक्त रूप से पत्रकार वार्ता की। इसमें मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि मिल्कीपुर में सपा पोलिंग एजेंटों को धमकाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के समर्थकों के घरों पर जाकर तलाशी ली जा रही है। मिल्कीपुर में आतंक का वातावरण व्याप्त है। इसीलिए अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि मीडिया को मिल्कीपुर के उपचुनाव को देखने पहुंचना चाहिए। यह देखना चाहिए कि किस तरह से भाजपा के इशारे पर प्रशासन लोकतंत्र को प्रभावित करने में लगा हुआ है। समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र ने कहा कि मिल्कीपुर में एक दिन पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर में चुनाव सभा को संबोधित किया था। पहले परिमिशन नहीं दी गई, फिर जहां दिया

गया, वहां पर भी प्रशासन ने आम जनता को सभा में पहुंचने में अवरोध प्रस्तुत किया। भाजपा लोकतंत्र की हत्या करना अपना धर्म मानती है। डिम्पल यादव ने मिल्कीपुर में रोड शो किया तो उसमें भी व्यवधान पैदा किया गया। मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि कल मतदान है, निष्पक्ष चुनाव हो जाएं इसमें प्रशासन रोड़ा बनी हुई हैं। लोकतंत्र में प्रशासन की जिम्मेदारी व्यवस्था करने की होती है। भाजपा जिस तरह से प्रशासन का उपयोग कर रही है, सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, उससे निर्वाचन आयोग मौन नहीं रह सकता। निर्वाचन आयोग को लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सम्पन्न कराने की जिम्मेदारी है। पिछले दिनों जो उपचुनाव में नंगा नाच हुआ, उसे देश जानता है।

भाखड़ा हादसे में मारे गए सात लोगों के परिजनों को सरकार ने जारी की आर्थिक सहायता

फतेहाबाद (हिंस)। जिले के रतिया क्षेत्र के गांव सरदारेवाला के पास क्रूजर गाड़ी के भाखड़ा नहर में गिरने से 12 लोगों की मौत होने के मामले में प्रदेश सरकार ने आर्थिक सहायता जारी कर दी है। मंगलवार को जारी पत्र के अनुसार प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत हरियाणा के 7 मृतकों और एक घायल को 15 लाख की आर्थिक सहायता जारी की गई है। मृतकों को 2-2 लाख रुपए तथा एक घायल को एक लाख रुपए की आर्थिक सहायता की राशि उनके परिजनों के खातों में भेजी गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के ओएसडी ने इस बारे फतेहाबाद की उपायुक्त मनदीप कौर को भी पत्र भेजा है। बता दें कि 31 जनवरी की रात को पंजाब के फाजिल्का के एक गांव में विवाद समारोह में शामिल होकर रतिया के गांव महमड़ा के लोग पंजाब के कुछ रिश्तेदारों के साथ एक क्रूजर गाड़ी में सवार होकर वापस महमड़ा लौट रहे थे। रास्ते में गांव सरदारेवाला के पास उनकी क्रूजर गाड़ी भाखड़ा नहर में जा गिरी। इस हादसे में गाड़ी में सवार 14 में से 12 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 लोग जिंदा बचे हैं। सोमवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मृतकों को दो लाख व घायलों को एक लाख रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की थी। मंगलवार को 7 मृतकों व एक घायल के परिजनों के खाते में कुल 15 लाख रुपए डाल दिए गए हैं। इनमें से मृतक झंडो बाई के पुत्र जरनैल सिंह, अंगीरो बाई के पति जांगीर सिंह, बलबीर सिंह की पत्नी सुखा बाई, तारो बाई के पति चांद सिंह, छिंदर सिंह की पत्नी गुरदीप कौर, बालक सहजदीप के पिता रविंद्र सिंह व मृतक लखविंदर कौर के पति रविंद्र सिंह के खाते में 2-2 लाख रुपए तथा हादसे में घायल जरनैल सिंह के खाते में एक लाख रुपए की राशि ट्रांसफर की गई है।

महाकुंभ प्रयागराज से लाखों श्रद्धालु काशी विश्वनाथ दरबार में पहुंच रहे

मंदिर परिक्षेत्र श्रद्धालुओं से पटा, गंगा घाट भी भीड़ से फुल

वाराणसी (हिंस)। प्रयागराज महाकुंभ से लाखों श्रद्धालुओं का काशी विश्वनाथ धाम में अनवरत पलट प्रवाह बना हुआ है। वसंत पंचमी पर महाकुंभ के तीसरे अमृत स्नान (शाही स्नान) के बाद श्रद्धालु मंगलवार तड़के से ही शहर में उमड़ने लगे। रेलवे स्टेशन और शहर की सीमा से श्रद्धालु पैदल ही गंगा स्नान और श्री काशी विश्वनाथ दरबार में दर्शन-पूजन के लिए आते दिखे। पूरे राह आने-जाने वाले श्रद्धालुओं की सेवा में विभिन्न सामाजिक संगठन जुटे हुए हैं। लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और मंदिर में सुगम दर्शन को लेकर अफसर भी व्यवस्था का लगातार जायजा लेते दिखे। मंदिर में भी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। मंदिर न्यास ने श्रद्धालुओं के सुचारू और सुरक्षित दर्शन के लिए कई प्रबंध किए हैं। इनमें भीड़ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त कर्मी है। धाम में श्रद्धालुओं की चिकित्सकीय सहायता के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया गया है। मंदिर परिसर में स्वच्छता को लेकर खासा ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए अतिरिक्त कर्मचारी तैनात किए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मार्गदर्शन पथ और नियंत्रित जिगजैग कतार व्यवस्था लागू है। इसके अलावा जिलाधिकारी एस राजलिंगम, पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल, अपर पुलिस आयुक्त डॉ. एस चिनप्पा व अन्य अफसर भी लगातार व्यवस्था पर पैनी नजर जमाए हुए हैं। मंदिर परिसर और धाम परिक्षेत्र में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। मंदिर प्रशासन ने फरवरी माह के शुरुआती तीन दिनों में मंदिर में आए श्रद्धालुओं का आंकड़ा जारी किया है। इसमें एक फरवरी को 05लाख 69 हजार, दो फरवरी को 04 लाख 61 हजार, तीन फरवरी को सायंकाल 7.30 बजे तक 04 लाख 76 हजार श्रद्धालुओं ने दर्शन-पूजन किया था। वहीं, 31 जनवरी को 07 लाख 53 हजार, 30 जनवरी को 07 लाख 29 हजार श्रद्धालुओं ने दर्शन-पूजन किया था। मंदिर न्यास के अनुसार इस समय महाकुंभ के कारण प्रयागराज संगम से श्रद्धालुओं का बड़ी संख्या में पलट प्रवाह श्री काशी विश्वनाथ धाम में हो रहा है। इस पलट प्रवाह के दृष्टिगत श्रद्धालुओं को सुरक्षित सुगम दर्शन सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था के अंतर्गत श्रावण मास के समान एंड टू एंड बैरिकेड के साथ श्रद्धालुओं के सतत प्रवाह को स्ट्रीमलाइन करते हुए दर्शन की व्यवस्था की गई है।

बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा की सुनवाई आज फिर टली

पटना (हिंस)। बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) परीक्षा को लेकर आज पटना हाई कोर्ट में होनेवाली अहम सुनवाई एक बार फिर से टल गई है। इस बार भी पीठ के उपस्थित नहीं होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी थी। न्यायाधीश अरविंद सिंह चंदेल की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई होनी थी। बीपीएससी 70वीं प्रारंभिक परीक्षा रद्द कर दोबारा परीक्षा लेने की मांग को लेकर पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। याचिका में बीपीएससी पर धांधली करने का कथित आरोप लगाया गया था। मामले पर बीते 31 जनवरी को बेंच के उपस्थित नहीं होने के कारण पटना हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी थी। 04 फरवरी को पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश अरविंद सिंह चंदेल की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई होनी थी लेकिन ऐन वक्त पर सुनवाई टल गई है। बीपीएससी अभ्यर्थियों को आज पटना हाईकोर्ट में होने वाली अहम सुनवाई का इंतजार था। इससे पहले बीते 16 जनवरी को हुई सुनवाई के दौरान पटना हाई कोर्ट ने बीपीएससी से जवाब तलब किया था।आज फिर से हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी थी लेकिन अब सुनवाई टल गई है। फिलहाल अगली सुनवाई कब होगी यह स्पष्ट नहीं हो सका है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इस मामले पर सुनवाई की मांग की गई थी लेकिन कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को पटना हाई कोर्ट जाने की सलाह दी थी और याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद अभ्यर्थियों के एक गुट ने पटना हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर परीक्षा को फिर से कराने की मांग की थी। कोर्ट ने रिजल्ट रोकने से इनकार किया था। जिसके बाद बीपीएससी ने पीटी परीक्षा का रिजल्ट पिछले दिनों घोषित कर दिया था।

अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे पीडीएस डीलरों ने धरना के बाद विधायक को सौंपा मांगों का ज्ञापन

अररिया (हिंस)। बिहार राज्य फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के महामंत्री वरुण सिंह के आह्वान पर जन वितरण प्रणाली के दुकानदार आठ सूत्री मांगों को लेकर एक फरवरी से ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। फारबिसगंज फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष उद्यानंद मेहता और अरुण निराला के नेतृत्व में पीडीएस डीलरों ने मंगलवार को प्रखंड कार्यालय में धरना दिया। धरना के बाद पीडीएस डीलरों ने स्थानीय विधायक विद्यासागर केसरी उर्फ मंचन केसरी के आवास स्थित जनसंपर्क कार्यालय पहुंचकर अपने आठ सूत्री मांगों के समर्थन वाली एक मांग पत्र विधायक को सौंपा। संगठन के फारबिसगंज अध्यक्ष उद्यानंद मेहता ने विधायक को बताया कि जन वितरण विक्रेता अंबिका प्रसाद यादव 20 जनवरी 2025 से पटना के गर्दनीबाग में अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। सरकार की ओर से अनशन को समाप्त करने की दिशा में किसी तरह का कोई सकारात्मक पहल नहीं किया गया, जिसके कारण वे लोग एक फरवरी से ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। उन्होंने विधायक को बताया कि उन लोगों की मांग गुजरात सरकार के तर्ज पर प्रतिमाह मानदेय 30 हजार रुपए देने, दुकान संचालन के लिए अन्य राज्यों की भांति डीलर मार्जिन मनी देने सहित कुल आठ मांगें हैं।

डॉ. अग्रवाल्स हेल्थ केयर का शेयर एनएसई पर सपाट और बीएसई पर मानइस में हुआ लिस्ट

नई दिल्ली

डॉ. अग्रवाल्स हेल्थ केयर लिमिटेड (डीएएचसीएल) के शेयरों की मंगलवार को स्टॉक एक्सचेंज पर सपाट शुरुआत हुई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर डीएएचसीएल कंपनी का शेयर इश्यू प्राइस 402 रुपये पर लिस्ट हुआ।

वहीं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) पर शेयर इश्यू प्राइस से 1.27 फीसदी नीचे 396.90 रुपये पर सूचीबद्ध हुआ। डॉ. अग्रवाल्स हेल्थ केयर लिमिटेड के आईपीओ का मूल्य 302.7.26 करोड़ रुपये है। कंपनी का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 29 से 31 जनवरी तक खुला रहा था। आईपीओ का मूल्य दायरा (प्राइस बैंड) 382-402 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था। आईपीओ तीन कारोबारी दिनों में कुल 1.49 गुना सब्सक्राइब हुआ था। आईपीओ को 5.35 करोड़ शेयरों की पेशकश के मुकाबले 7.98 करोड़ शेयरों के लिए बोलियां मिलीं। कंपनी का यह इश्यू कुल 3,027.26 करोड़ रुपये का था। इसके लिए कंपनी के मौजूदा निवेशक ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) के जरिए 2,727.26 करोड़ रुपये के 6,78,42,284 शेयर बेचे। वहीं, कंपनी 300 करोड़ रुपय के 74,62,686 फ्रेश शेयर जारी किए। इस इश्यू के लिए खुदरा निवेशक अधिकतम 490 शेयर और एक लॉट में 35 शेयरों के लिए बिडिंग कर सकते थे।

आईपीओ का मतलब - जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयरों को आम लोगों के लिए जारी करती है, तो इसे आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) कहते हैं। कंपनी को कारोबार बढ़ाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। ऐसे में कंपनी बाजार से कर्ज लेने के बजाय कुछ शेयर पब्लिक को बेचकर या नए इश्यू जारी करके पैसा जुटाती है। इसी के लिए कंपनी आईपीओ लाती है।

उल्लेखनीय है कि डॉ. अग्रवाल्स हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी 2010 में स्थापित हुई थी। यह मोतियाबिंद, रिफ्रैक्टिव और अन्य सर्जरी जैसी आईकेयर सर्विसेज भी मुहैया कराती है। ये कंपनी चश्मे, कॉन्टैक्ट लेंस और आईकेयर से जुड़े फार्मा प्रोडक्ट्स भी बेचती है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत में कुल आईकेयर सर्विस चेन मार्केट में इसकी हिस्सेदारी लगभग 25 फीसदी थी।

न्यूज ब्रीफ

भारत ने संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट में 2025 के लिए दिए 3.764 करोड़ डॉलर

नई दिल्ली। भारत ने वर्ष 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट में 3.764 करोड़ यूएस डॉलर का भुगतान किया है। इसके साथ ही वह संयुक्त राष्ट्र को उसके नियमित बजट का पूरा और समय पर भुगतान करने वाले 35 सदस्य देशों की सूची में शामिल हो गया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने एक बयान जारी कर बताया कि भारत ने वर्ष 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट में 37.64 मिलियन (3.764 करोड़) यूएस डॉलर का 31 जनवरी, 2025 को भुगतान किया है। इससे वह उन 35 सदस्य देशों की सूची में शामिल हो गया है, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र को अपने नियमित बजट का पूरा और समय पर भुगतान किया है। स्टीफन दुजारिक ने सोमवार को प्रेस ब्रीफिंग में उन देशों के नाम बताते हुए कहा, ''हम भारत में अपने मित्रों को धन्यवाद देते हैं।'' भारत लगातार उन देशों में शामिल रहा है, जो संयुक्त राष्ट्र के बजट में अपना अंशदान समय पर और पूर्ण रूप से अदा करते हैं। संयुक्त राष्ट्र योगदान समिति के अनुसार, 31 जनवरी, 2025 तक 35 सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र वितीय विनियमों में निर्दिष्ट 30-दिवसीय नियत अवधि के भीतर अपने नियमित बजट मूल्यांकन का पूरा भुगतान कर दिया है। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष फिलेमोन यांग 4 से 8 फरवरी, 2025 तक भारत की यात्रा पर रहेंगे।

किसी भी खतरे के कारण कंपनी का कारोबार समेटने का नहीं कर रहे निर्णय: हिंडनबर्ग रिसर्च

नई दिल्ली। अमेरिकी अनुसंधान एवं निवेश कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च के संस्थापक नैट एंडरसन ने हाल ही में अपनी कंपनी के कारोबार पर किए गए आरोपों का सामना किया। इस घटना ने उद्योग दुनिया में छाई अर्थव्यवस्था के बीच एक नया सवाल उठाया है। एंडरसन ने ऐलान किया कि वे किसी भी कानूनी या अन्य खतरे के कारण कंपनी का कारोबार समेटने का निर्णय नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अदाणी समूह पर विभिन्न आरोप लगाने वाली रिपोर्ट के समर्थन में सभी निर्धारित संकेतों पर जानकारी ली। इस संकेतक में समूह पर अदाणी के खिलाफ कॉर्पोरेट इतिहास की सबसे बड़ी धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। इसके परिणामस्वरुप समूह की कंपनियों के बाजार मूल्यांकन में 150 अरब अमेरिकी डॉलर की गिरावट आई थी। हालांकि, अदाणी समूह ने इन आरोपों का खंडन किया था। एंडरसन ने ओसीसीआरपी और जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर कथित भारत विरोधी समूहों के खिलाफ किए जाने वाले प्रयासों को मूर्खतापूर्ण षड्यंत्र बताया। उन्होंने अपनी नीति में लम्बे समय से लगातार कहा है कि वे ऐसे षड्यंत्रवाद को प्रोत्साहन की भूमिका नहीं खेल रहे हैं।

शैक्षणिक और अनुसंधान संगठनों के साथ स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र पर केंद्रित हुआ पहला सम्मेलन

नई दिल्ली। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के महानिदेशक प्रमोद कुमार तिवारी ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र पर वार्षिक सम्मेलन के दौरान कहा कि नवाचार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले मानकों को आकार देने में शिक्षा उद्योग के सहयोग की जरूरत है। बीआईएस महानिदेशक नोएडा स्थित अपने राष्ट्रीय मानकीकरण प्रशिक्षण संस्थान में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में शैक्षणिक संस्थानों और अनुसंधान एवं विकास संगठनों के डीन और विभागाध्यक्षों के लिए वार्षिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि शैक्षणिक और अनुसंधान संगठनों के साथ आयोजित किए जा रहे सम्मेलनों की श्रृंखला में यह स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र पर केंद्रित पहला सम्मेलन था। सम्मेलन में 28 संस्थानों के लगभग 36 प्रतिभागी मौजूद थे, जिनका प्रतिनिधित्व डीन, विभागाध्यक्ष, संकाय सदस्य और अनुसंधान संगठनों के विशेषज्ञ कर रहे थे। भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग के तहत आयोजित इस सम्मेलन का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में मानकीकरण के बारे में जागरुकता पैदा करना और इस क्षेत्र में बीआईएस की मानकीकरण गतिविधि को मजबूत करने के लिए शिक्षाविदों और अनुसंधान संगठनों के साथ सहयोग के अवसरों का पता लगाना था। बीआईएस का उद्देश्य भारतीय मानकों की उपयोगिता को मजबूत करना है जो विशेष रूप से उद्योगों या उपभोक्ता समूहों तक सीमित नहीं हो सकते हैं।

टैरिफ वॉर टलने से स्टॉक मार्केट में उत्साह का माहौल सेंसेक्स और निफ्टी ने लगाई जोरदार छलांग

बाजार की तेजी से निवेशकों ने 1 दिन में कमाए 5.70 लाख करोड़

नई दिल्ली

सोमवार की गिरावट के बाद घरेलू शेयर बाजार शानदार तेजी का गवाह बना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मेक्सिको और कनाडा पर लगाए जाने वाले एक्स्ट्रा टैरिफ को अस्थाई रूप से टालने का ऐलान करने के कारण दुनिया भर के स्टॉक मार्केट में उत्साह का माहौल बना रहा। ग्लोबल सपोर्ट के कारण घरेलू शेयर बाजार ने भी जोरदार तेजी दिखाई। इंट्रा-डे में सेंसेक्स 1,471 अंक और निफ्टी 401 अंक तक उछल गए। पूरे दिन के कारोबार के बाद सेंसेक्स 1.81 प्रतिशत और निफ्टी 1.62 प्रतिशत की मजबूती के साथ बंद हुए।

दिनभर के कारोबार के दौरान एफएमसीजी को छोड़ कर सभी सेक्टोरल इंडेक्स बढ़त के साथ हरे निशान में बंद हुए। के कारोबार में एफएमसीजी इंडेक्स 0.13 प्रतिशत की गिरावट का शिकार हो गया। दूसरी ओर बैंकिंग, आईटी, कैपिटल गुड्स और मेटल सेक्टर के शेयरों में दिनभर जोरदार खरीदारी होती रही। इसी तरह ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर ड्यूरेबल, हेल्थ केयर, ऑयल ऐंड गैस, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज और टेक इंडेक्स भी मजबूती के साथ बंद हुए। ब्रॉडर मार्केट में भी लगातार खरीदारी होती रही, जिसके कारण बीएसई का मिडकैप इंडेक्स 1.35 प्रतिशत की मजबूती के साथ बंद हुआ। इसी तरह स्मॉल कैप इंडेक्स ने 1.20 प्रतिशत की बढ़त के साथ के कारोबार का अंत किया।

शेयर बाजार में आई मजबूती के कारण स्टॉक मार्केट के निवेशकों की संपत्ति में करीब पौने छह लाख करोड़ रुपये का इजाफा हो गया। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन के कारोबार के बाद बढ़ कर 425.24 लाख करोड़ रुपये (अस्थाई) हो गया। जबकि पिछले कारोबारी दिन यानी सोमवार को इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 419.54 लाख करोड़ रुपये था। इस तरह निवेशकों को के कारोबार से करीब 5.70 लाख करोड़ रुपये का मुनाफा हो गया। दिनभर के कारोबार में बीएसई में 4,073 शेयरों में एक्टिव ट्रेडिंग हुई।

इंडिगो एयरलाइंस में शुगर पेशेंट को समय पर नहीं मिला भोजन

नई दिल्ली। एम्स दिल्ली के एक डॉक्टर ने इंडिगो एयरलाइंस पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें भोजन की अवहेलना की गई और उनकी सेहत पर ध्यान नहीं दिया गया। केबिन क्रू ने बार-बार यह बताने पर भी समय पर खाना नहीं दिया कि वे शुगर पेशेंट है और उनके लिए भोजन बहुत जरूरी है। डॉ. दत्ता ने बताया कि उन्हे बिना विवरण दिए विमान से उतार दिया गया जबकि उनके लिए भोजन जरूरी था। उन्होंने इस मामले को लेकर राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम के पास भी जाने की योजना बनाई है। डॉक्टर दत्ता ने सोशल मीडिया पर अपने अनुभव को साझा करते हुए इंडिगो एयरलाइंस से यात्रा न करने की भी सलाह दी है। उन्होंने उदाहरण के रूप में बताया कि उन्हें उनकी सेहत और भोजन की अवहेलना की गई, जो एक गंभीर समस्या हो सकती है। डॉ. दत्ता ने इस घटना को अत्यंत दुखद बताते हुए कहा कि उन्हें सही समय पर भोजन नहीं मिला और उनकी सेहत पर ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने इस मामले को जांचने की मांग की है और इस पर कार्रवाई की जाए। डॉ. दत्ता ने बताया कि उन्हें बॉर्डरलाइन हाई शुगर की समस्या है, इसी कारण उन्होंने फ्लाइट के लिए पहले से सैंडविच बुक किया था ताकि समय पर खाना मिल सके, फ्लाइट दोपहर 3:30 बजे टेक-ऑफ हुई, लेकिन भोजन समय पर नहीं परोसा गया। जब क्रू उनके पास पहुंचा तो बताया गया कि बेंगलुरु मे किसी समस्या के कारण उनके भोजन में देरी हो सकती है। डॉ. दत्ता ने अपनी पोस्ट मे लिखा, करीब आधे घंटे इंतजार के बाद मैंने विनम्रता से पूछा कि क्या कोई समस्या है, एक क्रू मेंबर ने कहा कि कोई अन्य सहकर्मी भोजन परोसेगा, लेकिन इसके बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। मुझे नजरअंदाज किया जा रहा था।

सर्राफा बाजार में लगातार दूसरे दिन कमजोरी का रुख, सोना और चांदी की घटी कीमत

नई दिल्ली

सर्राफा बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट का रुख नजर आ रहा है। सोना 400 रुपये से लेकर 440 रुपये प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो गया है। कीमत में आई इस गिरावट के कारण देश के ज्यादातर सर्राफा बाजारों में 24 कैरेट सोना 84,040 रुपये से लेकर 84,190 रुपये प्रति 10 ग्राम के दायरे में कारोबार कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना भी 77,040 रुपये से लेकर 77,190 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। चांदी की कीमत में भी गिरावट आने की वजह से ये चमकीली धातु दिल्ली सर्राफा बाजार में 99,300 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है।

देश की राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोना 84,190 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 77,190 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 84,040 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 77,040 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 84,090 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 77,090 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। इन प्रमुख शहरों के अलावा चेन्नई में 24 कैरेट सोना 84,040 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर और 22 कैरेट सोना 77,040 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बिक रहा है। इसी तरह कोलकाता में भी 24 कैरेट सोना 84,040 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 77,040 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है।

लखनऊ के सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना 84,190 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर और 22 कैरेट सोना 77,190 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। वहीं, पटना में 24 कैरेट सोने की कीमत 84,090 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 77,090 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह जयपुर में 24 कैरेट सोना 84,190 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 77,190 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

देश के अन्य राज्यों की तरह कर्नाटक, तेलंगाना और ओडिशा के सर्राफा बाजार में भी सोना सस्ता हुआ है।

टीवीएस होल्डिंग्स ने होम क्रेडिट का अधिग्रहण पूरा किया

टीवीएस होल्डिंग्स लिमिटेड ने होम क्रेडिट इंडिया फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड की 80.74 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण पूरा कर लिया है और इससे समूह की प्रबंधनाधीन ऋण सम्पत्तियों का आधार 33,000 करोड़ रुपये है। यह सौदा 554 करोड़ रुपये में हुआ है। कंपनी की शेष 19.26 प्रतिशत हिस्सेदारी प्रेमजी इन्वेस्ट और टीवीएस होल्डिंग्स के अन्य सहयोगियों द्वारा खरीदी गई है। टीवीएस होल्डिंग्स ने समूह के ऋण पोर्टफोलियो को तीन साल में 50 हजार करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।

मालपानी पाइप्स की स्टॉक मार्केट में फीकी एंट्री, लिस्टिंग के बाद लोअर सर्किट तक पहुंचा शेयर

नई दिल्ली

हाई ग्रेड प्लास्टिक पाइप बनाने वाली कंपनी मालपानी पाइप्स एंड फिटिंग्स ने फीकी लिस्टिंग से अपने निवेशकों को निराश कर दिया। आईपीओ के तहत कंपनी के शेयर 90 रुपये के भाव पर जारी किए गए थे। बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर ये शेयर 4.56 प्रतिशत डिस्काउंट के साथ 85.90 रुपये के भाव पर लिस्ट हुआ। लिस्टिंग के तुरंत बाद बिकवाली का दबाव बन जाने के कारण ये शेयर 81.61 रुपये के लोअर सर्किट लेवल पर आ गया। हालांकि थोड़ी देर बाद खरीदारों ने लिवाली शुरू करके इस शेयर पर लगे लोअर सर्किट को ब्रेक कर दिया। दोपहर 11 तक के कारोबार के बाद मालपानी पाइप्स एंड फिटिंग्स के शेयर 85.70 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहे थे।

मालपानी पाइप्स एंड फिटिंग्स का 25.92 करोड़ रुपये का आईपीओ 29 से 31 जनवरी के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। इस आईपीओ को निवेशकों की ओर से जोरदार रिस्पॉन्स मिला था, जिसके कारण ये ओवरऑल 146.93 गुना सब्सक्राइब हो गया था। इनमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के लिए रिजर्व पोर्शन 58.49 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इसी तरह नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (एनआईआई) के लिए रिजर्व पोर्शन में 343.13 गुना सब्सक्रिप्शन आया था। इसके अलावा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व पोर्शन 113.35 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इस आईपीओ के तहत 10 रुपये फेस वैल्यू वाले 28.80 लाख नए शेयर जारी किए गए हैं। आईपीओ के जरिए जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल कंपनी नई मशीनरी खरीदने, पुराने कर्ज चुकाने और आम कॉर्पोरेट उद्देश्यों में करेगी।

कंपनी की वित्तीय स्थिति की बात करें तो प्रॉस्पेक्टस में किए गए दावे के मुताबिक इसकी वित्तीय सेहत लगातार मजबूत हुई है। वित्त वर्ष 2021-22 में कंपनी को 89 लाख रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था, जो अगले वित्त वर्ष 2022-23 में बढ़कर 2.08 करोड़ रुपये और 2023-24 में 7.40 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। इस दौरान कंपनी का राजस्व 101 प्रतिशत वार्षिक की चक्रवृद्धि दर से बढ़ कर 141.16 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया।

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना नौकरी नहीं, अनुभव के लिए : वित्त मंत्री

नई दिल्ली

केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि पिछले साल घोषित प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (पीएमआईएस) का उद्देश्य नौकरियां प्रदान करना नहीं था, बल्कि इसका उद्देश्य युवाओं को नौकरी के लिए तैयार करने और उन्हें कौशल प्रदान करना था। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप या एक्सपोजर प्राप्त करने की अनुमति देना चाहती है। इसके बाद वे नौकरी की तलाश में बेहतर स्थिति में होंगे।

वित्त मंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान राज्य सभा में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए सदन को बताया कि पिछले साल शुरू हुई प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के पायलट प्रोजेक्ट के तहत उद्योगों ने 1.27 लाख अवसर प्रदान किए हैं। फिर संभावित उम्मीदवारों से आवेदन करने के लिए कहा गया और उसके बाद उन्हें अपने राज्य के भीतर चयन करने का अवसर प्रदान किया गया। उन्होंने कहा कि दूसरा पायलट प्रोजेक्ट इस साल जनवरी से शुरू हुआ है। करीब 80 और कंपनियां ऑफर लेकर आई हैं। देश के सभी जिलों में इस कार्यक्रम के तहत 743 से अधिक जिलों में युवाओं को नौकरी दिलाने में सफलता मिली है।

सीतारमण ने सदन को बताया कि सरकार बहुत सारे जागरुकता अभियान चला रही है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत समय दे रही है कि ज्यादा से ज्यादा युवा इस बारे में जानें। हम उन उम्मीदवारों से भी बात कर रहे हैं, जिन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया है और उन्हें अपने अनुभव के बारे में बता रहे हैं। उन्होंने सभी सांसदों से अनुरोध किया कि वे अपने-अपने राज्यों और निर्वाचन क्षेत्रों में उन युवाओं से सक्रिय रूप से जुड़ें, जो प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना से लाभ उठाना चाहते हैं।

वित्त मंत्री ने सदन को बताया कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का उद्देश्य नौकरी प्रदान करना नहीं है, बल्कि युवाओं को बाजार में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी प्रदान करना और उन्हें प्रशिक्षित करना है। इसलिए यह हमारी सरकार की नौकरी प्रदान करने और साथ ही उन लोगों को नौकरी के लिए तैयार करने की कोशिश का हिस्सा था, जो अभी भी तैयार नहीं हैं। हम महिलाओं को अपने जिले में और अगर उनके जिले में संभव न हो तो अपने राज्य में ही इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित कर रहे हैं, ताकि उन्हें बहुत दूर न जाना पड़े और महिलाओं ने इसे बहुत मददगार पाया है।

हरियाणा के खिलाफ रणजी क्वार्टर फाइनल के लिए सूर्यकुमार, शिवम दुबे मुंबई टीम में हुए शामिल

मुंबई

सूर्यकुमार यादव को हरियाणा के खिलाफ 8 फरवरी से होने वाले रणजी ट्रॉफी क्वार्टरफाइनल मैच के लिए मुंबई की टीम में शामिल किया गया है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने अपनी वेबसाइट पर उक्त जानकारी दी।

यह मैच बंसी लाल क्रिकेट स्टेडियम, लाहली में खेला जाएगा। अजिंक्य रहाणे टीम की अगुआई करेंगे। श्रेयस अय्यर, रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल 6 फरवरी से इंग्लैंड के खिलाफ भारत की तीन मैचों की वनडे सीरीज में शामिल होने के कारण इस मैच में नहीं खेल पाएंगे। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की वेबसाइट पर बताया गया है कि यह मैच सूर्यकुमार को अपनी फॉर्म हासिल करने के लिए कुछ समय देगा। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ पांच पारियों में 28 रन बनाए हैं और भारत और राज्य के लिए सभी प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में अपनी पिछली 10 पारियों में सिर्फ 66 रन बनाए हैं। गेंदबाजी ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर, जो फिलहाल भारत की योजना में नहीं हैं, 19 फरवरी से शुरू होने वाली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भी मुंबई के लिए अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखना चाहेंगे। ऑलराउंडर शिवम दुबे, जिन्होंने टी20 में इंग्लैंड के खिलाफ दो मैचों में शानदार प्रदर्शन किया था, जिसमें एक अर्धशतक और दो विकेट सहित 83 रन बनाए थे, को भी टीम में शामिल किया गया है। शार्दुल मेघालय के खिलाफ दोनों पारियों में चार विकेट और पहली पारी में 84 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार हासिल किया था। अब तक सात मैचों में उन्होंने 23.95 की औसत से 24 विकेट लिए हैं, जिसमें 4/43 का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। बल्ले से आठ पारियों में ठाकुर ने 47.62 की औसत से 381 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और तीन अर्द्धशतक के साथ 101.87 की अविश्वसनीय स्ट्राइक रेट है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 119 है। होनहार युवा आयुष म्हात्रे और सूर्यांश शेड्गे भी टीम में हैं। मुंबई ने ग्रुप ए में चार जीत, दो हार और एक ड्रॉ के साथ लीग चरण का समापन दूसरे स्थान पर किया, जिससे उन्हें 29 अंक मिले। उनकी एक चौंकाने वाली हार जम्मू और कश्मीर के खिलाफ आई, जिसने रोहित, जायसवाल, रहाणे, अय्यर, दुबे और ठाकुर से सजी पूरी ताकत वाली मुंबई को पांच विकेट से हराया। मुंबई का लक्ष्य टूर्नामेंट में आगे बढ़ना और अपना रिकॉर्ड 43वां खिताब हासिल करना होगा।

न्यूज ब्रीफ

राष्ट्रीय खेल फुटबॉलः मिजोरम, उत्तराखंड, मणिपुर और सर्विसेज ने पहले दिन दर्ज की शानदार जीत

देहरादून। 38वें राष्ट्रीय खेलों में फुटबॉल के लीग मुकाबले बेहद रोमांचक रहे हैं। सोमवार को पूल ए में मिजोरम ने असम को 3-0 से हराकर दमदार शुरुआत की, जबकि उत्तराखंड ने गोवा के खिलाफ 4-1 की शानदार जीत दर्ज की। पूल बी में भी मुकाबले कड़े रहे, जहां मणिपुर ने दिल्ली को 2-0 से शिकस्त दी। वहीं, सर्विसेज ने केरल को 3-0 से मात देकर अपनी स्थिति मजबूत कर ली। इन मुकाबलों में खिलाड़ियों ने असाधारण कौशल का प्रदर्शन किया, जिससे आगामी मैचों के प्रति उत्साह और बढ़ गया है। लीग मैचों ने यह साबित कर दिया कि सभी टीमें पूरे दृढ़ संकल्प के साथ मैदान में उतरी हैं, जिससे आगे और भी कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी।

आरसीबी ने कप्तानी को लेकर अभी कोई फैसला नहीं किया : मेनन

नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2025 सत्र में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी की कप्तानी कौन करेगा। इसको लेकर अटकलें लगायी जा रही हैं। इसका कारण है कि पिछले तीन सत्र से कप्तान रहे फाफ डु प्लेसिस को इस बार आरसीबी ने रिटेन नहीं किया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि विराट कोहली को एक बार फिर टीम की कप्तानी मिल सकती है। इसी को लेकर आरसीबी के सीओओ राजेश मेनन ने कहा है कि अभी तक इस बारे में कुछ तय नहीं किया गया है। साथ ही कहा कि हमारी टीम में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो कप्तानी की योग्य हैं। उनसे बात कर हम इस बारे में कोई अंतिम फैसला करेंगे। गौरतलब है कि कोहली ने 2011 से 2023 तक 143 आईपीएल मैचों में आरसीबी की कप्तानी की थी पर वह टीम खिताब नहीं दिला पाये थे। उन्होंने टीम को 66 मैच में जीत दिलाई जबकि 70 बार हार का सामना करना पड़ा। साल 2016 में टीम आईपीएल फाइनल में पहुंची थी। उस सत्र में विराट ने 973 रन बनाए थे पर टीम खिताबी मुकाबले में हार गयी थी। आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में आरसीबी ने फिल सॉल्ट, लियाम लिविंगस्टोन, जैकब बेथेल, टिम डेविड, भुवनेश्वर कुमार, जितेश शर्मा, देवदत्त पडिक्कल, जोश हेजलवुड, रोमारियो शेफर्ड, नुवान थुशारा, और सुयश शर्मा को शामिल किया है। मेनन ने साथ ही कहा, हमने देखा कि टीम में क्या कमी है और उसे क्या चाहिये। इसके साथ ही हमें किस प्रकार के बल्लेबाजों और गेंदबाजों की जरूरत है।

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट पुरस्कार घोषित, हेड को बॉर्डर व सदरलैंड को मिला बेलिंडा क्लार्क अवार्ड

मेलबर्न। पिछले कुछ समय से लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे बल्लेबाज ट्रैविस हेड को ऑस्ट्रेलियाई पुरुष क्रिकेटर के लिए प्रतिष्ठित एलन बॉर्डर अवार्ड दिया गया है। वहीं महिला वर्ग में युवा ऑलराउंडर एनाबेल सदरलैंड को बेलिंडा क्लार्क अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हेड का मुकाबला अवॉर्ड की दौड़ में तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड और पैट कमिंस से था। जिसमें सबसे अधिक वोट हेड को मिले हैं। हेड ने सम्मान मिलने पर खुशी जतायी है। साथ ही कहा कि यह मेरे लिए एक अच्छा साल रहा है। मैं बहुत खुश हूं कि अपनी टीम की ओर से जीत में अहम भूमिका निभाने में सफल रहा हूं। मैं सभी प्रारूपों में खेलने में सक्षम हूं। यह एक अच्छी उपलब्धि है, और मैं इसका लाभ उठाऊंगा। हेड को पुरुष वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी मिला है। इसके अलावा वह टवेंटी 20 और टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कारों में दूसरे स्थान पर रहे। हेड ने 11 एकदिवसीय में 5 मैच खेलकर भी अवार्ड जीता जो एक बड़ी बात है। ट्रेंट ब्रिज में इंग्लैंड के खिलाफ नाबाद 154 रनों की शानदार पारी के कारण उन्हें ये अवार्ड मिला। प्लेयर ऑफ द ईयर की दौड़ में उन्होंने एलेक्स कैरी, स्टीव स्मिथ और जेवियर बार्टलेट जैसे खिलाड़ियों को पीछे छोड़ा। वहीं सदरलैंड को पहली बार ये अवार्ड मिला है। इस ऑलराउंडर ने पिछले एक साल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 210 रन बनाए थे। सदरलैंड ने पुरस्कार की दौड़ में एशले गार्डनर और बेथ मूनी को पीछे छोड़ते हुए बेलिंडा क्लार्क मेडल जीता।

राष्ट्रीय खेल : उत्तराखंड के नीरज जोशी ने वूशु में जीता रजत पदक

हल्द्वानी के खिलाड़ी ने संघर्षों को दी मात, प्रदेश का नाम किया रोशन

देहरादून

उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में शानदार प्रदर्शन कर प्रदेश का मान बढ़ाया है। विशेष रूप से वूशु प्रतियोगिता में हल्द्वानी के नीरज जोशी ने रजत पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। नीरज का सफर संघर्षों से भरा रहा, लेकिन अपनी मेहनत और उत्तराखंड सरकार की खेल नीतियों से प्रेरित होकर उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की।

संघर्षों से भरा रहा सफर

हल्द्वानी निवासी नीरज जोशी के पिता राजेश बल्लभ जोशी एक किसान हैं और सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने अपने बेटे को खेल के प्रति प्रेरित किया। पिछले आठ वर्षों से देहरादून में रहकर प्रशिक्षण ले रहे नीरज को आर्थिक तंगी और चोटों का सामना करना पड़ा।

वर्ष 2022 में पैर की हड्डी टूटने के कारण उन्हें खेल से दूरी बनानी पड़ी थी। इस दौरान उन्होंने खेल छोड़ने तक का विचार किया, लेकिन परिवार और कोच के सहयोग से उन्होंने फिर से वापसी की। वर्ष 2023 में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर अपनी फिटनेस और खेल कौशल को साबित किया। हालांकि, गोवा में हुए राष्ट्रीय खेल 2023 में खेल सुविधाओं के अभाव में वह केवल पांचवें स्थान पर रहे।

सरकार की योजनाओं से मिली प्रेरणा

नीरज जोशी ने अपनी सफलता का श्रेय उत्तराखंड सरकार की खेल नीति को दिया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेताओं को नकद पुरस्कार और सरकारी नौकरी देने की राज्य सरकार की घोषणा से खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ा है। इन प्रोत्साहनों ने उन्हें बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया और इस बार उन्होंने वूशु स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया। उत्तराखंड के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के कई खिलाड़ियों ने पदक जीतकर प्रदेश को गौरवान्वित किया।

राष्ट्रीय खेलः कर्नाटक 42 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर

देहरादून। कर्नाटक 42 पदकों के साथ 38वें राष्ट्रीय खेलों के पदक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गया है। कर्नाटक ने अब तक 22 स्वर्ण, 10 रजत और 10 कांस्य पदक जीते हैं। सर्विसेज 38 (19 स्वर्ण, 10 रजत और 9 कांस्य) पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है। महाराष्ट्र ने अब तक सबसे अधिक 61 पदक अर्जित किए हैं, जिनमें 15 स्वर्ण, 26 रजत और 20 कांस्य पदक शामिल हैं, जिससे वह कुल पदकों की संख्या के आधार पर सबसे आगे है, लेकिन स्वर्ण पदकों की संख्या कम होने के कारण तीसरे स्थान पर है। मणिपुर ने 11 स्वर्ण, 10 रजत और 5 कांस्य पदकों के साथ चौथा स्थान प्राप्त किया है, जबकि मध्य प्रदेश 10 स्वर्ण, 5 रजत और 5 कांस्य पदकों के साथ पांचवें स्थान पर है। हरियाणा, तमिलनाडु और दिल्ली ने भी प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। हरियाणा ने 6 स्वर्ण, 9 रजत और 18 कांस्य पदक जीतकर कुल 33 पदक हासिल किए हैं, जबकि तमिलनाडु 9 स्वर्ण, 12 रजत और 13 कांस्य पदकों के साथ 34 पदकों पर पहुंच चुका है।

राष्ट्रीय खेल के लिए एथलेटिक्स टीम के कप्तान बने शिवपाल

लखनऊ। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल के लिए चयनित उत्तर प्रदेश एथलेटिक्स टीम में पुरुष वर्ग में शिवपाल सिंह और महिला वर्ग में पारुल चौधरी कप्तान बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश एथलेटिक्स एसोसिएशन के सचिव नरेंद्र कुमार ने उत्तर प्रदेश टीम की घोषणा करते हुए बताया कि टीम कोच बाबा दीन चौधरी, बीआर वरुण, रमेश यादव व गौरव त्यागी होंगे। मैनेजर शिवा नंद नायक, संदीप कुमार सिंह व विनीता बाजपेयी को बनाया गया है। राष्ट्रीय खेल में एथलेटिक्स की स्पर्धा आठ से 12 फरवरी तक देहरादून में आयोजित होंगी। पुरुष टीम : शिवपाल सिंह (कप्तान), सचिन यादव, रोहित यादव (जैवलिन थ्रो), प्रिंस कुमार, अहसन (1500 मीटर), आर्यन त्यागी (शॉटपुट), अवनीश, कुलदीप कुमार (पोल वॉल्ट), मो. शाहबान, मो. नदीम, मुकुल (हैमर थ्रो), शहनवाज खान, आदित्य कुमार सिंह (लंबी कूद), ऋत्विक चौधरी (400 मीटर), ऋत्विक चौधरी, अनिकेत पंवार (4 गुणे 400 मिक्सड रिले), कमल सिंह (डेकाथलान), लक्ष्य (200 मीटर), सूरज पाल, शाहरुख खान (3000 मीटर स्टीपल चेज), दिव्यांशु कुमार (10,000 मीटर), राम बाबू, धनंजय यादव (पैदल चाल। महिला : पारुल चौधरी (कप्तान), रेबी पाल, बबली वर्मा (3000 मीटर स्टीपल चेज), ख्याति माथुर, मानसी (ऊंची कूद), दीपांशी सिंह (लंबी कूद), सलोनी (जैवलिन थ्रो), सुनीता देवी (5000 मीटर), नीतिका वर्मा (डिस्कस थ्रो), नेहा पंवार, विनीता गुर्जर (1500 मीटर), राखी (800 मीटर), प्राची, रूपल (400 मीटर), तान्या चौधरी, नंदिनी, अनुष्का यादव (हैमर थ्रो), मुनीता प्रजापति, रेशमा पटेल, प्रियंका गोस्वामी (पैदल चाल), कविता यादव, अमृता पटेल (10000 मीटर), सोनम (ट्रिपल जंप), रूपल, प्राची (4 गुणा 400 मिक्सड रिले), साक्षी शर्मा (जैवलिन थ्रो), विधि (शॉटपुट)।

राष्ट्रीय खेलः मध्य प्रदेश और तेलंगाना ने बास्केटबॉल 3×3 में किया कमाल

देहरादून

38वें राष्ट्रीय खेलों के तहत आयोजित बास्केटबॉल 3×3 टूर्नामेंट का शानदार समापन हुआ, जिसमें पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। फाइनल मुकाबलों में मध्य प्रदेश ने पुरुष वर्ग में केरल को 22-20 से हराकर खिताब अपने नाम किया, जबकि महिला वर्ग में तेलंगाना ने केरल को 21-11 के बड़े अंतर से पराजित कर विजेता बनने का गौरव हासिल किया।

सेमीफाइनल मुकाबले रहे रोमांचक

पुरुषों के सेमीफाइनल में केरल ने तमिलनाडु को कड़े संघर्ष में 16-15 से हराया, जबकि मध्य प्रदेश ने तेलंगाना को 18-14 से मात देकर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं, महिला वर्ग में तेलंगाना ने तमिलनाडु को 18-11 से पराजित किया, जबकि केरल ने मध्य प्रदेश को 13-10 से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई।

खिलाड़ियों ने दिखाया शानदार कौशल

इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के दौरान खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन कर अपने खेल कौशल और समर्पण को साबित किया। 38वें राष्ट्रीय खेलों ने पूरे देश से आए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को मंच प्रदान किया, जहां उन्होंने उत्कृष्ट खेल भावना और जुनून का परिचय दिया।

प्रीमियर लीग फुटबॉल

लंदन में प्रीमियर लीग फुटबॉल में खेलते हुए चेलेसा के इनजो फर्नांडिज और वेस्ट हेम के कार्लोस सोलर ।

राष्ट्रीय खेल 2025 : अंडमान-निकोबार ने रोड साइक्लिंग में तीन और एसएससीबी ने दो पदक जीते

देहरादून

राष्ट्रीय खेल 2025 के रोड साइक्लिंग फ़ाइनल के पहले दिन अंडमान और निकोबार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक स्वर्ण, एक रजत और एक कांस्य सहित तीन पदक अपने नाम किए। वहीं, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड (एसएससीबी) ने भी दमदार प्रदर्शन किया और एक स्वर्ण व एक रजत पदक जीते।

महिला एलीट स्क्रैच 10 किमी रेस

महिला एलीट स्क्रैच 10 किमी दौड़ में कर्नाटक की कीर्ति रंगास्वामी सी ने स्वर्ण पदक जीता। असम की चयनिका गोगोई को रजत और हरियाणा की मीनाक्षी को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा।

पुरुष एलीट स्क्रैच 15 किमी रेस

पुरुषों की एलीट स्क्रैच रेस 15 किमी में एसएससीबी के साहिल कुमार ने स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। केरल के अद्वैत शंकर एसएस ने रजत और एसएससीबी के कृष्णा नायकोडी ने कांस्य पदक जीता।

महिला एलीट स्प्रिंट स्पर्धा

महिला एलीट स्प्रिंट में महाराष्ट्र की श्वेता बालू गुंजल ने 12.745 सेकेंड के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता। अंडमान और निकोबार की सेलेस्टिना ने 12.848 सेकंड में दौड़ पूरी कर रजत पदक अपने नाम किया, जबकि दिल्ली की त्रियशा पॉल ने 12.799 सेकेंड में स्प्रिंट पूरी कर कांस्य पदक जीता। महाराष्ट्र की अगाशे शुशिकला दुर्गाप्रसाद 12.567 सेकेंड के समय के साथ चौथे स्थान पर रहीं और कुछ मिली सेकेंड के अंतर से पदक चूक गईं।

पुरुष एलीट स्प्रिंट स्पर्धा

पुरुष एलीट स्प्रिंट स्पर्धा में अंडमान और निकोबार के डेविड बेकहम ने 10.691 सेकेंड में दौड़ पूरी कर स्वर्ण पदक जीता। मणिपुर के लैटोनजाम रोनाल्डो सिंह ने 10.724 सेकेंड के समय के साथ रजत पदक अपने नाम किया, जबकि अंडमान और निकोबार के एसो ने 10.826 सेकेंड में दौड़ पूरी कर कांस्य पदक जीता।

रोड साइक्लिंग के पहले दिन कुल 12 पदक अलग-अलग राज्यों और बोर्ड्स के खिलाड़ियों ने जीते, जिसमें अंडमान और निकोबार के शानदार प्रदर्शन ने सबका ध्यान खींचा।

अटारी-वाघा सीमा से हीरो एचआईएल के शीर्ष स्कोरर बनने तकः प्रेरणादायक रही है जुगराज सिंह की कहानी

नई दिल्ली

भारतीय पुरुष हॉकी टीम के डिफेंडर जुगराज सिंह की कहानी संघर्ष, मेहनत और सफलता का प्रतीक है। कभी अटारी-वाघा सीमा पर झंडे और पानी की बोतलें बेचने वाले जुगराज ने हाल ही में समाप्त हुई पुरुष हीरो हॉकी इंडिया लीग (एचआईएल) 2024-25 में श्राची रार बंगाल टाइगर्स के लिए खेलते हुए टूर्नामेंट के शीर्ष स्कोरर का खिताब जीता। उन्होंने 12 गोल किए, जिसमें फाइनल में हैदराबाद तूफान्स के खिलाफ हैट्रिक भी शामिल थी, और अपनी टीम को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई।

संघर्ष से सफलता तक का सफर

पंजाब के अटारी में जन्मे 28 वर्षीय जुगराज का सफर आसान नहीं रहा। जब उनके पिता, जो भारतीय सेना में कुली थे, बीमार पड़ गए, तब परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। ऐसे में जुगराज ने परिवार का सहारा बनने के लिए झंडे

और पानी की बोतलें बेचनी शुरू कर दीं।

उन्होंने कहा, मैंने कभी सवाल नहीं किया कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। मेरे लिए परिवार पहली प्राथमिकता थी। कड़ी मेहनत ही एकमात्र रास्ता था, और मुझे भरोसा था कि यह मेरे भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगी। हालांकि परिस्थितियां कठिन थीं, लेकिन जुगराज का हॉकी के प्रति जुनून कभी कम नहीं हुआ। सात साल की उम्र में उन्होंने हॉकी खेलना शुरू किया। उनके बड़े भाई, जिन्होंने पिता की नौकरी संभालने के लिए हॉकी छोड़ दी थी, ने उन्हें हमेशा प्रेरित किया।

हीरो एचआईएल में शानदार प्रदर्शन

हीरो एचआईएल के अपने पहले ही सीजन में जुगराज ने शानदार खेल दिखाया। फाइनल में हैट्रिक लगाकर उन्होंने अपनी टीम को जीत दिलाई और टूर्नामेंट के शीर्ष स्कोरर बने। उन्होंने कहा, फाइनल में हैट्रिक बनाना हर खिलाड़ी का सपना होता है। मैंने इसकी योजना नहीं बनाई थी, लेकिन जब दो गोल किए, तो तीसरे के लिए गया। यह मेरे लिए बहुत बड़ा व्यक्तिगत मील का पत्थर है। श्राची रार बंगाल टाइगर्स के कप्तान रूपिंदर पाल सिंह के मार्गदर्शन ने भी जुगराज के प्रदर्शन को निखारने में अहम भूमिका निभाई। जुगराज ने कहा, रूपिंदर ने मुझ पर भरोसा दिखाया और पूरे टूर्नामेंट में मेरा मार्गदर्शन किया। उनकी मदद से मैं अपनी क्षमता दिखा सका।

भविष्य की योजनाएं

अब जुगराज की नजरें भुवनेश्वर में होने वाली एफआईएच प्रो लीग पर टिकी हैं, जहां वह अपने शानदार फॉर्म को जारी रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा, एचआईएल ने मेरा आत्मविश्वास बढ़ाया है। अब मैं एफआईएच प्रो लीग में अच्छा प्रदर्शन कर भारतीय टीम के लिए योगदान देना चाहता हूं। इसके अलावा, उनका लक्ष्य विश्व कप, एशियाई खेलों और ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतना है। उन्होंने कहा, मैं भारत के लिए बड़े मंचों पर प्रदर्शन करना चाहता हूं। मेरा सपना है कि मैं अपने देश को ओलंपिक और विश्व कप में गोल्ड मेडल दिलाऊं। कड़ी मेहनत और देश के प्रति समर्पण अटारी-वाघा सीमा से भारतीय हॉकी के शीर्ष खिलाड़ियों में शामिल होने तक, जुगराज की कहानी संघर्ष और दृढ़ संकल्प का उदाहरण है।

पढ़ने के बावजूद याद नहीं रहता

...तो अपनाएं मेमोरी बढ़ाने के 7 टिप्स

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सब कुछ इतना तेज है कि कई बार आपको ढेर सारी चीजें याद रखना मुश्किल हो जाता है। कई बार आप लोगों के नाम भूल जाते हैं, चीजों को कहीं रख देते हैं लेकिन बाद में याद नहीं आती। पढ़ाई मन लगाकर करते हैं लेकिन बाद में पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। ऐसी कई समस्याएं आज आम हो गई है। आज छात्रों को कई सारी प्रतियोगी परीक्षाएं भी देनी होती है, लेकिन अगर ऐसे में मेमोरी साथ नहीं देगी तो कहीं न कहीं आप पिछड़ जाएंगे।

- नींद हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर आप अ?छी नींद नहीं लेंगे तो आपकी मेमोरी पर इसका असर पड़ेगा। इसलिए माइंड को शार्प रखने के लिए पर्या?त नींद लें।
- जिस तरह हमें शारीरिक रूप से चुस्?त-दुरुस्?त रहने के लिए ?यायाम की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह दिमाग को सक्रिय रखने के लिए दिमागी तौर पर ?यायाम करने की भी आवश्?यता है। क्रॉसवर्ड, पजल्?स, वीडियो गेम जैसी एक्टिविटी मेमोरी को शार्प करती है। साथ ही एकाग्रता भी बढ़ाती है।
- माइंड एक्?सरसाइज के अलावा आपको दिमाग को शांत करने के? लिए मेडि?टेशन का भी सहारा लेना होता है। इससे भी मेमोरी बढ़ती है।
- आपके खानपान का असर आपकी मेमोरी पर सीधे पड़ता है। इसलिए हेल्?दी फूड खाएं। हरी सब्जियां, बादाम अखरोट आदि मेमोरी पॉवर बढ़ाने में मदद करते हैं।
- अगर आपके साथ भी यही समस्?या है कि आप नाम और नंबर्स जल्?दी भूल जाते हैं, याद नहीं रख पाते तो आपको याद करने के तरीके बदलने होंगे। आपको इसके लिए किसी तरह के विजुअल या स्?टोरी जोड़ने से आसानी से याद हो जाते हैं।
- नयापन बहुत जरूरी है। इसलिए हमेशा ऐसी चीजें करें जो नई हो और आपने पहले कभी नहीं की हो। कुछ नया सीखते रहने से दिमाग सक्रिय रहता है और मेमोरी भी अ?छी बनी रहती है।
- अगर आप ऑर्गनाइज्?ड रहेंगे तो मेमोरी लॉस की समस्?या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप अपनी चीजें ?यवस्थित रखेंगे तो उन्?हें भूलने की संभावना कम होगी।

हास्पिटेलिटी में करियर के काफी मौके

समय के साथ-साथ लोगों के लक्ष्य भी बदल रहे हैं। व्यवसाय से संबद्ध सरोकार बदल रहे हैं। कुछ दशक पहले यह परंपरा थी कि अभिभावक अपने बच्चों को डाक्टर, इंजीनियर या वकील ही बनाना चाहते थे। आज अभिभावकों की सोच बदल चुकी है। वे डाक्टर, इंजीनियर और वकील के विकल्प को छोड़ अपने बच्चों के लिए बेहतर अवसरों के अंबार चाहते हैं। उनकी आकांक्षाओं की उड़ान को पंख लगाने में होटल व्यवसाय अहम भूमिका निभा सकता है। पिछले कुछ दशकों से टूरिज्म और ट्रैवल इंडस्ट्रीज में जबरदस्त ग्रोथ आया है। यही कारण है कि होटल, रेस्टोरेंट और एयरलाइंस में लोगों की मांग काफी बढ़ी है। भारत में इसका विस्तार काफी है और विदेशी धन का सबसे बड़ा स्रोत भी यही है। गौरतलब है कि भारत में सबसे अधिक अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं। होटल मैनेजमेंट की डिग्री हास्पिटेलिटी में करियर बनाने का पहला कदम है। इस करियर क्षेत्र में आप कभी भी खाली बैठे नहीं रह सकते हैं क्योंकि होटल हर शहर में है जहां आप विभिन्न तरह की नौकरी पा सकते हैं। साथ ही, यहां आप जिस भी उम्र वर्ग में हों, आपको काम मिल सकता है। होटल मैनेजमेंट के तहत आपको दो चीजें सीखनी होती हैं, पहला रूम डिवीजन जिसमें फ्रंट सर्विस और हाउसकीपिंग है। दूसरा, फूड एंड बीवरेज है जिसमें उनके प्रोडक्शन और सर्विस व किचन से संबंधित ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा होटल अकाउंटिंग, न्यूट्रीशन और फॉरेन लैंग्वेज की भी जानकारी दी जाती है। साथ ही संस्कृति, सामाजिक जिंदगी, एथनिक प्रोडक्ट्स, टूरिज्म, स्थानीय रीति-रिवाज भी सिखाए जाते हैं।

दुनियाभर में मौके

इस फील्ड मे करियर के काफी मौके है, जिसके तहत सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के बाहर भी अवसर हैं। होटल चेन वैश्विक स्तर पर कार्य करती है। यह काफी ग्लैमरस प्रोफेशन है। होटल इंडस्ट्री के ग्रोथ का मुख्य कारण विदेशी-देशी टूरिज्म और बिजनेस ट्रेवल का बढ़ना है। हास्पिटेलिटी इंडस्ट्री में वे लोग काफी आगे जा सकते है, जिनकी रुचि अतिथियों की सेवा करने में होती है। अब होटल मैनेजरों की नियुक्ति बैंक, एयरलाइंस, कॉल सेंटर, मल्टीप्लेक्स शॉपिंग माल्स, क्रूजशिप आदि मे होने लगी है। नए ग्रेजुएट के साथ-साथ होटल या रेस्टोरेंट में कार्य करने वाले प्रशिक्षित लोगो की मांग भी काफी है। मार्केटिंग,सेल्स एक्जीक्यूटिव, एफएमसीजी, स्पोर्ट्स कंपनी, मीडिया हाउस, पीआरओ एजेंसी, एडवर्टाइजिंग आउटलेट्स और इवेंट मैनेजमेंट आदि में भी काम मिलता है।

विकल्पों की भरमार

रेस्टोरेंट मैनेजमेंट, फास्ट फूड ज्वाइंट मैनेजमेंट, क्लब मैनेजमेंट, क्रिएशन एंड हैल्थ सेंटर मैनेजमेंट, क्रूजशिप मैनेजमेंट, इंस्टीच्यूशनल एंड इंडस्ट्रियल कैटरिंग, एयरलाइन कैटरिंग एंड कैबिन सर्विस होटल एंड कैटरिंग इंस्टीच्यूट, होटल एंड टूरिज्म एसोसिएशन कैटरिंग डिपार्टमेंट, बैंक और इंश्योरेंस हाउसेज, सरकारी कैटरिंग डिपार्टमेंट मसलन रेलवे, आर्म्ड फोर्सेज, मिनिस्ट्रियल कन्वेंशन आदि फूड कन्फेक्शनरी, बीवरेज प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज आदि में नौकरी की काफी संभावनाएं हैं।

शैक्षणिक योग्यता

अभ्यर्थी ने अंग्रेजी विषय के साथ बारहवीं की हो, तो निश्चित तौर पर वह इसके बाद तीन वर्षीय होटल मैनेजमेंट की डिग्री हासिल कर सकता है। यदि अभ्यर्थी किसी विषय से ग्रेजुएशन किया है तो वह होटल मैनेजमेंट में दो वर्षीय ग्रेजुएट डिग्री कर सकता है। सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट प्राप्त कर चुके छात्र तीन महीने से लेकर एक साल की अवधि वाले सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। बारहवीं कर चुके छात्रों के लिए डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के कोर्स हैं। आपकी तरक्की शैक्षणिक योग्यता पर ही निर्भर करती है। होटल इंडस्ट्री का दायरा इतना बड़ा है कि इसमे कम पढ़े- लिखे से लेकर ज्यादा से ज्यादा पढ़े- लिखे के लिए भी आसानी से रोजगार प्राप्त किया जा सकता है। इसे रोजगार का खुला आकाश कह सकते हैं।

होटल व्यवसाय में चुनौतियां

होटल मैनेजमेंट बेशक बहुत ही अच्छे व्यवसाय का रूप है, लेकिन यह बिजनेस भी कई चुनौतियों से भरा हुआ है। आपको अगर मार्केट में जगह बनानी है, तो यह आपके लिए चुनौती है कि आप किस तरह से होटल इंडस्ट्री में अपना मुकाम बनाकर उसे कायम रख सकते हैं। होटल इंडस्ट्री में सबसे बड़ी चुनौती यह भी है कि लोगों को काफी शिफ्ट में काम करना पड़ता है। इस के लिए काफी स्टाफ की जरूरत होती है। कई बार जब अच्छे ग्रेजुएट लोग नहीं मिल पाते हैं, तो कंपनी डिप्लोमा किए हुए लोगों की नियुक्ति कर लेती है। इसलिए अगर आप ने डिप्लोमा किया है तो भी आप इस इंडस्ट्री का हिस्सा बन सकते हैं।

कितनी होती है सैलरी

इस क्षेत्र में वेतनमान इस बात पर निर्भर करता है कि आप सरकारी क्षेत्र में हैं या प्राइवेट सेक्टर में। इसके अलावा वेतन आप के पद और वरीयता के आधार पर निर्धारित होता है। कई कंपनियां होटल प्रोफेशन से संबद्ध अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को अच्छा वेतन देती हैं। फिर भी शुरुआती दौर में 15-25 हजार रुपए प्रति माह आसानी से मिल जाते हैं।

हालातों से सामंजस्य बैठाएं...

भावनाओं की अभिव्यक्ति

यह आफिस है- आपका घर नहीं, यह छोटा-सा जुमला हमें अकसर सुनने को मिलता है। निजी जीवन में जहां आप भावनाओं को सबसे अधिक महत्व देते हैं, आपके पेशेवर व्यक्तित्व में भावुकता का कोई स्थान नहीं होता। इस बात के लिए एक नहीं कई संदर्भ हो सकते हैं। आज समय की मांग ऐसी है कि हर इनसान कार्यस्थल पर खुद को अच्छा प्रोफेशनल साबित करना चाहता है और इसके लिए वह जी-जान से मेहनत भी करता है, लेकिन इसके लिए केवल मेहनत ही काफी नहीं है, बल्कि करियर में सफल होने के लिए अपनी भावनाओं को सही ढंग से अभिव्यक्ति और उन पर नियंत्रण भी बहुत जरूरी है। आजकल ज्यादातर कंपनियां अपने कर्मचारियों को इंप्रेशन मैनेजमेंट की ट्रेनिंग देती हैं। इसमें यह सिखाया जाता है कि इंसान व्यक्तिगत रूप से चाहे कितना ही तनावग्रस्त क्यों न हो, लेकिन आफिस में लोगों से बातचीत करते समय उसके चेहरे और बॉडी लैंग्वेज में तनाव बिल्कुल दिखाई नहीं देना चाहिए, क्योंकि सहकर्मियों पर इसका बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

कमजोरियों को पहचानें

आफिस में कामकाज का स्वस्थ माहौल बनाए रखने के लिए अगर आप कुछ बातों का ख्याल रखें तो यह आपके करियर के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। सबसे पहले अपने व्यक्तित्व की कमजोरियों को पहचान कर उन्हें डायरी में नोट करें। साथ ही उन स्थितियों को भी हमेशा याद रखने की कोशिश करें, जब भावनाओं पर आपका नियंत्रण नहीं रहता। जिन स्थितियों में आपको ज्यादा गुस्सा आता है या जब आप अति उत्साहित होकर बहुत ऊंचे स्वर में बोलने लगते है, तब सचेत तरीके से भावनाओं पर काबू रखने की कोशिश करें। शुरुआत में आप के लिए ऐसा करना मुश्किल होगा, लेकिन धीरे-धीरे यह आपकी आदत बन जाएगी।

कैसे करें सेल्फ असेसमेंट?

सेल्फ असेसमेंट का मुख्य लक्ष्य अपने काम, अपने लक्ष्य के साथ उपलब्धियों के बारे में अधिकारियों को बताना होता है। हालांकि यह भी सच है कि आपके बॉस के संज्ञान में आपसे संबंधित सारे तथ्य और जानकारियां रहती है, लेकिन साथ ही साथ वह यह देखना चाहता है कि कर्मचारी खुद के प्रति और अपने काम के प्रति कैसा नजरिया रखता है। वह अपना मूल्यांकन सही-सही करता है या नहीं। इस दौरान वह अपनी खूबियों के साथ कमियों पर भी नजर डालता है या नहीं। इसलिए सेल्फ-असेसमेंट के समय बेहद सजग रहने की जरूरत होती है। अपने बारे में वही बताएं, जिसे आप सिद्ध कर सकें। बड़े-बड़े बोल से कुछ हासिल होने वाला नहीं, बल्कि उल्टे छवि खराब ही होती है। सेल्फ-असेसमेंट में आप यह जरूर बताएं कि आपकी यह उपलब्धियां सिर्फ निजी नहीं है, बल्कि संस्थान के लिए भी हितकर साबित हुई हैं। इसका उसके बिजनेस पर सकारात्मक असर पड़ा है। यहां इस बात का भी ध्यान रखें कि निजी उपलब्धियों का बखान करने का कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन इसका यह भी अर्थ नहीं कि अगर संस्थान से इतर आपने कोई ऐसी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जिससे समाज में आपका कद ऊंचा हुआ है तो उसका जिक्र जरूर करें, क्योंकि आपके साथ आपके संस्थान का नाम जुड़ा है। निश्चित ही आपकी ऐसी उपलब्धियों से संस्थान की भी प्रतिष्ठा बढ़ती है, क्योंकि समाज में ऐसी छवि जाती है कि संस्थान में कर्मियों के व्यक्तित्व का विकास होता है।

एवैल्युएशन फॉर्म: अधिकतर संस्थानों में सेल्फ-असेसमेंट के दौरान एक एवैल्युएशन फॉर्म भरना होता है। इसे भरते समय काफी सजग रहने की जरूरत है। यह फॉर्म संस्थान का एचआर डिपार्टमेंट तैयार करता है और इसमें कंपनी की सोच भी लक्षित होती है। इस वजह से यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यह एवैल्युएशन फॉर्म आपके करियर विकास में महती भूमिका निभा सकता है। यदि आप इसे पॉजिटिव एप्रोच के साथ भरें तो यह आपके करियर को नई दिशा भी दे सकता है। इसलिए फॉर्म भरने से पहले यह तय कर लें कि अपनी किस कार्यक्षमता, उपलब्धि और योजना को फोकस करना है। इससे यह भी पता चलता है कि संस्थान के हित में आपने क्या-क्या किया है और आपके आगामी लक्ष्य क्या-क्या हैं। इसलिए अपनी महत्वपूर्ण आगामी कार्ययोजनाओं की जानकारी देते समय एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वह योजना धरातल पर उतारने योग्य हो, साथ में यह भी कि अगर इसकी जिम्मेदारी आपके ही पास आ जाती है तो उसे आप सफलतापूर्वक अंजाम दे सकें।

कैसे भरें इवैल्युएशन फॉर्म: सबसे पहले खुद का सटीक आत्ममूल्यांकन करें। उसके बाद उसी अनुरूप पूरी ईमानदारी से फॉर्म भरें। अपने काम और अपनी योजनाओं के बारे में लिखें। सबसे पहले पिछले साल की अपनी उपलब्धियों को सूचीबद्ध करें। इसके बाद आगामी साल के लिए आपने जो लक्ष्य तय किया है, उसे लिखें। फिर इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपके पास क्या-क्या योजनाएं हैं, उसे भी लिखें। किसी प्रशिक्षण, परियोजना या संस्थान की किसी समिति आदि से जुड़े रहे हैं तो उसके बारे में भी जरूर लिखें। साथ में यह भी बताएं कि वहां रहते हुए आपने क्या महत्वपूर्ण कार्य किए।

मजबूत पक्ष: इवैल्युएशन फॉर्म में अपने मजबूत पक्ष को हाईलाइट करें, साथ में अपने वीक जोन की भी चर्चा करें और यह भी बताएं कि उन क्षेत्रों में विकास करने के लिए आपके पास क्या-क्या योजनाएं हैं। अगर प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस करते हैं तो उसका भी जिक्र करें। इससे आपकी ईमानदार सोच और संस्थान के प्रति आपकी प्रतिबद्धता का पता चलेगा।

तथ्य सही हों: यह भी बेहद जरूरी है कि अपनी उपलब्धियों को सही ढंग से पेश करें। पिछले साल का अप्रेजल पेश करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, बशर्ते आप उससे यह साबित कर पाएं कि पिछले एक साल के दौरान आपका कितना विकास हुआ है और अपने काम को लेकर आप पहले से कितना बेहतर हुए हैं। साथ ही यह भी बताएं कि आपके काम से संस्थान को क्या और कितना फायदा पहुंचा है।

अपनी अपेक्षाएं: इस बात को भी स्पष्ट करें कि आप अपनी मेहनत और लगन से संस्थान की अपेक्षाओं पर अब तक किस तरह खरे उतरे हैं और आगे किस तरह उतरेंगे और इसके बदले में संस्थान से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं।

कैसे बनें फोरेंसिक एक्सपर्ट?

कानून और अपराध के बीच आंख-मिचौनी का खेल हमेशा से चलता रहा है। अपराध और कानून की दौड़ में कभी अपराध आगे, तो कभी कानून पीछे होता है। पर कानून कहीं न कहीं अपराध को पछाड़ ही देता है। नई-नई तकनीकें जिनमें फोरेंसिक साइंस भी एक है, कानून को कारगर बनाने में मदद करती है। आज कल आपराधिक घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, वह कोई न कोई सुराग छोड़ ही जाता है। इन्हीं बारीक साक्ष्यों के सहारे फोरेंसिक एक्सपर्ट विज्ञान के सिद्धांतों और नई तकनीकों का उपयोग करते हुए अपराधियों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। इस के लिए एक्सपर्ट ब्लड, बॉडी फ्ल्यूड, हेयर, फिंगर प्रिंट, फुट प्रिंट और टिश्यू आदि की मदद लेते हैं। कुछ प्रमुख विश्वविद्यालयों में भी फोरेंसिक साइंस से संबंधित कोर्स शुरू किए हैं, जो कि कुछ वर्ष पहले तक नहीं थे। इससे यही साबित होता है कि यह कोर्स अब लोकप्रिय होता जा रहा है।

कैसे मिलेगी एंट्री

फोरेंसिक साइंस में एंट्री के लिए साइंस बैकग्राउंड में दस जमा दो पास होना अनिवार्य है। जमा दो साइंस मे करने के बाद ही आगे के रास्ते खुलते है। यदि साइंस संकाय से दस जमा दो की हुई है, तो फोरेंसिक साइंस में ग्रेजुएशन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद फोरेंसिक साइंस और क्रिमिनोलॉजी में एक वर्षीय डिप्लोमा भी कर सकते हैं। फोरेंसिक साइंस में मास्टर डिग्री कोर्स करने के लिए स्नातक मे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, बायोकैमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बी फार्मा,बीडीएस और एप्लाइड साइंस मे किसी एक में 60 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य हैं। इसके अलावा फोरेंसिक स्पेशलिस्ट (जो मरने के बाद पोस्टमार्टम करते हैं) बनने के लिए एमबीबीएस की डिग्री जरूरी है। फोरेंसिक साइंस में एमडी भी कर सकते है। फोरेंसिक साइंस में स्पेशल कोर्स करके आप इस क्षेत्र में ऊंचा मुकाम हासिल कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता बढ़ते ही आपके पद और पगार में बढ़ोतरी होती जाएगी। गवर्नमेंट संस्थान मे नौकरी मिलने पर इस क्षेत्र में आरंभिक दौर में 20 हजार रुपए प्रतिमाह तक वेतन मिलता है। इस के अलावा प्राइवेट सैक्टर में भी इस जॉब में अच्छा सैलरी पैकेज मिलता है।

बढ़ती लोकप्रियता

फोरेंसिक साइंस एक अप्लाइड साइंस है। अपराधियों का पता लगाने के लिए इस में वैज्ञानिक सिद्धांतो व तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इस कार्य मे सहायक होते है अपराध स्थल से मिले साक्ष्य। आधुनिकता के साथ अपराध के तरीके बढ़े है, तो छानबीन के तरीके भी ईजाद हुए हैं। युवाओं का इस फील्ड के प्रति रुझान बढ़ा है।

व्यक्तिगत गुण

इस प्रोफेशन मे आने के लिए युवाओं को लीक से हटकर योग्यताएं रखनी होती हैं। युवा ऊर्जा से भरपूर होना चाहिए। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल और विश्लेषणात्मक क्षमता होना जरूरी है। इस फील्ड मे जाने का इच्छुक नार्मल लाइफ से हट कर सोचने वाला चाहिए। अच्छी तार्किक सोच रखने और हर पहलू पर बारीकी से विचार करने वाले और अलर्ट माइंड वाले इस करियर मे आसानी से एडजस्ट हो सकते हैं।

कहां मिलेगी नौकरी

फोरेंसिक एक्सपर्ट के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब की अच्छी संभावनाएं हैं। यदि गवर्नमेंट जॉब की बात करें, तो फोरेंसिक साइंटिस्ट के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी), सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन(सीबीआई), स्टेट पुलिस फोर्स की क्राइम सैल में, केंद्र व राज्य की फोरेंसिक लैब और प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी में जॉब के अच्छे अवसर हैं। प्रोफेशन चुनौतियों भरा है। इसलिए इस करियर में आना है, तो चुनौतियों से निपटना आना चाहिए। किसी केस को निपटाने के लिए कभी-कभी असफलता भी हाथ लगती है, तो ऐसे में धैर्य नहीं खोना चाहिए और उस केस को चुनौती के तौर पर लेना चाहिए। जांच-पड़ताल का क्षेत्र है, तो जाहिर सी बात है कि दोस्त कम होंगे और दुश्मन ज्यादा बन जाएंगे, तो इस बात से भी भयभीत होने की चुनौती भी इस करियर में है। हर स्थिति से निपटने की चुनौती स्वीकार करने वाला ही इसमें सफल होता है।

मुद्रक एवं प्रकाशक राकेश शर्मा द्वारा अजय त्यागी के लिए ईको प्रिंटिंग प्रेस, पोस्ट एवं पीएस : गड़चुक, कटाबाड़ी मस्जिद के पास, कामरूप (मेट्रो), गुवाहाटी-35 से मुद्रित एवं **गुड लक पब्लिकेशंस, हाउस नं. 30, डी. नेउग पथ, डोना प्लैनेट के नजदीक, एबीसी, जीएस रोड गुवाहाटी-5 से प्रकाशित।**
संपादक : राकेश शर्मा, मोबाइल : 94350-14771, 97070-14771 • **कार्यकारी संपादक : डॉ. आसमां बेगम • फोन :** 0361-2960054 (**संपादकीय**) e-mail : viksitbharatsamacharghy@gmail.com, (**सभी विवाद सिर्फ गुवाहाटी न्याय क्षेत्र के अधीन**)